

12.24 hrs.

**SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (TAMIL NADU), 1975-76**

**THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI-MATI SUSHILA ROHATGI):** I beg to present a statement showing Supplementary Demands for Grants in respect of the State of Tamil Nadu for the year 1975-76.

12.03 hrs.

**GENERAL BUDGET, 1976-77—GENERAL DISCUSSION—Contd.**

**MR. SPEAKER:** Before I call Shri Mulki Raj Saini, I would like to inform the House that there are a large number of Members who want to speak; so, I would request hon Members to confine themselves to seven or eight minutes.

**THE MINISTER OF FINANCE (SHRI C. SUBRAMANIAM):** May I know whether the speeches of the Members will finish today? I would request, even if they have to sit late, they may finish their speeches today so that I may reply tomorrow at 12 O'Clock

**MR. SPEAKER:** Is the House willing to sit for half-an-hour more?

**THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH):** This may please be decided at the end of the day after seeing how many speakers are there at that time. I will consult the leaders of the Opposition. The Minister will speak tomorrow.

**श्री मुल्की राज सैनी (देहरादून):** अध्यक्ष जी, बजट में राजस्व प्रायः 81 अरब 79 करोड़ की है जिस में व्यय 76 अरब 90 करोड़ का है। इस तरह 4 अरब 89 करोड़ रु० की बचत हो जाती है। परन्तु पूँजीगत व्यय 52 अरब 80 करोड़ है जो कि 44

अरब 24 करोड़ में 8 अरब 57 करोड़ अधिक हो जाता है। इस तरह से बजट का घाटा 3 अरब 68 करोड़ का हो जाता है। नये कर 80 करोड़ के लगाने गये हैं उस में से 48 करोड़ केन्द्र का हिस्सा है। इस तरह से घाटा घट कर 3 अरब 20 करोड़ रह जाता है। अर्थ-शास्त्रियों की शका है कि यह घाटा काफी बढ जायगा। इसलिए वित्त मंत्री जी में निवेदन है कि उन्हें सनक रहना पड़ेगा। यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब कि मूल्य आश्चर्यजनक ढंग में स्थिर हो गये है। कृषि की उपज ऊँचाई पर पहुँची है। बिजली, परिवहन, इस्पान, कोयला और कच्चे माल की कमी नहीं रही है। देश के पास विदेशी मुद्रा है और गवर्नमेंट के माध्यम उन्माहवर्धक है।

1976-77 के बजट में योजना व्यय 78 अरब 52 करोड़ रु० है जो कि सन् 1975-76 से 31 प्रतिशत अधिक है। विकास व्यय में अधिकतम राशि रखी गई है जिस में कृषि, मिचट, विद्युत्, पेट्रोलियम, उर्वरक, इस्पात, परिवहन संचार, पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को उत्थान मिलेगा। 20 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होने लगेगी और 24 हजार हैक्टेयर बीहड़ भूमि कृषि योग्य बनायी जायेगी। 2500 मेगावाट अधिक बिजली पैदा होगी। तेल का उत्पादन 82 लाख टन से बढ़ कर 90 लाख टन हो जायगा। कोयला 900 लाख टन से बढ़ कर 1,080 लाख टन हो जायगा और उर्वरकों में 50 प्रतिशत वृद्धि होगी। इस तरह से बजट बड़ा आशाप्रद है।

बजट में उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। कपड़े धोने का साबुन, नहाने का सस्ता साबुन, डिटरजेंट, मटेनलेस स्टील ब्लेड, ट्रांजिस्टर, टायरों में ड्राई बेटर सील टेबिल व पंडस्टल पखे और स्वस्ती सिगरेटों

[श्री मुल्की राज सैनी]  
पर टैक्स नहीं लगाये गये हैं। जिन चीजों पर टैक्स बढ़े हैं उन का बोझ गरीबों पर नहीं जाता है। वे हैं स्टेनलेसस्टील, स्टील की चादरें, कारबन, इस्पात, मिश्रित धातु इस्पात, तांबा, माफ़्लेटेकम आदि और एल्कोहाल मादक दवायें, मादक तत्वों में युक्त औषधियों परसाधन वस्त्र। हम के साथ ही कुछ चीजों पर टैक्स कम किये गये हैं, वे हैं—टेलीविजन, रेफ़रीजरेटर, एयरकंडीशनर, वाटरकूलर, कुछ पैंसेंजर कारे, टायर ट्यूब और बैटरी। यह चीजें मध्यम श्रेणी या निम्न श्रेणी तक भी पहुंच रही हैं। इन को गत वर्ष विलासिता का सामान मान कर टैक्सों की सूची में लाया गया था। लेकिन अब की वफ़ा यह टैक्स कम किये गये हैं। यह स्वागत योग्य है। लेकिन साथ ही देश के आज के प्रखबारों में छपा है कि जो उपभोक्ताओं की मामूली है, उन पर उपभोक्ताओं को राहत नहीं पहुंच रही है। वह आज भी उमी आध पर बिक रही हैं। और उद्योग वालों को माननीय पाई ने साफ साफ कहा है कि यह जो राहत दी गई है यह उद्योगों के लिए नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए है। तो सरकार को इस का नोटिस लेना चाहिए कि जो उपभोक्ताओं के लिए राहत दी गई थी वह उन को नहीं मिल रही है। उद्योगपति या उद्योग चलाने वाले उन को अपने ही उद्योग की क्षमता बढ़ाने में लगा रहे हैं। इस बात को सरकार को देखना चाहिए और ऐसे ऐक्शन लेने चाहियें जिस से कि उपभोक्ताओं को जो राहत देने का मंशा था वह पूरा हो सके।  
इस के साथ ही उद्देश्य यह बताया गया है कि ग्रामों का विकास करने की योजना है। लेकिन छनराशि सिर्फ 15 करोड़ रखी गई है जो कि उत्साहवर्धक नहीं है। और इतने बड़े काम में जिसे कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, यह इस तरह की बात हो जाती है।

इसी प्रकार से इन्कम टैक्स में रियायत दी गई है। इनटैक्स, कारपोरेट टैक्स तथा अन्य भागों में रियायत दी गई है। ग़रीब जमीन, इन्वारतो पर अतिरिक्त कर लगाने वाला है। बैंक, माटेककार, अभिनेता, कलाकारों और संघीतज्ञों को राहत दी गई है। राहत देने का आशय यह है कि बचत होगी, पूंजी निवेश होगा, पूंजी बचेगी और उपज बढ़ेगी। उस- पूंजी के नये उद्योग और नई इमारतें बनेंगी। लेकिन अभी तक का जो एक इतिहास और तजुर्बा रहा है हमारे देश के पूंजीपतियों का वह यह कि वह टैक्स इन्वेज्शन भी करते हैं, तत्कारी भी करते हैं, एडवट्रेशन, ब्लैंक चार्ज और मुनाफ़ाखोरी भी करते हैं। लेकिन आपानकालीन स्थिति के डर से और साथ साथ जो छापे मारे गये हैं, पकड़-धकड़ की गई और उम की बजह में व्यक्तिगत रूप से डिम्कलोज़मेंट हुए हैं। उम से काफी प्राय हुई है और बहुत सी आर्थिक बुराइयाँ दूर हुई हैं। इनका श्रेय सरकार को है और हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी को है और हमारे वित्त मंत्री और हमारे मंत्री मंडल को भी है जिन्होंने इतनी सक्षमता के साथ और सख्ती के साथ एकसन लिया और उम से एक भय कायम हो गया, एक टैरर कायम हो गया। इस का भय उन के साथ साथ प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी जाता है। यह बात भी देखने के काबिल है कि इसी इमर्जेंसी के टाइम में हमारी इती ब्योरोक्रेसी में ने, जिस की बड़ी आलोचना की जाती थी, इन्ही अधिकारियों और कर्मचारियों में से एक बड़ी सख्या में सपनिण्ट, कर्मेट और निष्ठावान अधिकारी और कर्मचारी निकले हैं जिन्होंने छापे मार मार कर 50, 50 लाख का भाव पकड़ा है, 20, 20 और 30, 30 लाख रुपये का भाव पकड़ा है और उन पर इस तरह का कोई आरोप नहीं

झाता है कि उन्होंने उस में कुछ माल गवन किया है जैसा कि पुलिस के बारे में कहा जाता है कि जितना माल वह पकड़ती है उस में कुछ जेबर धीर नकदी ले लिया करती है। इस का श्रेय उन को जाता है। इसलिए भैया यह सुझाव है कि उन की उन्नति, उन को इनाम और उन को प्रोत्साहन देने की योजना चलती रहनी चाहिए और साथ ही साथ यह जो पूजीपति वगैरह अपनी प्रादत से बाज नहीं आता है, उस के खिलाफ भी एकशन होने रहना चाहिए।

इन के साथ ही साथ मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आपान-स्थिति में कर्मचारियों के अन्दर जो यह काम करने की भावना आई है, जिले के नैबिल के नीचे के जो थाने हैं, तहसीले हैं, जनता के सम्पर्क में आने वाले कार्यालय है वहा पर इमर्जेंसी का कोई बटन ज्यादा प्रभाव नहीं पडा है और वहा का हने कोई अच्छा अनुभव नहीं हुआ है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि कर्मचारियों और अधिकाारियों की छानबीन और छटनी की व्यवस्था चलनी रहनी चाहिए और उन में से जो गलत काम करने वाले लोग हैं उन को निकाला जाना चाहिए।

अध्यक्ष जी, बजट में कृषि की उपज बढ़ाने के लिए काफी धन रखा गया है। उर्वरकों में मूल्यों की कमी से किसानों को 105 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी, जिस में फास्फोट खाद में 60 करोड़ रुपया यूरिया में 40 करोड़ रुपया, औद्योगिक फर्टिलाइजर्स (खाद) में 5 करोड़ रुपया, और इसी के साथ ही साथ सहकारी समितियों को 8 करोड़ रुपये होंगी। लेकिन इस के साथ ही साथ यह भी निवेदन है कि थल क्षेत्रों में किसानों पर सिंचाई, बिजली और खाना आदि के कर बढ़े हैं और तेल,

कोयला, इन्प्यात आदि की कीमतें बढ़ी हैं। इस कारण किसान के कृषि की उपज के मूल्य लागत के अनुसार उन्साहवर्धक नहीं रहे हैं।

इन में साथ ही साथ एक बात की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मागे देश के अन्दर यह कहा जाता है कि अगर गहू के दाम बढ़ गये तो सब चीजों के दाम बढ़े जाते हैं लेकिन कृषि के दामों के बढ़ने की जो व्यवस्था है उस को भी जरा ध्यान में रखना चाहिए। जब कृषि की उपज के दाम बढ़ते हैं तो कन्ज्यूमर गुड्स के दाम पहले बढ़ते हैं और उस के साल दो साल बाद ही कृषि पदार्थों के दाम बढ़ते हैं और उस के बाद जब कम होने का मवाल आता है तो शुरुआत कृषि-जिम्नो के मूल्यों में ही होती है। इस तरह से आप देखें कि किसान पहले दो तीन सालों में मन्ना बेचता है और फिर उस के बाद थोडा महंगा बेचता है और जब दाम कम करने की बात आती है तो सबसे पहले उसी के दाम कम होने हैं जब कि कन्ज्यूमर्स गुड्स जो है, सेनूफैक्चर्ड गुड्स जो हैं उन के दाम पहले से ही बढ़ जाते हैं और अगर घटते हैं तो बाद में जा कर थोड़े समय के लिए घटते हैं। किसान की चीजों के दाम योजनाबद्ध तरीके से घटाए और बढ़ाए जाते हैं और इस तरह से किसान लूट जाया करता है। पैदावार अगर बढ़ जाती है तो उस की चीजों के दाम कम हो जाया करते हैं।

साथ ही साथ मुझे यह निवेदन करना है कि बेरोजगारी और अशिक्षा देश के बड़े रोग हैं और खास तौर से गावों में, जहां कि 80 प्रतिशत हिन्दुस्तान की आबादी है, अशिक्षा है और रोजगार नहीं है। कुछ अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ यह मानते हैं कि अगर देश में बेरोजगारी को मिटाना है तो अगर विकास की योजनाएँ हाथ में लेनी होंगी। ग्राम विकास की योजना में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है—

**[श्री मुल्की राज सैनी]**

श्रीर मैं उसे साफ पेश कर देना चाहता हूँ। कृषि की उपज बढ़ाने के लिए बिजली और पानी के साथ साथ घाज गाव की सब से बड़ी माँग सड़को की है। सड़के अग़र बन जाती है तो शहर को केन्द्र मान कर, उस के चारो तरफ 15, 20 मील के दायरे में जो गाव हैं, वहाँ के लोग शहरों में काम करने के लिए अग़र जाते है तो वे सड़कों के बन जाने के बाद काम कर के अपने गांवों को वापस आ सकते हैं और शहरों में अपना घर बनाने की बजाए वे अपने घरों पर गत को पहुँचेंगे। इस तरह से जब यात्रा के साधनों में बढ़ोतरी होती, रिक्शा, तांगे, टैक्सी और बसें चलेगी, तो उन से नये रोज़गार पैदा होंगे। शहरों में काम करने वाला व्यक्ति रोगन-दिमाग का होगा। इसलिए वह अपने ही माधनों में अपने घर को बनायेगा, गलियों और नालियों का सुधार करेगा और अपने बच्चों की शिक्षा के लिये गाव में ही स्कूलों को उन्नति देगा। छोटा सा बाजार भी बनेगा और साथ ही मनोरंजन के माधन, सिनेमा हॉल गाव में पहुँचेंगे। इस तरह में शहरों के चारों ओर ग्राम विकास की बात आ जायगी।

मैं एक बात और कह कर समाप्त कर दगा। बीस-सूत्री कार्यक्रम को बहल महत्ता दी गई है लेकिन मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि दुर्बल वर्ग को और खास तौर से हरिजनो और पिछडे वर्ग के लोगो को बीस-सूत्री कार्यक्रम लागू करने में कितनी दिक्कत होती है, किस तरह से उन की पिटाई होनी है, किस तरह से उन्हें कत्ल किया जाता है और किस तरह से बच्चियो के साथ बलात्कार किया जाता है इस सम्बन्ध में मैं अपने जिले सहारनपुर के बारे में यहा ध्यान कर देना चाहता हूँ। रूल्हा सिंह ग्राम सभा बहरमऊ, नकुड तहसीन के प्रधान है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तगत उस ने आवास और जुताई की जमीन कृषि भूमिहीनो को एलाट कर दी थी। इस पर ऊंची जाति के किसानो ने, सर्वण वर्गों के लोगो ने उस पर कब्ज़ा नही होने

दिया और मुकदमा लडा लेकिन मुकदमें में वे लोग हार गये। इसी वलहा सिंह का एक लडका रेलवे के अन्दर सहारनपुर में टिकट कलक्टर है। एक दिन जब वह अपने घर जा रहा था और बस से जैसे ही वह उतरा तो 8, 10 आदमियो ने बुरी तरह से लाटियों, और बल्लम से उस पर हमला कर दिया और वह जखमी हो गया। उस को अस्पताल में भर्ती किया गया लेकिन पोलीटिकल मैन्डोरिंग में, एम० एल० एज० और एक मंत्री जी के कहने से उस को 8 दिन में ही अस्पताल से निकाल दिया जाता है और वहाँ से उस का तबादला कर दिया जाता है जिस से वह मुकदमे की पैरवी भी न कर सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि बीस-सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में बहुत सी दिक्कत आ रही है। एक जगह पर एक वामोकी लर्रे को जमीन एलाट हुई थी और जब वह अपने गाव को जा रहा था तो उस को जान में मार दिया गया। 15 साल की बच्चियो के साथ बलात्कार किया जाता है और हमारे जिले की मशीनरी मलियो और एम० एल० एज० के प्रभाव में आ कर कोई एक्शन नहीं लेनी है। न सी० ब्रा० कुछ करना चाहता है और न एम० पी० ही कुछ करना चाहता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि नकुड तहसीन के विधान सभाई क्षेत्र, जिस का मैंने पहले जिन किया है, के बारे में उच्चस्तरीय जाच कराई जाए और जो भी उस में दोषी हों उन को सजा दी जाए और अग़र राज्य मंत्री भी दंपी हो, तो उन को हटाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** टम के बारे में आप गृह मंत्री जी को लिख सकते हैं।

**श्री मुल्की राज सैनी** - इतना कह कर मैं समाप्त करता हूँ और बजट का स्वागत करता हूँ।

**MR. SPEAKER:** Shri Virendra Agarwal. He has got 28 Minutes; he may try to confine his remarks within that time.

**SHRI VIRENDRA AGARWAL** (Moradabad): Hon.-Speaker, Sir, Mr. Subramaniam's budget has been aptly described as much ado about nothing. This pre-election budget has produced the least excitement. The senior officials of the Union Ministry of Finance tried hard to create some controversy but they have also failed to do so. What is its psychological analysis? We have reached a saturation point in our national history when people by and large do not expect much from this Government because of its low credibility. The political atmosphere is so suffocating that it is full of frustration, disappointment and annoyance. People are greatly scared to express their opinion even on economic issues. Why? It is largely because of naked and brutal police raj imposed through emergency. People do not feel happy because they were expecting much higher fiscal relief. They are not unhappy either because they have not felt hard-hit. The only question which has been asked today is whether the Union Budget will help the prices shoot up or not and if so from when. The man on the street is least bothered whether it would create growth climate or not. Pre-budget hopes and expectations have been largely belied.

We do have a comfortable financial situation. For the first time in two decades, prices are remarkably stable, farm output has reached a new peak, shortage of power, transport, steel, coal and raw materials have disappeared, the country's foreign exchange reserves are comfortable and the Government's revenues are buoyant. The Finance Minister had an excellent opportunity to go still further to provide fiscal relief and concessions for reviving the economy. He has made genuine efforts but he has not gone far enough to cut much ice on the economic front. It is unfortunate that the Prime Minister's thinking has not been carried to its logical conclusions. Vast sweeping powers granted to the bureaucracy constitute a major hurdle. There are serious reservations on the

Union Budget in respect of the following six points.

First, the price inflation has been effectively curbed. But price stability may be the major casualty in 1976-77. Why is it so? The tax liability placed on the nation by the Union Government amounts to Rs. 307 crores—including Rs. 80.0 crores on account of hike in Railway freight plus Rs. 140.0 crores on account of postal rates. Indirect taxation are always passed on to the consumer. The Finance Ministry has evolved a new strategy of differentiating between the budget deficit and deficit financing. The budget gap which was Rs. 247.0 crores in 1974-75 shot up to Rs. 490.0 crores in 1975-76 and in 1976-77 this figure has been kept at Rs. 320.0 crores. Deficit financing—another item which was Rs. 971.0 crores in 1974-75, and it was Rs. 438.0 crores in 1975-76. The level of deficit financing which we have had in 1974-75 and 1975-76—we can very well believe how much deficit financing we would have in 1976-77.

Thirdly, the Government has shifted its liability of food procurement and fertiliser distribution from its own funds to the banking account. It has made a tremendous impact on the nation's financial position but still money supply has shot up from Rs. 11,322.0 crores in 1974-75 to Rs. 12,40.0 crores in 1975-76—an increase of 11.5 per cent. The real question I would like to ask the Finance Minister is What is likely to be the extent of money supply in 1975-76 after having taken all the three aspects into account—one is budgetary deficit, second is deficit financing and the third is the plan outlay as envisaged in the budget? At the moment after having examined the total economic situation I for one was expecting tax free surplus budget. This budget is wholly inflationary in content as well as in meaning.

Secondly, the major achievement of the Union Budget today is that the plan outlay has been raised from Rs. 6100

[Shri Virendra Agarwal]

crores in 1975-76 to Rs. 7852.0 crores in 1976-77, an increase of 31.6 per cent. Or you can say that it is 1752.0 crores. It is really unprecedented in the history of the planning economy. This has been done and rightly done to reflate the economy. But my question is how it is going to be financed and how it would ultimately be utilised. These are the two questions which will ultimately determine the future of the economy in 1976-77. It is not financed by public savings. Let us be very clear about that, because the revenue receipts have shot up from Rs. 8022 crores to Rs. 8178 crores. It is financed entirely by foreign aid amounting to Rs. 1341 crores, market borrowing of Rs. 535 crores and the budget deficit of Rs. 320 crores. You know the uncertainty in respect of foreign aid. So, whether we would be able to raise the resources to step up the plan outlay by 31.6 per cent remains uncertain. It is not merely a question of allocation of resources but immediate production. Ultimately it boils down to the question of utilisation of resources. What is our history in this regard? We know that this amount of Rs. 7852 crores will be spent on priority sectors, i.e., development of power, fertilisers, etc., which are, no doubt, basic to the development of agriculture, but these are all long gestation projects. You will not get the results from them in 1976-77. The resources get into circulation but they will take three or four years, for actual production. Actually, the real question is what you are going to achieve in terms of production in 1976-77. My submission is, public resources have been largely squandered on unproductive expenditure. That is the history of the last 27 years: though the experiments conducted have been very bold, they have produced a very inflationary situation for the economy.

The maximum marginal rate of income-tax has been reduced from 77 to 66 per cent. It is believed it will result in no loss to the revenue. Similarly, the wealth tax has been reduced but we will still realise Rs. 52 crores from this and there is no loss to the

revenue. The Finance Minister has rightly raised the question: What is reasonable tax limit? While Mr. Chavan moved for reducing the maximum margin rate from 97.75 to 77 per cent and the entire Congress party voted for it, I thought it was irrational. Today when Mr. Subramaniam has moved to reduce it to 66 per cent, I say it is equally irrational. Prof. Kaldor pleaded that the maximum marginal rate in no case should exceed 45 per cent. That is the only limit which can ensure a system by which you can regenerate wealth and build an egalitarian society, not a limit of 97.75 or 77 or even 66 per cent. There is a national consensus that if they really want to evolve a strategy where there would be no black money and an honest man would come forward to pay his taxes, the maximum rate should not be more than 50 per cent. In respect of corporate taxes which at the moment range from 66 to 77 per cent, the Finance Minister has refused to touch them. I would plead that the Corporate tax also should be reduced to 55 per cent. The whole thing ultimately boils down to this that the Finance Minister has tried to provide some relief with one hand which he has taken away with the other. A higher rate of CDS has been imposed on the affluent sections of the society. The CDS is being continued for another year and it will mop up Rs. 80 crores from the affluent section. I would urge that the whole question of CDS should be reconsidered. The earlier it goes the better. I would like to ask the Finance Minister: Is 100 per cent a realistic or equitable limit on the combined incident of taxation of an individual assessee? I do have names who are paying 300 per cent taxes on their total incomes. I still hold the view that hundred per cent is neither realistic nor just. I would urge upon you to place a ceiling of 80 per cent on taxation on the combined incidence of taxation on one individual assessee.

In this House and outside, people are trying to brand this Budget as rich men's budget, socialist budget or a

poor man's budget. To me it is neither a rich man's budget nor a socialist budget, it is a budget meant for growth. If this is for growth, then it will serve both the masses and the classes. Unfortunately, this growth is being acquired at the cost of price stability. That means that if there is an inflationary price the whole nation will suffer and more so the poor.

I would like to say a word about stagnation. At present, stagnation is eating away the vitals of the economy in the country. It is such a serious menace that if it is not checked and checked immediately, I am afraid, all the calculations and strategies being made by the Union Government will go flop. Meagre tax concessions have been largely offset by steep increase in import duties, I will say that they are all half-hearted measures which will largely prove to be self-defeated measures. They will do more harm than good to the economy. At the moment, what do we see is that the excise duty alone increased from Rs. 52 crores in 1950-51 to Rs. 4100 crores in 1976-77 which is record of our fiscal system. I feel that the Finance Minister should kindly consider to have a reduction in excise duty at least by 10 per cent. That means that Rs. 400 crores need be granted as fiscal relief so that the taxation which is the result of cost-push inflation rather than demand-pull inflation, is checked and checked effectively. The question is: Are we going to allow these industries to die which are generating resources for social justice? I will not have any hope for economic recovery if industrial revival is not made a reality. I know, certain researches have been conducted that if the industrial growth rate is raised to 9 per cent, the Government can easily mop up as much as Rs. 700 crores. I do not know why all possible efforts need not be made to step up industrial growth rate in this country.

This Budget remains silent so far as lowest income group is concerned. No relief has been provided to the lowest

income group. I was expecting the Finance Minister to raise the tax exemption limit to Rs. 10,000—which is absolutely the minimum. I would immediately urge him to raise the tax exemption limit to Rs. 10,000 immediately and further to Rs. 12,000 in case of those having two or less than two children. This fiscal programme need be linked with the programme of family planning. At the moment, considering the value of the rupee which is almost one-third, this step seems necessary.

Similarly, the Finance Minister had done nothing to raise the domestic house-hold saving in the country. He is relying greatly on public saving or saving coming from the affluent sections of the community. But the real savings, out of the 12 per cent of the total savings, at least 7 per cent are coming from the small man, the small house-hold man. While we know that small savings are going down from 14 per cent to 12 per cent, therefore, I would also urge him to reconsider that the tax exemption limit on dividends and incomes be raised from Rs. 3,000 to 6,000

You have placed so many duties on so many things and I will refer to just one or two. The Finance Ministry has armed itself with certain powers in the Finance Bill to raise the excise duty—10 paise per litre on petrol and 50 paise per litre on refined diesel. I for one feel that there is a need to reduce the price of petrol if you really want the economy to recover.

The import cost of petrol today is hardly Rs. 600 to Rs. 700 per tonne; but the selling price in India is more than Rs. 4,800 per tonne. It means that the Government is making a profit of Rs. 4,200 per tonne. I really do not see any justification why the Government should not take necessary steps to reduce the petrol price at least by a rupee per litre. Secondly, in regard to the paper industry which is a very small capital-intensive industry, the Finance Minister has found it necessary to impose excise duties worth about Rs. 26 crores out of the total tax

[Shri Virendra Agarwal]

burden of Rs. 80 crores—on this just small industry whereas the paper is hardly saleable in the market. It suffers from recession greatly. There is no additional capacity which is likely to come forward. I think this whole proposal needs to be given a fresh review. Otherwise the paper industry will go completely into liquidation. Now about life-saving drugs. The Finance Minister has not even spared the patients who are suffering from severe ailments; he has placed a duty of Rs. 18.2 crores. I would say that we should at least save human lives, if not anything else. If he wants really to curb inflation on a permanent or long-term basis, large production of mass goods is inevitable. I know he has provided roundabout Rs. 64 crores for this purpose, but we still have to go very far to have a very large production of mass goods, which is the only sure strategy to check inflationary trends in this country. And finally, it is not the mobilization of resources, but the re-generation of new wealth which can take the country forward.

Mr. Speaker, Sir, the Indian economy has been struggling hard against heavy odds for various reasons. The growth in the per capita income was one per cent during the last 20 years, as against the growth target of 3 per cent. There is hardly any increase in the per capita income since 1964-65. It actually meant a reduction in the living standards of the vast majority of the people. A price rise of 80 per cent during 1974-70 and an adverse balance of trade of Rs. 1046 crores has resulted in a sharp erosion in the general purchasing power of the people, a slow-down in the rate of growth and investment and in a general psychology of despair.

The fiscal policy, as pursued during the last 27 years, has produced nothing but a corrupt man and an inefficient economic structure and poverty—growing at an enormous pace. The Reserve Bank's report says that the percentage of those who live below the poverty line has gone up from 40 in

1966 to 66 in 1975-76. Unemployment is growing so fast that 5 million people are added to the labour force every year, whereas the employment potential is hardly being created even for a few thousands. The structure of the Indian economy today has changed very little, since 1966. During the last 10-year period, i.e., the decade of Indira Gandhi's stewardship, the compound rate of growth of farm output, despite the much-heralded Green Revolution, works out barely to 1 per cent a year. The industrial growth rate has shrunk markedly, by 2/3, compared with the preceding decade. The availability of food is lower per head than what it was 10 years ago; and production of cotton textiles, a pivotal consumer item, has fallen absolutely. If the economic situation is allowed to deteriorate at this pace, it is obvious that by the end of the century, when the population of this country would reach 100 crores, every citizen of this country would fall below the poverty line. That is the only achievement of the Congress Party. Will this budget arrest this unhealthy trend? This is the crucial question. My humble submission is that the economic planning needs to be so evolved as to ensure that the living standards which are now prevailing in the western countries, should be made available to every citizen of India by the end of the century. Will this budget ensure this? A growth rate of at least 10 per cent a year can solve this mystery. It is really a difficult task, but not an impossible one. The population growth rate also, in no case, should be more than 14 per cent a year. The living standards of those living below the poverty line must be raised; and that should be the only economic objective. It can be achieved only if the people as a whole are involved in a big way. If this target is to be achieved, the creative genius of the people must be channelized in the productive process, so that a growth rate of this order is achieved every year. If the Government fails to achieve this target, it has no right to remain in office.



Sir, I know the Finance Minister's reply His usual reply is that all this cannot be achieved in one budget. But we have seen 27 budgets, and they have all made very bold experiments Unfortunately, the economic situation has not improved We all pay lip sympathy to the poor, but the poor today is cursing all of us, especially those at the helm of affairs.

Sir, it is neither the emergency, nor the Government's anti-inflationary policy, nor the Prime Minister's 20-point programme which has produced any miracle on the economic front The Prime Minister's programme is neither Gita, nor Magna Carta, but it has emerged to be a charter of inaction These measures have produced neither stability nor growth, at best, they can be described as politically motivated, with the sole objective to retain power

If the economic situation has become favourable it is mainly because of the favourable benign monsoon, which has ensured a bumper crop of 114 million tonnes To me this figure of 114 million does not seem to be correct My assessment is that the food production during 1975-76 will not cross the figure of 111.40 million tonnes—an increase of 7 per cent The industrial growth rate, which has gone up by 4 per cent may ensure an over-all growth rate of 5.5 per cent in 1975-76

The Government's strategy for ensuring rural prosperity by creating 75 million jobs seems to be perfect, but it is equally true that we cannot go very far to bring about any radical change in the complexion of rural life so long as it is not accompanied by a comprehensive rural economic programme It should not only help in raising their purchasing power but should also provide them a better quality of life in the rural areas.

Secondly, what incentives have we provided to the farmer so that we can expect him to produce more? The Government's efforts to accelerate the rate of growth of fertiliser use, the speedy implementation of the land reforms as well as the creation of increased irrigation potential are laudable But they cannot go very far because the farmer does not feel enthused to produce more In spite of Government's guaranteed procurement price of Rs 105 per quintal, agricultural prices have crashed all over the country Very little has been made to provide subsidised inputs. What is needed today is, not only to procure 73 million tonnes of food-grains as against 46 million tonnes as already done but the Government should enter the market of other agricultural products, like gram, barley and also potatoes I for one would plead for a still higher procurement price for agricultural produce The Pant Agricultural Research University had gone into this matter and have discovered that the cost of production for foodgrains is not less than Rs 117 per quintal In view of this, I would advise the Chief Ministers to revise their decision and to raise the procurement price from Rs 105 to at least Rs 110 It should actually be made available so that the prices do not crash in any mandi Revision of minimum wages for agricultural workers is another need of the hour. We see from today's newspapers that in West Bengal the farm workers earn 37 paise a day If all this is not achieved I can assure you that the agricultural production in no case can ever exceed 108 million tonnes in 1976-77, a decline of 2 per cent

The survey acknowledge the problem of stagnation unless the output grows more than twice as fast as in the last ten years, if the economy is to achieve an overall growth rate of 6 per cent This is the correct analysis of the economic situation. But this can never happen if there is continued sluggishness of private investment The Government cannot

[Shri Virendra Agarwal]

afford to forget that private enterprises still amount to four-fifths of the total value added in the industrial sector. Certain factors like production of coal, power, steel and transport, liberal imports of materials and components and improving industrial relations have brightened the prospects, but still the growth rate could not cross 4 per cent in 1976-77.

The Budget has provided striking concessions to the corporate sector, namely, Investment allowance at the rate of 25 per cent of the cost of new plant for an enlarged list of priority industries, the conversion of surcharge of five per cent into compulsory savings and small easing in the incidence of surcharge. Will it help the situation to accelerate the growth rate? My simple reply is no. What are the basic factors responsible for industrial stagnation?

The gap between promoters' capacity to raise resources and the escalating cost of new projects cannot be closed by the financing institutions within their existing policy framework. The Finance Minister has pleaded hard not to reduce the bank rate to contain inflation, but I will plead that the bank rate should be reduced from 9 to 8 per cent while reduced from the present 165 to 13 per cent. Credit squeeze in no sense should amount to production squeeze. Selective availability of credit seems absolutely essential for economic revival.

It is true that the prices at the moment are steady. They may be declining in certain cases. But as soon as such large resources as Rs 1800 crores get into circulation and the growth rate remains stagnant at 2 or 2.5 per cent, the prices will sharply shoot up at least by 10 to 15 per cent by the end of 1976. Price stability does not seem to be a permanent feature of the national economy. This Budget is wholly inflationary in character and has lost its primary objectives.

Growth is a very delicate process. This Budget has made it a rather unpredictable phenomenon. Self-reliance is no longer our objective because the large plan outlay is being financed by foreign aid. Social justice still remains a far cry because the lowest income group has received no relief.

Democratic socialism and decentralised rural economy always prosper in a free atmosphere. They start showing ugly signs and complexions if the economic freedom ceases to be the basis of the political system. Today democracy has been denigrated into Fascism. The authority of Parliament, the press and the judiciary has been greatly undermined. The opposition has been practically liquidated. In such an atmosphere what economy is best suited is the curcial question. Fascists believe in a regimented economy. Several countries tried it, and they had to pay a heavy price. Is it not surprising that our leaders take pride in maligning and abusing the businessmen all over the world, while Indian goods are described as shoddy in foreign market? One who does not take pride in one's own goods cannot be a rationalist. This is the situation which has made the economy suffer a great deal. This Budget unfortunately moves in this very direction. It talks a great deal in terms of an integrated strategy for rural prosperity, but remains silent on providing remunerative prices to the farmer for his agricultural produce. Adequate wages are not yet paid to the agricultural workers. A large investment through inflationary finance cannot deliver the goods. It will certainly perpetuate poverty, unemployment and corruption. The earlier this trend is reversed the better it would be to build a bright future for our motherland.

In the end, I will just read out a couplet which should be of some interest to you.

**SHRIMATI MAYA RAY (Raiganj):**  
By whom?

**SHRI VIRENDRA AGARWAL:** By Meena Kumari, the great heroine and actor.

नमाम विम्बों पे पङ्क्रे बिटा दिए है  
 कि :

इकिलाब को बस गिरफ्तार कर ले  
 हर एक सादा लम्हा भी बस  
 शक की तजरो से झाँकता है,  
 न जाने कौन सा रूप धारे  
 न जाने कौन सा ब्रह्मरूप भटके,  
 न जाने कौन से भ्रम में वह,  
 इकिलाब अपनी राह निकाले ॥

**SHRIMATI MAYA RAY.** I rise to support this Budget and congratulate the hon. Finance Minister for having shown imagination after many years. In fact, I beg to differ with the hon. Member of the Opposition who has just preceded me. I think he missed his vacation as an actor. He would have given marvellous performances, but I think as an economist perhaps he has many shortcomings. I do not claim to be an economist myself but I think I do have some common sense. All I can say is that he comes from the Opposition and is opposing just for the sake of opposing which is not going to solve any economic problems or any economic crisis. But then what can we expect in this country. He belongs to a party which preaches nothing but negativism, and throughout his speech, we find just that and there was nothing positive but only negative statements. I was concentrating on what the hon. Member was saying and I did not find a single constructive suggestion.

(Interruptions)

You see sometimes it is I who cannot understand. I take full responsibility for my lack of understanding.

**MR. SPEAKER:** Do not get excited.

(Interruptions)

**SHRIMATI MAYA RAY:** It was there in the last bit of his speech which sparked off this controversy otherwise my remarks would not have arisen.

He complains of a deficit budget, but he did not take into consideration the global conditions that have been existing for the past two years, creating such havoc in the developing countries and he complains that this is not a surplus budget. How could it have been a surplus budget under the conditions we have seen in the past one year or so with the rise in oil prices and other difficulties that we have faced?

He also made a point about corporate taxation and something to the effect that there was no relief really, because it has gone up from 55 per cent to 75 per cent. May I say that these figures are purely theoretical calculations. In practice, Reserve Bank of India has done intensive research by going through the returns of more than a hundred companies, and it is being found that the effective rate works out to be in the vicinity of 40 per cent, and therefore, there is no case for reduction.

I also differ with him on another point. This Budget shows that the investment allowance given is, in fact, a revival of development rebate with some modifications. Then again he spoke about the Kaldor recommendations and said that the tax evasion could be curbed if these recommendations were accepted and the rate of Wealth Tax was not more than 50 per cent. As I said from the beginning, that I am far from being an economist, but this theory is totally fallacious, because the fact is that attitudes have to change in our country. My dear friend, until we change

[Shrimati Maya Ray]

the national characteristics that we possess, all these theories are not going to work, and in this respect, I must cite Kenya and Hong Kong where the rate is 12.5 per cent. So, I do not agree with his idea of citing Kaldor.

Can I now come back to the points that I myself wish to make? After all, we must bear in mind that a budget is not merely a balance-sheet of credit and debit of expenditure nor is it a straight jacket within which monetary transactions of the country take place. It requires to be a dynamic instrument for quickening the pace of development, at the same time keeping in mind that the development must be speedy as well as equitable.

Therefore, priorities have to be chalked out and priorities have to be given to those sectors of the economy which must have infusion of resources; priorities must be given to those areas which are capable of rapid growth, and last but not the least and this is the most important point, it should be directed towards those sections of society which are the weakest, most vulnerable and deserving of upliftment. It is in this respect that I think, the hon. Finance Minister is to be congratulated.

There is always room for improvement. It is true, more relief could have been given to the weaker sections of society and, in that respect, I am in agreement with the hon. Member opposite. He can never agree with us. But when he says something which can be agreed with, we agree with that. I would say, that this is the difference between his party and my party. To that extent, I would say, perhaps, a little more imagination could have been directed towards the weaker sections of society. But then nothing can be done overnight. It has to be thought out and, we hope, there will be room for further improvement in this regard.

Why are we congratulating the hon. Finance Minister for this Budget? It is one for generating a demand for a large number of items. It is investment-oriented. The prices of a number of consumer goods have already come down affording relief to some sections of the society, in fact, with immediate effect.

The major problem that Indian economy was facing during the last one year or so, was a steep decline in demand in respect of a number of goods. I find that the remedial measures that have been spelt out in the present Budget do meet the situation and this is most encouraging. There has been a reduction in excise duties on a number of commodities. There has been a lowering of personal taxation which means an increase in the purchasing power of a number of people, enabling a revival of demands to ensure an up-swing in the economy.

I must say that when the Government at last sees fit to give some relief to the honest tax-payer—I have been tax-payer in my time and quite a heavy one at that—I think, it is now incumbent on every Indian citizen, as a patriotic Indian also, to pay his taxes regularly and without evasion. This is the national characteristic which I was trying to point out, of not trying to evade. This will not come about overnight I know, but I am a person who still cherishes some idealism. It may be wrong on my part, but this has not yet disappeared. When I truly become a cynic like the hon. Member opposite then, of course, I will come to him for advice....

AN HON. MEMBER: Or join the Jana Sangh.

SHRIMATI MAYA RAY: Never! that is definitely out completely.

The present Budget, as I said, is definitely growth and investment-oriented. Apart from reducing excise duties and laying emphasis on re-generating demand, the Finance Min-

ister has provided resources for modernisation of cotton textiles, jute, sugar, cement and engineering industries through the I.D.B.I. and other financial institution. But here, I would like to say that there is room for further improvement. This could be made, if these funds are made available at a concessional interest rate with repayment between, say, 10 to 15 years and with a moratorium of payment over 5 years.

12.58 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

In West Bengal, we are specially interested in jute and engineering industries.

MR. DEPUTY-SPEAKER Now, I have a very unpleasant duty of reminding the hon. lady Member that she has taken more than the allotted time.

SHRIMATI MAYA RAY: If you tell me to sit down, I will sit down immediately. This is an era of discipline.

MR. DEPUTY-SPEAKER I am just drawing your attention.

SHRIMATI MAYA RAY: How many minutes more?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have exceeded your allotted time.

SHRIMATI MAYA RAY: Sir, I must seek your protection. I have been let down once again by the Minister of Parliamentary Affairs. He promises me every time that I will get sufficient time. He raises my hopes before I enter this Chamber but demolishes them at one stroke and lets me down once I have entered it.

SHRI K. RAGHURAMAIAH: I promised her 10 minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is a women's decade. I need more protection than you do. Please try to conclude.

13.00 hrs.

SHRIMATI MAYA RAY: In West Bengal, we are very interested in the jute and engineering industries. As far as these industries are concerned, modernisation is of the utmost importance, but it is very problematic and prickly. Here it is necessary to sound a note of warning when implementing these policies. The authority for disbursement of these loans should not be confined and restricted to the Head Offices of these financial institutions and totally centralised in one part of this vast country of ours. This point has been made several times. Over and over again I have spoken about this in other contexts, but, of course, I must say that scant regard is paid to the suggestions of insignificant back benchers such as we are. I hope, the Finance Minister will, at least in this important context, pay heed to something of what I am saying.

Rapid growth in various regions is considerably impeded because of this impossible idea of total centralisation. This has been proved over the years in the overt imbalance of development of various regions of the country. Times without number it has been suggested that there should be the maximum possible delegation of functions and authority to the local offices of these institutions in the Northern, Eastern and Southern regions.

Since India is a vast country, Managers, Industrialists and officers have to travel long distances, spending a great deal of money and time to get to one part of India only, to sort out their problems. Therefore, this causes delay, expenditure, over-centralisation, not to say the least how it contributes heavily to Parkinson's Law.

When we are advocating the 20-point programme, under the present bureaucratised and centralised set-up of these financial institutions, can one seriously imagine that the small entrepreneur and the small trader from

[Shrimati Maya Ray.]

the Northern, Eastern and Southern regions can afford to go backwards and forwards to the headquarters of these financial institutions? You cannot get anything from the nationalised banks for the weaker sections of the society, which really reflects the old system that prevailed in the past. The small entrepreneur and the small trader of the Northern, Southern and Eastern regions cannot afford to go to say, Bombay or Maharashtra. I am not objecting to Bombay as such but I am just saying that it is not practical. Such persons coming from the rural sectors are at a serious disadvantage and the effective implementation of the new economic programme will be totally defeated unless the State Governments are allowed to be closely associated with the processing and disbursement of such loan applications by the regional centres.

May I, therefore, now round up—because I don't want to incur the odium of the Deputy Speaker though, in fact, it is the Minister of Parliamentary Affairs who has incurred my odium and I shall deal with him outside.

SHRI K RAGHURAMIAH, Sir,  
I seek your protection!

SHRIMATI MAYA RAY: With these few words, Mr. Deputy Speaker, I sincerely congratulate the Finance Minister for showing considerable imagination in presenting his budget.

SHRI Y. S. MAHAJAN (Buldana): Mr. Deputy Speaker, Sir, in recent years no budget has been received with such a chorus of applause by all sections of the community as the one presented by the Hon. Finance Minister for 1976-77. It reflects the satisfactory economic progress achieved during the current year which is the result of our resolute and dynamic leadership and, secondly, of the favourable monsoon during the year, all over India.

Inflation, which still ravages many developed as well as un-developed countries of the world, has been not only contained, but reversed. This has been a great achievement. The wholesale price index has fallen by 7.5 per cent during the last year and the national income, in real terms, is likely to register an increase of about 5.5 per cent over the year. Food production is likely to achieve the record level of 114 tonnes and the tempo of industrial production will increase by 5.5 per cent. In spite of an unprecedentedly heavy deficit in the balance of payments, we were able to maintain our foreign exchange reserves at a comfortably high level.

The most significant part of the Budget is the steep increase in the investment level in the next year, an increase upto Rs. 7,852 crores, that is, by 31.6 per cent over the last year. This is the highest ever increase in annual investment ever since planning began in this country. It has been distributed in a judicious manner in such high priority sectors as agriculture, irrigation and power. The greatest stress has been laid on the completion of on-going projects, so that the capital will not be locked up in an unproductive manner.

As a result of the investment in schemes of irrigation, it is expected that the irrigation potential will increase by about one million hectares.

It is a matter of great satisfaction that sectors such as power, petroleum, petro-chemicals and fertilisers have been given the urgent attention they deserve in view of their critical importance in the present context of our economic development.

Along with the probable increase in the private sector outlay, the investment outlay in the public sector can be expected to give a very great stimulus to agricultural as well as industrial production.

Another important and good feature of this Budget is that the Finance Minister has proposed a number of measures to promote savings, without which his large investment programme cannot be successful. Resource mobilisation has to be on an adequate scale; otherwise, it might give rise to deficit financing, with the attendant evil of rising prices. To promote savings and to provide relief to the recession-hit industries, the Minister has announced a number of measures. The most important of these is reduction in the marginal rates of income-tax and wealth-tax. This will mean that higher amounts of disposable income will be available in the hands of the people, and it is mostly probable that these amounts will be diverted to savings and investment.

Secondly, the introduction of an investment allowance at the rate of 25 per cent is rather a bold and important innovation; it replaces the present scheme of initial depreciation allowance, and the rate of 25 per cent will be calculated on the basis of the cost of acquisition of new machinery and plants installed after 31 March, 1976.

Fiscal policy will, in this way, provide a great stimulus to the renovation and modernisation of industries which is an urgent problem in our economy.

A surcharge of five per cent on income-tax has been levied on companies since 1972. The Budget proposes to exempt the companies from this surcharge provided they deposit an equal amount with the IDBI. This will mean that the IDBI will be able to get finance from the industrial sector and pass the money back to the industries themselves. That is, finance will be rotated between industries and the IDBI.

There are, however, certain aspects of the Budget to which I would like to draw the attention of the hon. Fin-

ance Minister. The Budget proposes a massive increase in investment during the next year to realise the social objectives of our economic policy. But may I say that this steep increase in investment is not accompanied by a commensurate effort at resource mobilisation? The additional taxes will net only Rs. 80 crores and some important additions will be made by the Compulsory Deposit Scheme and impounding of dearness allowance. The Finance Minister also expects significant increases in revenue at the current rates of taxation. But all these leave a large deficit of Rs. 320 crores. It is likely that this deficit will increase during the year if the increases in the revenue are not upto the expectations or additional savings as a result of tax concessions do not materialise or are frittered away in the priority sectors. The Finance Minister, therefore, will have to take special care to see that deficit financing is not resorted to on as large a scale as in the past. I need not detail the figures of deficit financing in the last five or six years. If deficit financing is resorted to in the same proportion as the increase in real national output, it does no harm, but if it is out of proportion, then it only builds up inflationary potential. I hope care will be taken to avoid this sort of contingency.

The Finance Minister has rightly expressed appreciation of the work done by the Income-tax Department in connection with the Voluntary Disclosure Scheme. There is no doubt that a number of reforms will have to be carried out to make the Department a fit and efficient instrument of revenue collection. What has been disclosed is merely the tip of the iceberg. There are still any number of people who have escaped the net of the Income-tax Department. Apart from the reorganization of the Department to ensure that the claims of revenue are not sacrificed because of lack of survey, inadequate staff or corrupt and inefficient officials, I sug-

(Shri Y. S. Mahajan.)

gest that the tax payers should be required to submit a complete statement of their assets as suggested by Mr. Kaldor in his report on income-tax reforms in this country.

Sir, we all come from the rural areas and we represent agricultural interests. During the last six months, the prices of agricultural commodities have fallen by 40 per cent, whereas the prices of manufactured commodities have fallen by 2 per cent. The prices of inputs have fallen by 3-4 per cent. Thus, the biggest section of our community has been put to a great disadvantage. I suggest that one economic strategy or pricing policy should be so framed as to see that the majority of our people do not suffer as a result of economic development

Sir, with these words, I support this budget, since it is realistic, imaginative and best calculated to achieve the social objectives of our economic policy.

SHRI S. K RAI (Sikkim): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the very fact I am a part of this August House and have the privilege to participate in matters concerning welfare of the people not only of my State but of the whole country reflects the fulfilment of our long standing aspirations to become a full-fledged member of the great Indian community and to merge in the mainstream of social, economic and political life of the nation.

We are fortunate in emerging as the 22nd State of India. After a relentless struggle for 27 years, we have successfully overthrown the feudalistic autocracy and established democracy. But we have yet to eliminate traces of feudalism from the fabric of our society and fully democratize the social, economic and political life of the region for which we need to build up the infra-structure of education, transport and communi-

cations. We are sure, we will always find an appropriate place in the national priorities.

These are wide ranging and high sounding aspirations and can be fulfilled by a socially conscious and dynamic leader like our beloved Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi.

May I now take the opportunity of congratulating the hon. Minister for Finance, Shri C. Subramaniam, for adopting a new, bold and pragmatic strategy in the budget presented, which underscores the philosophy behind the Prime Minister's 20-Point Programme and for steering the country towards growth and stability.

There may be grounds for disagreement on the basis of one's ideological affiliations when we look at the reduction of the income and wealth tax rates, but in my view, the foremost responsibility, to quote Millon Friedman, of the corporate sector and those who run it is to maximise profits, and I think, this budget gives our private business an opportunity to show dynamism, take the bull of recession by its horns and increase production. Growth economics is a matter of innovation, innovation suited to the genius of the country. This budget is innovative as much as it has tried to evolve a strategy of development hinging on the consumption expenditure of the upper and upper-middle classes. The middle classes are social climbers and in this process they can generate demand and thus bringing an end to consumer shyness witnessed in the country during the past one year and so. Changes in personal taxes are not only welcome but are timely.

I would, however, like to make only two suggestions for consideration by the hon. Minister. One is to link consumption expenditure of the classes that have been given relief in wealth tax to investment so that danger of any inflationary trend it might



produce is checked and the other is aimed at providing relief to parents of the physically handicapped children.

The actual money to be released, due to relief in rates, to the people who fall in wealth tax bracket should not be allowed to augment consumption expenditure. That part can well be played by the money released from the reduction in the Income-tax liability. The amount of wealth tax relief should be directed towards investment. With this purpose in view a number of investment portfolios suitable to various complexions of this class of people and various amounts of monies should be devised. The people concerned should be required to invest their relief money in a portfolio of their choice. In this way, the budgetary relief could be channelised towards growth and the market will be saved from a potential inflationary pressure.

Sir, about the relief suggested by me to the parents of handicapped children, the possibility of crediting the annual actual expenses of parents of physically handicapped children involved in transporting such children to school against their income-tax liability for the year be examined. If the State can help the education of such children in this way, it would actually be helping a citizen to become economically active. Otherwise, if such children are unable to acquire education and productive skills, they will become social liabilities.

Sikkim has but a few sources and resources of revenue. We have, therefore, to maximise efforts to tap and fully mobilise all revenue earning avenues. Tourism and industries, including minerals, are such sectors which remain sadly neglected despite tremendous potentialities. Sikkim has often been described as a Tourist Paradise with a unique wealth of flora and fauna extending from sub-tropical to Alpine ranges. It is also

a God's gift for the botanists, zoologists, bird watchers and animal lovers, yet not much appears to have been done to exploit these potential. Besides this, Sikkim is famous for producing cardamom and Sikkim is also famous for orchards, which can compete in the world market.

The effort of the State Government alone to expand bed capacity by building new hotels, tourists lodges and youth hostels is not enough. In this respect, I would request the Central Government to start a cell to attract tourists, and to issue and extend permits etc. In this way, I hope, our aspirations will reach the Ministers concerned and Sikkim will be developed within no time.

SHRI VASANT SATHE (Akola)  
 Sir, I take this opportunity to congratulate the Finance Minister for having brought a Budget which is a near miracle. In a capitalist system of economy which we unfortunately continue to have in this country this is the best budget that any one could bring under the circumstances, a budget which with one stroke tries to make everybody happy. It is said that it is difficult to please all but here is a budget which has achieved this miracle. Under the existing circumstances, as I said, this is the best budget and he will go down in the history of this country as father of this miracle budget. But what I would like to plead today is that here is the opportunity when we could create conditions where man can raise himself to greater heights and keep pace with the space age and the technology of which the Finance Minister has talked and as Aurobindo said, from man, to elevate himself to the height of a super-man, to create a heaven on earth, as Rabindranath Tagore wanted us to do in free India, to wipe out the tear from every eye which Gandhiji would have us to do, and ultimately, to keep our trust with destiny. I am speaking on the general philosophy behind the budget.

[Shri Vasant Sathe]

You could not have had a better time than now when we have got a dynamic leadership which can translate dreams into realities. I thought we would decide to take a bold step to pass from the capitalist system, to make a structural change from the capitalist system. Today we have two nations in our country, a nation within a nation, a small nation of the elitist class which lives on exploitation of the rest of the 58 crores of our population. Hardly 3 crores of our population in India has got the purchasing power to buy anything of the consumer goods that are produced by our industries in this country. And therefore when the Finance Minister wants to provide in his strategy an employment to 7-1/2 crores of unemployed young men in this country in production work as envisaged, I do not know, with all the miracle that he is performing with the 15 crores, that he has provided there, how he is going to perform this miracle? You want investment with the basic objective of GNP growth, with the objective of capital formation. Where will the capital formation take place? Naturally it will be in those sectors and in those classes where there is capital and who bring about this capital. Therefore, they have a vested interest in keeping the poor poor. Whenever there is higher purchasing power in the rural area it is said that we have to curb inflation. The capitalist system's philosophy is to keep the purchasing power in the hands of the rich classes. In effect we see a triangular conspiracy of the capitalist vested interest, the political vested interest and the bureaucratic vested interest. They all have a common vested interest in keeping this system of poverty, to keep the poor poor, and with all the pious wishes that you may have in a budget like this which is essentially a capitalist budget you cannot achieve socialism through capitalism *via* capitalism, *via* a philosophy of encouraging capitalism. This

is what, unfortunately, this budget will try to do. So, the remedy is to divert the resources from elitist capitalist section to the poor and the rural areas. For achieving this I want to make the following suggestions:

1. For resources mobilisation let us put a moratorium on non-priority sector investment in the urban areas, namely, sky-scrapers, twin cities, under-ground railways, etc. at least for five years.
2. Create at least 20 million tonnes of food buffer-stock this year. It can be done if you want to do.
3. Create a national marketing organisation to bring about a rational parity of prices to ensure remunerative prices to the growers of the raw-material in the rural areas.
4. Create a national rural development authority. If you want to implement this strategy to coordinate all developmental activities in the country and funds to make programmes task-oriented or result-oriented instead of expenditure-oriented as they are today.
5. Bring a comprehensive legislation to put a ceiling on urban property. The present ceiling on vacant land is a farce.
6. The investment incentive should be available only to those who take the industries to the rural areas.
7. Encourage organic manure, which is wasted to the tune of Rs. 900 crores per year, if you want a proper balance and save the fertility of the land.

8. Encourage savings by giving better return Life Insurance Corporation with profit should be made more attractive.

9 Family Planning must mean an economic planning of the lowest family and not mere sterilisation

Last but not the least, increase the lowest taxable level to 10,000 when we have reduced the upper limit to 66 per cent

**SHRI RAJA KULKARNI** (Bombay-North-East) Mr Deputy Speaker, Sir, I go a step further in giving compliments to the budget and to the Finance Minister who has put this budget. The compliments that have been given in this House are that it is a growth-oriented and production-oriented budget. No doubt it is growth and production oriented but at the same time I submit without any exaggeration that it is also a socialist budget.

I call it a socialist budget because whatever we achieved in the previous year has been as a result of the non-budgetary measures namely the effective implementation of MISA COFEPOSA income-tax raids or voluntary disclosure schemes and the implementation of the 20-point programme. As a result of these non-budgetary methods and measures, our country has achieved a miracle. It has saved not only our political democracy but our socialist policy of economic growth of the last 15-20 years. The concrete result was that inflation was put on the minus side which was a singular achievement compared to all the other countries in the world. We have achieved this through non-budgetary measures and the socialist task of the budget was to consolidate those gains and to root out from the economy some of the anti-socialist elements and forces which nourish inflation. The accent,

therefore, was on production. This budget is now consolidating the socialist policies and achievements of the outgoing year.

In the incoming year, the socialist budget tries to do this by relying on two important pillars of socialist policy. One is the savings which mostly are surpluses of the public sector undertakings. This budget is relying on higher production to meet the record increase by 31.6 per cent, to about Rs 7800 crores in the plan outlay. Reliance is placed on surpluses of the public sector undertakings. This is the basis of the socialist budget.

Secondly a new chapter has been opened and a new dimension has been added. There is an acknowledgement that the organised working class has also contributed its due. Government wants to rely on the savings of the organised working class. Government has taken a decision to defreeze Rs 480 crores which were with the Reserve Bank in a frozen account as an anti-inflationary measure. Earlier they were not to be used for growth purposes.

Government has now taken a decision that the savings of the working class frozen out of the compulsory deposit scheme of dearness allowance, are to be utilised for growth. There is nothing wrong in it.

**SHRI C M STEPHEN** (Muvattupuzha) Mr Kulkarni is saying that about Rs 480 crores or so which will be with the Reserve Bank frozen, will be used for planning purposes. The Finance Minister tells us that the deposits during the extended period will be used for the plan and also he says further that the government will abide by its assurance to repay the instalments of additional dearness allowance already impounded and falling due in regard to the existing scheme. From the statements of the Finance Minister, it is clear that what

[Shri C. M. Stephen]

is now due to the workers will be paid back to the workers and for the planning purposes the amounts which will fall due during the extended period, alone will be used. From where does he get the information that whatever has accrued will be used for planning purposes?

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is for the Finance Minister. . . .

SHRI RAJA KULKARNI: It is my reading of the Budget.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, please. Everybody is so full of speeches that nobody wants to listen. He has made a point and I should like to say one or two sentences or to make one or two observations. You would not allow even the Chair to say something?

I was saying that it was for the Finance Minister to clarify the position. But what I also understand is that this Rs. 450 crores which were frozen in the Reserve Bank of India would be utilised for investment; money would be taken out from that. That is what I understand. It is for the Finance Minister to clarify. I also understand that the Government will also meet its obligation of repaying to the workers part of the money which it has imputed. I think the two things go together. It is for the Finance Minister to clarify the position.

The Finance Minister in his budget has stated that by way of repayment to the working class during this year, there would be an amount of Rs. 270.0 crores and the other savings which are now to be defrozen and utilised for the economic growth would amount to Rs. 480.0 crores. Now this amount of Rs. 480.0 crores is the contribution of the working class. To this contribution of Rs. 480.0 crores, there is further to be added a net saving of Rs. 190.0 crores in the Provident Fund Account. The accumulation of the provident fund during the budget year would be Rs. 395.0

crores and for the disbursement of the provident fund, the amount as budgeted would be about Rs. 205.0 crores. The net savings on this account at the disposal of the Government would be about Rs. 190.0 crores. Further, additionally the net amount that would be available to the Government from family pension-cum-life Insurance scheme would be Rs. 39.0 crores. Thus, in all it would be more than Rs. 700.0 crores of the workers' money which would be placed at the disposal of the Government. This opens completely a new sector for national development purposes. If the growth of the nation depends on the contribution of working class, it is here, to contribute for that purpose. So, a "workers sector" is opened in the national economy. Workers can go a step further and ask the Government that they want to have some share in the national economy, by way of share-holding or sharing of surpluses from public sector undertakings or from the foreign companies which are now being nationalised.

Now, I would say that the Provident Fund linked Insurance Scheme has widened the horizon of social security. In view of amount, it would not be so important. This budget has brought in through the working class a new dimension to the social security administration in this country.

There is also an expectation that with the reliefs that have been given in excise duties on a large number of items of engineering and electronic industry, lay-offs and retrenchments are likely to be stopped. But at the same time I would like to caution the Government that in case the entrepreneurs and the employers in the engineering industry or the car manufacturing industry, come and ask for further relief with a plea to avoid lay-offs and retrenchment, then the working class will have to go to the Government and request them to take some stringent measures.

It is true that so far as petroleum, chemical and fertiliser are concerned, there has been no change in the existing rates of duty. But Government has been vested, through the Finance Bill, with a new power enabling it during the budget year they might reduce the rate of duty. This power has to be granted by this House. But Government should think twice before doing so. In fact there is a necessity to cut down the cost of these items.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have explained the point.

SHRI RAJA KULKARNI: The excise duty revenue from petroleum, chemicals and fertiliser industry is expected to be about Rs. 1400 crores as against an investment of about Rs. 774 crores in this industry. Therefore, I feel there is scope for reducing the excise duty on petroleum.

SHRI K. S. CHAVDA (Patel): Sir, during the last week, the Rajya Sabha expressed concern over the health of Khan Abdul Ghaffar Khan who is now in detention in Pakistan. The Minister of External Affairs, Shri Y. B. Chavan, expressed his concern by saying that Badshah Khan was one of the great leaders during our freedom struggle. Shri H. D. Malaviya, a member of Rajya Sabha...

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not customary to refer to the proceedings of the other House during the same session except when it is a definite statement of policy. Don't refer to what is going on in the Rajya Sabha. You may make your own points.

SHRI K. S. CHAVDA: Here also in this august House we do express our concern over the health of Badshah Khan, but what about the health of those leaders of the freedom struggle who are now under detention since 26th June, 1975? Morarji bhai has been detained...

MR. DEPUTY-SPEAKER: I do not understand how these things come in. There is such a thing as relevance.

SHRI K. S. CHAVDA: Sir, the Government is spending money on the detenus and we are speaking on the budget. It includes everything.

MR. DEPUTY-SPEAKER: A very ingenious method! Yes, some money is being spent by the Government on them. All right; go on!

SHRI K. S. CHAVDA: The country does not know about their health. If the emergency is lifted and the political detenus are released, well and good. If not, the least the government should do is to issue health bulletins about the health of Morarji bhai and other political leaders who are under detention. This is my submission.

Coming to the budget, I fail to understand why the Finance Minister has become very harsh on the sick man. He has proposed imposition of taxes to the extent of Rs. 30 crores on drugs. He has increased the excise duty on patent and proprietary medicines from 75 to 125 per cent, which will yield about Rs. 20 crores. On medicinal preparations containing alcohol, narcotic drugs etc the increase in excise duty is from 10 to 20 per cent, which will yield about Rs. 10 crores.

The Drugs and pharmaceutical industry pays about Rs. 80 crore to the Government by way of excise and customs duties on the drugs whose annual production is about Rs. 360 crores. I would, therefore, request the Finance Minister to drop this proposal of increasing the excise duty on drugs.

A great deal of subversive and corrupt activities are going on by multi-national corporations in our country. It is alleged that M/s. Pfizer, M/s. Abbott and M/s. Merck, Sharp and Dhome are supporting CIA anti-

[Shri K. S. Chavda]  
vities in our country. I would like to read a strictly confidential letter of M/s. Hoechst and a news item regarding M/s Pfizer before the House so that one can know how the multinational corporations are operating in our country against the national interest.

"We are supplying our veterinary and agro products to Government departments, on 5 per cent more rates than the rates applicable to our distributors. This means, our rates are different to Govt supplies than to the trade parties. If any officer is willing to place an order with us for our products, we shall pay him the difference of 5 per cent as gift, commission, incentive etc. In other words, if we pay this amount to the intending officer, the Company loses nothing, but we are paying the commission amount to the officer from the Government funds, as we are charging more from the Government

We have already executed orders under this arrangement and any order above Rs 5000 - will be covered under this system

However please keep this information very confidential and nothing should be brought on record about this transaction. You should only send such proposals on rough piece of papers. Further please also ask the stockists and the intending officer of the Govt office not to bring anything on record

I would also like to read a news item regarding Pfizer which has appeared in the yesterday's Financial Express.

"Pay-offs by Pfizer. New York, March 20, Pfizer INC today announced that employees of its overseas subsidiaries made \$ 265,000 in illegal direct payments to foreign government officials in three countries. The pharmaceutical firm which voluntarily reported the pay-offs to the securities and exchange commission, re-

fused to identify the three nations or the foreign subsidiaries involved."

The record of the Pfizer is not good in America also. I only want to quote a few headlines appeared in the American newspapers.

"Two companies accused of drug patent fraud—US \$ 25 million damage claimed against Pfizer, and Amical cyanamide"

This appeared in the Los Angeles Times edition of July 16, 1969. In the same way, Wall Street Journal Staff Reporter, Washington reported:

"Justice Department sued Pfizer, an American cyanamide for at least \$ 25 million of damages allegedly resulting from over-charges on Govt. purchases of tetracycline and related anti biotic wonder drugs"

9 Members of Parliament have written to the Prime Minister that the licence for the production of doxycycline should not be given to it. Regarding that, I read one news item which appeared in Chemical Marketing Reporter:

"Pfizer is disappointed by a just decision on doxycycline. The Federal Judge ruled that Pfizer's patent of the anti-biotic drug doxycycline is invalid and unenforceable."

What I am trying to place before this House is this. Such Company should not be given licence for the production of drugs like doxycycline. IDPL has been given a licence for doxycycline, upto a capacity of 5 tonnes, and the other Indian firms also are given the licence. It is much more than what is required for our country. Suppose the licence is given to Pfizer. In the drug industry, if the lead is established, it is impossible to compete and come up with the leader. This will happen, so far as IDPL, a public sector undertaking, is concerned. And this undertaking will not come out of the red. The whole of the equity capital of IDPL, viz. Rs. 23 crores has been wiped out by the cumulative

losses till now. Here, Pfizer is requesting the Government to give the licence. I am making a request to the Government, because just now, it is lying before the Cabinet Committee. I would request them not to give the licence for the production of doxycycline to Messrs Prizer, in the interests of the nation and of the public sector. Our country is just self-sufficient so far as anti-biotics are concerned; and this is the only multi-national which is asking for licence for doxycycline, for which Letters of Intent have already been given to the national sector, I mean to the public sector and to the private sector.

The Finance Minister has proposed in the budget, to switch over from specific excise duty to a system of *ad valorem* duties on cotton cloth. The net effect of this change would be to increase the price of cloth, viz. of super, medium, fine, super-fine and other varieties of cloth. This will not reduce the prices of lower medium and coarse cloth. That is why this will not give any relief to the weaker and vulnerable sections of the society, as claimed by the Finance Minister in his speech.

Coming to the decade of progress, a great deal of propaganda is made about the officially-inspired celebration of a decade of progress 1966-76. What is the progress made up till now? Unemployment is mounting year after year; and prices have increased much higher, from what had prevailed in 1966. The Wholesale Price Index was 131.6 for all commodities, in 1965-66 it went up to 313.7 in 1974-75. In respect of food articles, the index was 144.6 in 1965-66; it went up to 363.6 in 1974-75. There was an increase in prices to the extent of 250 per cent compared to 1966. Who is responsible for this? I say that it is the Government of India which is responsible for this.

On the 6th June, 1966 the Indian rupee was devalued. Its value was fixed from Rs. 4.76 per US dollar to

Rs. 7.50 per US dollar and from Rs. 13.33 per pound sterling to Rs. 21 per pound sterling. Secondly, the bank rate of Reserve Bank of India was 5 per cent in 1968. It was raised from 5 to 6 per cent in 1971, to 7 per cent in 1973 and to 9 per cent in 1974. This is the economic situation.

What is our position in the international field? To give a recent example, both India and Pakistan contested for seat in the Security Council and we secured 58 votes and Pakistan 75 votes in the 7th ballot. Though Pakistan had maintained the leading position in the ballot, it failed to secure a two-thirds majority to win. India could not secure more than 58 votes in a House of 142.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What has this to do with the budget?

SHRI K. S. CHAVDA: They speak a lot about the Decade of Progress.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are talking of the budget for next year.

SHRI K. S. CHAVDA: So, India did not secure more than 58 votes in a house of 142. Therefore, she withdrew from the contest, thus enabling Pakistan to become a member of the Security Council. This is our position in the international field.

They speak a lot about the welfare of the weaker sections, but I do not find anything which gives relief to the weaker sections in this budget.

SHRI RAGHUNANDAN LAL BHATIA (Amritsar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I do not know what Shri Chavda was speaking about. He was so irrelevant in his speech that one could not make out what he was driving at. Sir, perhaps you might have been able to understand him better.

This year's budget is a reflection of Government's determination to have accelerated economic growth with greater social justice. It is also evi-

[Shri Raghunandan Lal Bhaia]  
dent that the various measures that Government took sometime back have brought about fruitful results before us, and that is why I say that the present budget, which has brought about cheers from all sections of our society, is the direct result of those policies.

I do not agree with Dr. V. K. R. V. Rao when he says that the present budget was inevitable in the present circumstances. Who created those circumstances? Who created this position in which we find ourselves today? It is because of the dynamic leadership of our Prime Minister and the policies that she has adopted that we are today in a better shape and a better position. It is as a direct result of those policies that we are today in a position to give certain facilities to all sections of our society.

The Finance Minister in the present budget has made a bold attempt to break through from the diffident approach of the past. He has given concessions to the industrial sector. Direct taxes have been reduced from 76 to 66 per cent. It will give sufficient lure in the hands of the industrialist to grow more, to accelerate the rate of growth, to expand, to modernise their mills for the betterment of this country.

14.00 hrs.

The 25 per cent investment incentive given to the new industries and new machinery is also another incentive which, I am sure, will accelerate our growth and will be for the betterment of our country. But I am very sorry to say that the Finance Minister has not paid proper attention to the rural sector. In order to accelerate growth of our agriculture, an area which requires greater attention, which requires more facilities, only Rs. 100 per tonnes by way of concession has been given in the inputs. This is not enough. Seventyfive per cent of the people in this country are

farmers, or live on agriculture. So, it is that sector which we have to strengthen. The present recession in industry is because of the fact that there is lesser purchasing power left with the agriculturists. The present rates for their produce are not high enough to sustain the modern, technical and scientific treatment which they are giving to agriculture. The price of tractors is very high, the rates of electricity are increasing every year, the water rates are going up, the prices of agricultural implements have also risen and the prices of fertilisers were almost doubled last year. All this has reduced the purchasing power of the agriculturists, and that is why there is recession in industry. Whatever concession or preference you may give to industry, unless you fortify the purchasing power of this 75 per cent of the population, industrial growth will not taken place the way we want it. I therefore suggest that the agriculturists should be given more concessions. The prices of fertilisers should be reduced, tractors, should be made available at cheaper prices, and similarly other facilities may kindly be made available to the agricultural sector.

The Finance Minister has been kind to the industrialists and to some extent to the agriculturists, but there is one section of our society which has been left untouched, and that section is the large number of people who fall under the fixed income group. It is the salaried people who suffered more in the inflationary period, but no attention has been paid to those people who are paying their taxes more honestly because their tax is deducted at source. They have no means to save money. May I therefore suggest that the exemption limit may be raised from Rs. 8000 to Rs. 12,000? I strongly demand this concession for this section of the people to whom the Finance Minister has not paid any attention. The only argument that can be urged against this suggestion is that Government will lose some revenue. I agree with that, but at present a large number of asses-



cases are being tackled by the ITOs. If they are freed from looking after a large number of assessees who pay very little, they will be able to devote more attention to the bigger cases, and Government's revenue will increase. Secondly, there is a lot of tax arrears with the income-tax department, and the officers are not able to pay attention to the recovery of these arrears because they have to dispose of a large number of cases. Thirdly, if the ITOs have enough time, they will be able to find new assessees and Government will not lose money at all.

When we nationalised the banks, we wanted to serve the unbanked areas. I congratulate the Finance Minister on the success achieved by the banks in serving the unbanked areas, but I find that the banks are not paying proper attention to our policies, the policies for which we nationalised them, to give more money to the weaker sections of the society, to provide credit to the agriculturists in the villages. The banks are shy of investing in such areas. The present system of banking is the same that we had before. So, there is need to change this system. At present we have 14 Chairmen, 14 Managing Directors and other paraphernalia which is very expensive. I strongly demand of the Finance Minister that the banking system should be organised into four or five ones. All the branches of all the banks should be placed under one zone. What we find is that in every bazar all the banks are competing to have a place by paying higher rent and all that. This is not a proper service.

Punjab gives 60 per cent of their wheat to the National Pool; Punjab gives 95 per cent of their rice to the National Pool. But, unfortunately, I do not know why the Centre is not paying any heed to Punjab's problems. We have a lot of problems. There is a general feeling that Punjab is a very prosperous State, this and that. But we have very many problems. Every

year, there is a flood in the Ravi because of the fact that Pakistan has built a *bandh* on the other side of the river. The result is that water flows to India. Every year, we are having floods. What we need is Rs. 5-6 lakhs to build a *bandh* on this side. I would request the Centre to give us this help. Punjab has 11 million acre-ft of water. Out of this, 33 per cent is lost in the seepage. We want to line up our canals and channels. For that, we need money and I hope that the Centre will come forward to give this money.

In the case of a scheme to help small and marginal farmers, what we find is that Punjab is giving the maximum of help to the National Pool, but we are getting the minimum of help. They give us only Rs. 250 lakhs in this sphere, when we say that we are helping the small farmers and this and that. Instead of giving anything to Punjab, they are taking away. During the 1st year, Punjab's bank deposits was Rs. 250 crores, but the Nationalised Banks invested only Rs. 60 crores. This is not fair. I request the Centre to look into the problems of Punjab. Punjab is giving rice, wheat, water and electricity to other States. But a little help we want, they must come forward to help us.

श्री नाथू राम बिर्बा (नागीर): उपाध्यक्ष महोदय, दस मिनट में इस बजट को बारे में बहुत कहना सम्भव नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस साल का बजट एक नये तरीके का बजट है और मैं समझता हूँ कि नये हानान में इस बजट को इसी तरह से माना चाहिए था।

बहुत से प्रगतिशील तत्व, जो इधर या उधर बैठते हैं, इस बजट से काफी नाराज हैं। उन का कहना है कि पूँजीपतियों पर टैक्स हमेशा बढ़ाना चाहिए। एक समय अधिक से अधिक टैक्स 97½ परसेंट तक बढ़ गया था। बाद में उसको घटा कर 77 परसेंट कर दिया गया और इस बजट में उसको और घटा कर 66 परसेंट कर दिया गया है। इसी कारण

[श्री नाथू राम मिश्रा]

उन लोगों की नाराजगी है और इसी लिए वे इस को पूंजीवादी बजट कहते हैं। पर मेरी राय में टैक्स कम करने, अनावश्यक खर्च में कमी करने, बचत करने और योजनाओं पर ज्यादा खर्च करने के बिना देश की आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती है। इसी दृष्टि से टैक्सों में कमी की गई है। इस बजट में दूसरे सालों के मुकाबले में नये टैक्सों का माबिलाइजेशन कम है, जब कि योजना के खर्च में 31.6 परसेंट वृद्धि एक बहुत अच्छी बात है। इस बजट में बिजली और खाद के ज्यादा उत्पादन और सिंचाई तथा कृषि के विकास और इस प्रकार एक लम्बी दृष्टि से एक मृदू नीव पर काम करने का प्रावधान है।

एक ग्रामीण की दृष्टि से इस बजट का तुरन्त क्या असर हुआ है, और आज गांवों में क्या हालत है, मैं वित्त मंत्री महोदय की जानकारी के लिए उस का कुछ जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। उन्होंने अपने बजट-भाषण में कीमतों की गिरावट का भी जिक्र किया है और प्राइम इंडेक्स में 7 या 8 परसेंट कमी की बात कही है। लेकिन वह इंडेक्स गांवों की स्थिति को किनना रिफ्लेक्ट करता है, मंत्री महोदय उस पर गौर फरमायें। वह देखें कि पिछले साल रेशों, अर्थात् रुई और जूट गेहूँ और अन्य फूडग्रेन्ज तथा तिलहन के क्या दाम थे और आज उन के क्या दाम हैं। मैं समझता हूँ कि आज गेहूँ के दाम पिछले साल की तुलना में आधे हो चुके हैं। 200 रुपये से ऊपर पर क्विंटल दाम थे। इस दफा अभी 100 रुपये पर क्विंटल बॅस्ट गेहूँ का दाम है और 80 रुपये क्विंटल साधारण गेहूँ का दाम है। जो 50-60 रुपये क्विंटल है, बाजरा 70 से 80 रुपये क्विंटल है। ज्वार भी इसी भाव है। जूट और रुई के भाव पहले से आधे हो चुके हैं। दालें जो 200 रुपये क्विंटल से ऊपर थीं वह आज 100 और 140 रुपये के बीच में हैं। मेरे कहने का मतलब यह है

कि किसान की उत्पादित चीजों के दाम बहुत तेजी के साथ नीचे गिरे हैं और आज किसान की यह स्थिति है कि जो हम ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की थी उस से भी नीचे पड़ी, बाजरा और कोर्स ग्रेन के दाम जा चुके हैं। गेहूँ के दाम भी नीचे जा चुके हैं और वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी नीचे जा रहे हैं; आप का खयाल निगम जो है वह बाजार में बहुत धीरे अनाज खरीदता है और कई तरह की कटौतियां करता है। वह अपने यहां स्टोरेज की भी कमी बताते हैं। तो इस तरह में सही माने में वह जो इतनी अच्छी फसल इस साल ईश्वर की कृपा से आ रही है उस का कैसे मोबिलाइजेशन हो सकेगा ?

जहां तक बजट का ताल्लुक है फूड कार्पोरेशन का वित्त मंत्री ने सिर्फ 100 करोड़ रुपये का इन्विट्री गेयर दिया है और 30 करोड़ रुपये का कर्जा दिया है। इस तरह फूड कारपोरेशन को सारे मार्केटिंग आपरेशंस को मोबिलाइज करने के लिए कुल व्यवस्था 130 करोड़ रुपये की है। ऐसी हानन में फूड कारपोरेशन अगर टोक खरीद की व्यवस्था मार्केट में नहीं जमा सकेगा तो किसान के गेहूँ के दाम 60-70 रुपये क्विंटल तक हो जाएंगे। जब किसान की आमदनी का जगिया गांवों के अन्दर इनकी तेजी के साथ में घुट गया तो उन की जरूरत की जो चीजें हैं जिन के दाम इंडेक्स में रिफ्लेक्ट होते हैं उन के दाम केवल 5-7 परसेंट घटे हैं। किसान को जो मिला है इस बजट में वह हमारे सामने है। हमारे वित्त मंत्री जी ने एक ग्रामीण दृष्टिकोण बहुत सुन्दर रखा है। गांवों के विकास के बारे में उन की बड़ी सुन्दर कल्पना है। वह सब तरह की व्यवस्थाएँ करना चाहते हैं। पर उस का कुल प्रावधान 15 करोड़ रुपये है। खाद के दाम जो उन्होंने घटाए हैं वह भी हमारे सामने हैं—एक बोरी के ऊपर 7 रुपये से 32 रुपये तक दाम घटे हैं। बाकी मारी चीजों में बढ़े हैं। सिंचाई के दाम बहुत बढ़े हैं, बिजली के दाम बढ़े हैं, इनपुट्स के और

बाकी हर चीज के दाम बढ़े हैं। ट्रैक्टरों के दाम जो थे वही हैं। तो किमान के खर्च के अन्दर तो कुछ कामों की है 7 से 32 रुपये प्रति बोरी खाद में और कुछ विशेष उन के खर्चों के लिए तथा गांव के खर्चों के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। तो इस बजट के अन्दर गावों के लिए जो कुछ भी किया गया है मैं समझना हूँ वह काफी नहीं है। आप कहेंगे कि इस के लिए क्या किया जाय तो मेरा पहला सुझाव यह है कि किसान की जितनी भी चीजें इस साल रबी में पैदा हो रही है चाहे वह निलहन हो, चाहे अनाज हो, चाहे सब्जियाँ हो उन को कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की घोषणा करे और उम को खरीदने की व्यवस्था करे। उस को खरीदने के भाव अग्र स्टोरेज की या मनी की या और दूसरी प्राबलम्स हो तो उन को पहले भ मार्ट आउट करे। नहीं तो किमान की प्रामदनी बिन्दुल नीचे चली जायगी और उम री आगे खर्च करने की जो क्षमता है, आगे कमल पैदा करने की जो क्षमता है वह बिन्दुल पट जायगी। इस अलावा टन ममय वस्तुनियों की गहरी मार चल रही है, चांगे तरफ से गावों के अन्दर वस्तुनियों के मारे किसान के प्राण निकल रहे हैं। पिछले तीन चार साल के तर तरफ के बकायों की बहुत तेजी से वसूली तो जा रही है। किमान की हालत इस समय बहुत खम्ता है। गावों के अन्दर बड़े काश्तकार, छोटे काश्तकार और मध्यम काश्तकार का धेद करके जो चलते हैं उन को मालूम होना चाहिए कि वह गरीब काश्तकार सब से पहले अपनी चीज बेचने के लिए बाजार में जाता है, फिर बाद में चाहे मोल ले कर ही उसे खाना पड़े। तो सब से पहले उस का छाटा ज्यादा होता है। इसलिए गावों की हालत के अन्दर इस बजट के बाद कोई बहुत परिवर्तन या सुधार आए इस की गुंजाइश मुझे नहीं लगती। मेरा एक ही निवेदन है कि किसान की जो इस समय कसब में आने वाली उत्पादित चीजें हैं उन चीजों को

ठीक दामों के ऊपर खरीदने की व्यवस्था आप करें। अभी सिर्फ गेहूँ को दाम की घोषणा की है। लेकिन जो तो पचास रुपये किबटल जा रहा है। तो जैसी हालत है उस में मिनिमम दाम सब चीजों के तय कर के सपोर्ट प्राइस पर उन की खरीदने की व्यवस्था हो सके तो किमान के लिए सब से बड़ी बात इस समय होगी।

माननीय प्रधान मंत्री जी भी यहां इस समय विराजमान हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धन जो उत्पादित होना है वह चार चीजों में होता है जिन में वन, खेत और पशु मुख्य है। इन सारी चीजों को कृषि आयोग में देख कर अपनी एक फाइनल रिपोर्ट सरकार के सामने पेश कर दी है। उन की जो रेकमेंडेशंस हैं उन का सही विश्लेषण करवाया जाए। उन सारी चीजों पर जो कदम उठाने हैं, अगर बन्द मिला तो कृषि की मांग के बन्द में निवेदन करूंगा। कुछ कदम तो उठाए हैं कुछ कारपोरेशन बगैरह बनाने के। उन निफारिशों के आधार पर ऊंचे स्तर पर विवेचन कारवाया जाये। यदि गावों के लिए हम नीतियों को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो वह लाभान्वित नहीं होंगे जैसा कि कुछ लोग समझते हैं कि यह बजट सभी को खुश करने वाला है। गावों के लोग आज भी कठिनाइयों और शिकायतों में फंसे हुए हैं।

**श्रीमती लखिमी देवाय (धांवला) :** उपाध्यक्ष जी, मैं वित्त मंत्री जी को और उनके मन्त्रालय को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। अपनी कुशलता, दक्षता एवं व्यावहारिकता से उन्होंने इस देश के बजट को प्रस्तुत किया है। इस देश की प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक रास्ता दिखाया था, एक दिशा दिखाई थी कि इस टूटी फूटी अर्थ-व्यवस्था को हम किस तरह से काबू में ला सकते हैं। उसी के फलस्वरूप आपातकालीन स्थिति की घोषणा हुई, बीस सूत्री कार्यक्रम चला और हमने देखा कि उसके कुछ नतीजे निकले।

## [बीजत सारिणी श्याम]

बीजो की कीमतो मे निरावट आई और बीजो जो गायब ही जाती थी बह गायब भी नही हुई। मुद्रास्फीती भी घटी और इस तरह मे देश मे आर्थिक नियन्त्रण और अनुशासन थाया। आज इस सदन के सामने जो बजट उपस्थित है वह इसी बात का द्योतक है। इसमे इस बात के प्राधार है कि हमने जो सफलता पिछले 6-7 महीनो मे प्राप्त की है उसको कायम रखे। मैं बजट की पडित तो नही हू लेकिन इतना मैं महसूस करती हू कि इस बजट का प्रभाव समाज के हर अंग पर पडा है और हर अंग ने महसूस किया है कि उसको वास्तव से राहत मिली है। गरीब निम्न वर्ग के लोगो को बीजे खरीदने मे राहत मिलेगी और जो ऊचा टैक्स देने वाले हैं उनको कम टैक्स देने से राहत मिलेगी। इस बजट से उद्योगो को 8 से लेकर 22 फीसदी तक लाभ हुआ है। लेकिन एक दुष्टिकोग सरकार को भी अपने ध्यान मे रखना चाहिए, हमे याद है 1967-68 मे जब श्री मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे और जब उन्होंने इस सदन मे वित्त विधेयक प्रस्तुत किया था तब भी उद्योगो को बहुत से लाभ दिए गए थे—मार्नेटाईजेशन के नाम पर, एक्सपेंशन के नाम पर, एक्सटेंशन के नाम पर और नयी टेक्नोलॉजी अपनाने के नाम पर लेकिन कुछ सालो बाद हम ने देखा उसके नतीजे खराब निकले। इस आपान कालीन घोषणा के अन्दर, जो उद्योग है उनकी अर्थव्यवस्था कितनी बदली है इसका अनुमान सरकार लगा सकती है, जनसाधारण नही। हम सम्बन्ध मे सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

जहा तक मजदूरो की बात है, हम देश के मजदूर आपातकालीन स्थिति मे देश की मुख्य धारा के साथ बडे हैं। बहुत कम मिसालें हैं जहां पर स्ट्राइक्स हुई हो। बहुत कम मिसालें हैं जहां पर बर्के को कम किया गया हो।

लेकिन इस सदन मे हमारे माननीय अंग मंत्री ने बताया कि 60-70 हजार से-याफ हुए हैं और इनका नतीजा हमारे देश के मजदूरो पर, उनकी आर्थिक अवस्था पर और उनकी घर की अवस्था पर खराब पडा है। उनके कारण कुछ भी रहे हो लेकिन सबसे बडा कारण तो थिफिंग का, सोच विचार का है। मजदूरो ने अपने सोशल प्रोब्लम नैशन को, अपनी जिम्मेदारियों को समझा है और उन्होंने सोशल आडवैक्टम को सामने रखा है लेकिन उद्योगो के सामने सोशल आडवैक्ट नही रहा, उनके सामने प्रॉफिट का आडवैक्ट रहा। अगर बीजो की खपत बाजार मे कम हुई तो उन्होंने से-याफ किया, मजदूरो का रिट्रेन्वैक्ट किया। कानून मे प्राविजन है कि सरकार से इजाजत ली जायेगी तब वे मजदूरो को से-याफ कर सकने हैं। इसलिए मैं ममझती हू इस पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है कि किस तरह से उम वर्ग के लिए, जिसको हमारी प्रवान मंत्री ऊचा उठाना चाहती हैं, उयोगी कदम उठाये जायें। आज सारे देश मे सोचने विचारने का माहौल निम्न वर्ग के उन्धान के पक्ष में बना है फिर भी अगर इस तरह से मजदूर निकाले जाये या उनकी मजदूरी न मिले तो उचित नही। महिलाओ को तो मन्तकिल नौकरी नही मिलनी है, आज भी फीटरीज मे यह हालत है। ऐसी स्थिति मे हम उम निम्न वर्ग के लिये, जिस के लिये कुछ करने के लिये हम ने प्रण किया है, उस के लिये कुछ करने मे कामयाब नही हो सकेगे।

इस बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा के बाद मुझे अपने क्षेत्र मे, जो कि एक प्राथीय क्षेत्र है, भूमने का अवसर मिला। मैंने अपना काफी समय इस में लगाया है और

जो मैं महसूस करती हूँ या जो मैंने देखा है—हमारे यहाँ जो भूमि लोगों को मिली है, उसमें पानी का अभाव है। रबी की फसल की बुझाई इस समय तक हो जानी चाहिये थी, लेकिन अभी भी बहुत से खेतों में नहीं हुई पाई है, इसका कारण यही है कि उनको पानी प्राप्त नहीं हो सका। अच्छे बीज तो उनको किसी तरह से मिल गये, लेकिन पानी और ऋण नहीं मिल सका। नतीजा यह हुआ है कि जमीन के ये टुकड़े अभी भी सूखे पड़े हुए हैं। इससे हमारे यहाँ अनाज में जो बढ़ोत्तरी हुई थी, उसमें गिरावट आयेगी। हम अभी भी अनाज विदेशों से मगा रहे हैं, मैं यह नहीं कहती कि हमारे यहाँ कमी है, इस लिये मगा रहे हैं, बल्कि उस लिये कि हमारा अनुमान है कि विश्व में अनाज की कमी होने वाली है। इसी लिये हमारी प्रधान मंत्री जी ने अपनी दृग्दर्शिता से अपना यहाँ बफर स्टॉक बनाना का निश्चय किया है, उस स्टॉक को पूरा करने के लिये हम अनाज वाटर से मगा रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना जरूरी है कि अनाज के सबंध में हमें जो सफलता प्राप्त हुई है, वह चटनी नहीं चाहिये।

पिछले दिनों खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन के अनेक मुद्दाओं के आधार पर तथा उनसे धन लेकर कुछ उद्योग धंधे देहातों में शुरू हुए। मैं कम से कम नहेलखंड के सबंध में तो कह सकती हूँ—मैंने देखा कि इन उद्योग धंधों में जो सामान बना, उनके लिये मार्केट नहीं मिला। अगर बनी हुई चीजें बिक नहीं पायीं, तो फिर लोग कैसे चीजों को बनायेंगे, कर्जा कैसे वापस करेंगे—यह हानि उनको व्यक्तिगत हानि ही नहीं राष्ट्र की भी हानि है। इस लिये मेरा सुझाव है कि देश में एक नेशनल मार्केटिंग ऑर्गेनिजेशन बनाया जाय जिसकी शाखायें हर राज्य में तथा हर जिले के अंदर खोली जायें। इस ऑर्गेनिजेशन के जरिये इन उद्योग-धंधों

के बनाये हुए माल को बाजार में लाया जाय, जिससे कि वे चीजें बिक सकें और हमारे किसानों को फायदा हो सके।

कुछ शब्द में परिवार नियोजन के सबंध में कहना चाहती हूँ। परिवार नियोजन हमारे लिये "मस्ट" है। हमें चाहे जितनी उन्नति हो, यदि अपने परिवार को नियोजित नहीं कर सकें तो उस उन्नति का कोई लाभ देश को नहीं हो सकेगा। इस सबंध में विभिन्न राज्यों में अलग-अलग कानून बनाये जा रहे हैं, हरियाणा में अलग कानून बन रहा है पंजाब में अलग कानून बन रहा है, उत्तर प्रदेश के सबंध में भी घोषणा की गई उसमें कानून की बात नहीं थी, लेकिन कुछ इन्फ्लिक्शन और डिस्ट्रिक्शन की बात थी। मेरा सुझाव है कि यदि इस सबंध में लेजिस्लेशन की जरूरत है तो वह लेजिस्लेशन केन्द्र में बनना चाहिये। इसका इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन सब के साथ बिना किसी क्लाम, क्रीड या जाति के भेदभाव के, समान रूप में होना चाहिये। यह हमारे देश की आर्थिक समस्या है, इसका धर्म या जाति से कोई सबंध नहीं है, यह सब पर समान रूप में लागू होनी चाहिये। सब में पहले तो मैं इस मत की हूँ कि इसको परामर्शन में, इन्फ्लिक्शन या डिस्ट्रिक्शन देकर इसको कामयाब बनाने का प्रयास होना चाहिये, यदि इसमें सफलता न मिले और कानून बनाना पड़े तो कानून बनाने में भी हमें नहीं हिचकना चाहिये। जो लोग बच्चे पैदा नहीं करने हैं या जो लोग लैट शादी करते हैं या शादी नहीं करते हैं, वे हमारे इस इवानामिक प्रोग्राम में मदद कर रहे हैं। मेरा सुझाव है—हमारे यहाँ इन्कम टैक्स में 8000 रुपये तक की छूट है, ऐसे लोगों के लिये हमें अपनी इन्कम टैक्स लिमिट 12 हजार रुपये कर देनी चाहिये, जिससे कि और ज्यादा लोगों को इन्फ्लिक्शन मिल सके और हमारा यह आर्थिक प्रोग्राम सफल हो सके।

**SHRI D. BASUMATARI** (Kokrajhar): Sir, at the outset I must congratulate the Finance Minister and the Government for presenting this year a real common man's Budget, though the Opposition Members may not agree. For the first time, after Independence, we find that the prices have started showing a downward trend, and the Government has been pleased to grant all-round concessions in various taxation measures which will go a long way in benefiting the common people, particularly the weaker sections of the society.

This is due to the dynamic leadership of our Prime Minister who has given to the country a new and dynamic 20-point Economic Programme for the development of the country which, in the present atmosphere of discipline all round, is bound to increase the national income, give the much-needed boost to agriculture, trade and industry and also improve the lot of our poor, down-trodden people.

My friend Shri Kulkarni has spoken eloquently about the organised section of the people. I am speaking about the un-organised people in slums.

Since independence, welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been talked about outside and inside highly so much so that it has become a matter of jealousy for the other communities. Wherever we go, tauntingly it is said that it is the day of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Hon'ble Deputy Minister Shrimati Sushila is here. She must know where we stand.

In the field of literacy, we find that as per 1971 census the general literacy percentage is 29.45, that of the Scheduled Castes is only 14.71 per cent and that of the Scheduled Tribes still less at 11.29 per cent. If we take the figures of literacy of women among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, we will get still further disappointed. The literacy among Scheduled

Caste women is only 6.45 per cent and that among Scheduled Tribe women is only 4.88 per cent. Until and unless the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are educated, it will be appreciated that they cannot avail of the facilities given to them *i.e.*, these people will not be in a position even to take advantage of the benefits which the Government is providing for them.

Side by side with the education of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and poorer sections of the society, we must also look into and work for the economic upliftment of our less privileged brethren. Without economic position, they cannot achieve their due social and educational position in society. Although a number of orders providing for reservations for Scheduled Caste, and Scheduled Tribes and concessions for them in services have been provided and there has been a slow increase in the employment of these communities in the services, the position is still most unsatisfactory. As Chairman of the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, I have had occasion to examine various Ministries and Departments and Public Undertakings, including Nationalised Banks, etc. But we have been disappointed to see the meagre representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services thereof. For example, we find that in the Central Government Services in Class I, Scheduled Castes are only 3.36 per cent and Scheduled Tribes only 0.51 per cent. In Class II Services of the Central Government, Scheduled Castes are only 4.39 per cent, and Scheduled Tribes 0.48 per cent. Even in Class III Services of the Central Government, Scheduled Castes are much below their quota, *i.e.*, they are only 10.10 per cent and Scheduled Tribes 1.90 per cent. As will be seen, the position of Scheduled Tribes is absolutely hopeless.

It is not that it is only in the Central Government Services that the representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is unsatisfactory, even in the Public Sector Undertakings:

of the Government of India, the position is equally bad. In Class I Services of the Public Sector Undertakings under the Government of India, Scheduled Castes are only 1.20 per cent and Scheduled Tribes 0.27 per cent. In Class II Services of the Public Undertakings, Scheduled Castes are 2.98 per cent and Scheduled Tribes 0.42 per cent. In Class III Services of Public Sector Undertakings, Scheduled Castes are 10.27 per cent and Scheduled Tribes 4.66 per cent.

In the Nationalised Banks, in the Officers' category, the percentage of Scheduled Castes varies between 0 per cent and 1.10 per cent. So far as Scheduled Tribes are concerned, their percentage varies between 0 per cent and 0.45 per cent. It is not that it is only in the Officers' Class of the Nationalised Banks that Scheduled Castes and Scheduled Tribes have a poor representation. Even in the Clerical staff, the percentage of Scheduled Castes varies between 0.41 per cent and 7.67 per cent. For Scheduled Tribes in the Clerical cadre in the Nationalised Banks the percentage varies between 0.3 per cent and 0.89 per cent.

From these figures of employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services, it will be seen that much greater efforts will be needed to fulfil their quota in services. In this connection, I would like to draw the attention of the House to provisions of Article 335 of the Constitution which says that the claims of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union and of a State.

Now whenever the question of reservation comes, their stock reply is that there are no suitable candidates under shelter of this Article. So, we

have proved in various cases where they said that there were no suitable candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes available, that sufficient number of candidates are there and actually, we take the applications of the candidates and give them to examine.

MR DEPUTY SPEAKER: What should the Budget do about it?

SHRI D. BASUMATARI: Now they have agreed, very reluctantly agreed, after great persuasion. I think it is all due to the mentality inherited by certain officers from the old colonial days. Sir, you and I belong to the same State the same Tribal. You imagine if this is the attitude how can the country be expected to develop?

Another point, since Independence, our government has taken very keen interest in the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They have created about 500 Tribal Development Blocks. In 1969 when we examined the Tribal Development Blocks, we found that the land belonged to the tribals but after some years it is found to have been alienated. When the roads were constructed and the tribal blocks made accessible, money-lenders and sowcars went there and usurped all the lands from the poor tribals unscrupulously. Now the Tribal Development Blocks have been merged into Integrated Area Development Schemes. We are told that sub-plans for Tribal Development has to be prepared by the States. But I am sorry hardly any State has yet finalised its sub-plans for tribal development. I would request the government to impress upon the States to finalise the sub-plans without any further delay.

...another point I want to make is: in the tribal areas the State Governments have auctioned the liquor shops to contractors and this drink evil, instead of improving the lot of the poor tribal, has actually ruined them. I would

[Shri D Basumatari]

urge that the evil of drinking should be abolished in the tribal development blocks forthwith

Now, they are thinking of rehabilitation of the tribal people many of whom have been ousted from their hearths and homes Here at hand at Deihu, our committee visited the slum areas where scheduled castes people live. They have been uprooted from their earlier slums and shifted to some far away places and they have been given plots of only 22 sq yards Do you think anyone can construct a house on a 22 sq yard plot? It is just impossible So in the new places also they live like pigs and create new slums just contrary to our drive for socialist society

MR DEPUTY SPEAKER The hon Member is not listening to my bell If he goes on like this I do not wonder why the Scheduled Tribes do not get a fair deal (Interruptions)

श्री श्री० सुलतीराज (वेदवाण्डल्ल) :  
उपाध्यक्ष महोदय मुन्नहमय्यम जी ने जो बजट पेश किया है, उस का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। चाहे कोई भी कुछ कहे, सुन्दर भा बजट उन्होंने पेश किया है। कई चीजों के रेट इस में घटे हैं और घटने जा रहे हैं।

जैसाकि बहुत से वृज्जों ने कहा है, उन्होंने बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ध्यान शायद कम दिया है, ऐसे मुझे लगता है। रेट्स कम होने से वैसे सब को खुशी है लेकिन किसानों को खाद और बीज बर्गरह लेने में जो पैसा देना पड़ता है वह ज्यादा होता है जबकि उन को अपनी उपज का रेट कम मिलता है। इस से किसानों को ज्यादा नुकसान होता है। फर्टिलाइजर इत्यादि खरीदने के लिए जाते हैं तो उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। जब अपनी उपज को है मार्केट

में लाकर बेचते हैं तो उनको उस उपज के कम दाम मिलते हैं। किसान हमेशा मुर्खोंबत में पड़ा रहता है। पहले तो उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है पैदा करने के लिए लेकिन जब वह अपनी उपज को बाजार में लाता है तो जो कमिशन एजेंट होता है वह वैसे खा जाता है। साथ ही उधर मजदूर वैसे क्षि जाता है। अतः में उसको कुछ मिलता नहीं है। इन सब मुसीबतों के कारण वह निरन्तारित हो जाता है। मैं नहीं कहना कि लेबर का पैसा, उनकी मजदूरी नहीं बढ़नी चाहिये। वह बढ़नी चाहिये। लेकिन किसानों के लिए भी कुछ सहूलियतें पेश की जानी चाहिये।

छोटे किसानों को कर्ज देने की बात की जानी है। लेकिन कर्जों में साथ तरह-तरह की शर्तें लगा दी जानी हैं। कहा जाता है कि तहमीलदार से लिखा कर लाओ, बी डी आ में, सब रजिस्ट्रार में लिखा कर लाओ। सब फार्मलटीज जब वह पूरी कर लेता है तो उसको जो अपना मिलना है उस में आधा उमका फार्मलटीज आदि पूरी करने पर ही खर्च हो गया होता है। आधे पैसे से वर जब वह खाद बर्गरह लेने में लिखा जाना है तो उसका दाम उमका ज्यादा देने पड़ने है। बाजार में जब वह अपनी उपज लाता है तो उसको जो रेट है वह कम दिया जाता है रेट ही कम हो जाता है। इस वाम्ने ये सब जो बातें हैं इनकी तरफ आपका ध्यान माना चाहिये।

मैं चाहता हूँ कि ग्रामीणों के लिए बैंकिंग की सुविधा का विस्तार होना चाहिये। वहा से उनको कर्ज मिलने में सुविधा होनी चाहिये।

घाज चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन मैंडम प्राइम मिलिटरी श्रीमती इंडियन गांधी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है वह



बहुत ही संतोषजनक है। बीस सूची कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी हटाने का जो कार्यक्रम बना है इसको एक तरह से मैं एक छोटी सी जंग ही कहूँगा और मेरा विश्वास है कि श्रीमती इंदिरा गांधी इस जंग की अवश्य जीतेंगी। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग लोग कई चीजें पास करते हैं। वे बहुत अच्छी चीजें होती हैं। लेकिन राज्यों के अधिकारी या यहाँ के लीडर जो हैं उनको देखना चाहिये कि उन चीजों को ठीक तरह से इम्प्लेमेंट किया जाए। मैं यह तो नहीं कहता हूँ कि सभी अधिकारी या सभी लीडर वहाँ अच्छे नहीं हैं। कई लीडर और—कई अधिकारी बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ खराब भी है। इन खराब अधिकारियों और खराब लीडरों की वजह से प्रधान मंत्री जी का नाम और भारत सरकार का नाम बदनाम होता है। ऐसे लोगों के विरुद्ध मैं चाहता हूँ कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिये। मैं आपके सामने एक घटना रखना चाहता हूँ। मैं करीम नगर डिस्ट्रिक्ट में पेदापल्लि निर्वाचन क्षेत्र से जीता हूँ। वैसे मैं हैदराबाद जिला वैंट तालुक़ा से रहता हूँ। वहाँ जो घटना घटी है उसकी तरफ़ आपका ध्यान दिलाना मैं अपनी फ़र्ज समझता हूँ। वहाँ 38 (इ) के तहत जमीन का पट्टा कर दिया प्रोटेक्टिड टेनेंट की फ़ेबर में और गवर्नमेंट की तरफ़ से तहसीलदार ने आर्डर भी कर दिया, कोर्ट का इंजैकशन आर्डर भी है कि उन लोगों को उस जमीन पर नहीं आना चाहिये। जमीन का पोज़ेशन देने के बाद भी वहाँ पर मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि वे पुलिस अधिकारियों की मदद से वहाँ के जमींदारों की मदद से, वहाँ एक आदमी को मरवा दिया गया है, दो आदमियों के हाथ टूटे हैं, तीन आदमियों के सिर फूटे हैं, दो स्कूटर जलाए गए हैं, एक मोटर साइकिल जलाया गया है। सब से ज्यादा अफ़सोस की बात तो यह है कि इन तर्कों को पुलिस की सपोर्ट है। 29 फ़रवरी को वहाँ मर्डर हुआ। मैं 17

मार्च तक हैदराबाद में था। उन में से 4-5 को ही तब तक ऐरेंट किया जा सका था। इससे साफ़ मान्य होता है कि पुलिस वालों की मदद से यह सब हुआ है। हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट पुलिस श्री पर्वदा रेड्डी, वहाँ के पुलिस स्टेशन के सब इन्स्पेक्टर श्री दामोदर रेड्डी आदि की मदद से वहाँ ये सब कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इस की तरफ़ मैं प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का ध्यान आकर्षित करना हूँ और उन से तथा होम मिनिस्टर से प्रार्थना करना हूँ कि इस की तरफ़ पूरा ध्यान। मैं उनको इसके संबंध में लिखने भी वाला हूँ। तो वहाँ ऐसी चीजें हैं, इनसे बहुत ही मर्डर वहाँ होने वाले हैं। इनकी तरफ़ ध्यान देने की जरूरत है।

एक बात की तरफ़ मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वहाँ नेशनल पुलिस अकादमी है, उसके कुछ अधिकारियों की गलती से प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा जी का और दूसरे सरकार के लोगों का नाम खराब होता है। वहाँ गांधी आश्रम है, मैं गांधी आश्रम का ट्रस्टी हूँ। ये नेशनल पुलिस अकादमी वाले वहाँ दूसरों की ज़मीन से कड़ी गाड़ देते हैं और अपने बढ़क वाले सिपाही लेजाकर खड़े कर देते हैं। इस तरह की बातें वहाँ हो रही हैं, मैं चाहूँगा कि सकी इन्वैस्टिगेशन करवाये।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ।

SHRI K. MAYA THEVAR (Dindigul).  
 At the outset, I congratulate our Finance Minister for the Budget he has presented before the country. I call it a realistic budget with imagination and deep insight. The budget tries to take into account the real feelings and aspirations of the people. Through this budget an attempt has been made to give a shape to the expectation of our country. Determination is explicit and direction clear. Even I can call this budget as a breakthrough budget.

[Shri K Mayathevar]

Unlike previous budgets this one has a clearcut departure from the traditional and conventional one. I agree with the Minister that this budget is growth-oriented. This is the first time that the majority of the people have welcomed the budget with satisfaction. The common man is considered and not crushed equally the rich man is seen but not touched!

The Finance Minister is confident that the increase in the plan outlay will not affect the stability of prices. I wish it must be so. But I have read his speech at the Governor's Conference which created in me a bit of apprehension. Let me quote

The Finance Minister Mr C Subramamam warned today that if the massive plan investment funds of over Rs 7800 crores were not properly utilised the economy might face inflationary tendencies

This apprehension was reflected in his budget speech also. He said

It would be a grave mistake to take price stability for granted. If we are not vigilant inflation will raise its ugly head again.

Now far his confidence is going to help in thwarting the inflationary spiral is to be seen. But one thing all must and will agree that the pull that has been the order of the day is being gradually replaced by a sort of vibration. Partial holiday declared might be out of compulsion for political activity and in a way it accelerated the tempo of economic activity. This does not mean that I wish a permanent holiday for political functioning. I am sure that if political activities of parties are properly streamlined with the sense of determination and dedication the 20-point economic programme of our Prime Minister can be effectively implemented. The 20-point programme of the Prime Minister is a programme of the people of this country. Hence

we must take the people along with us and see that they are involved emotionally. Programmes are announced with purpose. I can say, Sir, that our Anna DMK Party in Tamilnadu and elsewhere throughout the country as instructed by our revolutionary leader, MGR, has organised district level and State level all-party committees for effective implementation of the 20-point programme of our beloved Prime Minister.

The cry of the country must be "speed—speed and speed". As our Finance Minister has rightly pointed out the role of the Finance Minister is not that of a mere gatherer; he has also to provide relief selectively when any section of the industry or the consumer is in serious difficulty. No doubt he has given relief to common man in many ways. I welcome these measures.

As regards refrigerators (medium) and television sets they are not at all considered luxury items. With the march of time tastes change, tastes change and concepts also change. These are all inevitable and unavoidable items. Care must be taken to see that these articles are within the reach of the common man, poor class and the middle class.

The prices of many commodities have come down after the emergency but the prices of petrol have not been reduced. So I would like to request to the Government to take effective and immediate steps to reduce the petrol prices for the good of the common man as well as the middle class people.

It is welcome that the very theme of the budget is sufficiency for all and superfluous to none. After the announcement of the Prime Minister's twenty-point programme another four-point programme of young and energetic youth of the nation, Mr. Sanjay Gandhi, has come. Any patriotic citizen of this country can offer his or

her programmes for the use of the country. To revitalise, reactivate, restructure, regenerate and to reconstruct the economy of the country maintaining political stability are very welcome suggestions.

I have got some programmes and suggestions to offer for the consideration of this House and the country. Firstly, there is a whispering campaign going on as if the future Prime Minister is being groomed. I suggest that such a useless and meaningless talk must be stopped. Let me be frank, if the wish of the country is for that choice nobody can stop it. It is for the people to elect and select suitable Prime Minister in future. Our Prime Minister, Smt. Indira Gandhi, is hale and hearty and has proved to be one of the most influential, able and efficient Premier of the country and we wish her a life of more than 100 years to serve the country. Moreover our country is not only safe and happy but also very strong at the hands of the present Prime Minister. So, it is not only unnecessary and unwarranted under the present state of circumstances to talk about future Prime Minister but also such whispering talk is premature.

Then I come to the next point about ceiling on age for politicians and statesmen. The ceiling should be introduced in the Constitution itself. Now, I would like to say a few words on the agricultural labourers and poor farmers in the rural areas. They are the backbone of the rural economy. They are the feeders of the country but they are born in debt, live in debt, die in debt and bequeath debt to legal heirs. So, the Government should redeem them from their perpetual and permanent poverty and provide them more and more employment opportunities by paying cash subsidy and also starting agro-based industries in the rural areas. Out of 365 days they are employed only for 150 days and for the rest of the days they are absolutely unemployed. So, Government must

bring forward certain practical measures to safeguard the interests of the poor farmers.

One more point regarding the handloom industry and handloom weavers. We are all aware that the weavers have not been protected economically, for a long time by the Central Government or the state governments. I do not say, absolutely unprotected; they are protected to a certain extent but not to the extent that they require protection. Therefore, I suggest that the Government should have some weavers' centres. Even in my own constituency in Tamilnadu there are one or two weavers' centres but one or two will not meet their requirements and the government should start more weavers' centres to protect their interests. These interests should not be affected adversely by technological and scientific advancement.

Now, the final point, the last point. The weavers are now at the mercy of master weavers. Government should redeem them from the tyranny of the master weavers, from their clutches. In a democratic government the voters, the electorate should be given the right to recall an MLA or MP if their performance is disappointing and if they do not fulfil their promise. Finally, one sentence, with regard to ladies. We are having the personality of the Prime Minister of India; nobody can compete with the Prime Minister. Therefore I request the Government and the Prime Minister and this House also that 25 per cent of the seats of MLAs, MPs, Ministers and other offices should be set apart for the ladies. With these words, I conclude my speech.

श्री सतपाल कपूर (पटियाणा) :  
उपाध्यक्ष महोदय, एगजेंसी के बाद जो हथारी  
देश में एक बानावरण पैदा हुआ हर बीघ  
की प्राइमरी मिरी उस का इन बजट से महारा  
तास्तुक है और यह पहली बार है आजादी

**[श्री सतपाल कपूर]**

के बाद कि बजट धाने के पहले मार्केट से चीजें गुम नहीं हुईं, नहीं तो हर साल हम देखते थे कि बजट धाने से पन्द्रह दिन बीस दिन पहले चीजें गुम होने लगती थी और तीन चार दिन पहले तो मार्केट में कोई चीज मिलती नहीं थी। लोगों को ऐसा होता था कि पता नहीं किस चीज पर टेकम लगने वाला है किस चीज पर नहीं लगने वाला है। यह फास्ट टाइम है कि बजट धाने के समय जो एक आम तौर पर टेंशन देखा जाता था सोसाइटी में वह गैरान इस साल नहीं था। बजट धाने के बाद यह कहा जा सकता है कि किसी को कम रियायत मिली किसी को ज्यादा रियायत मिली लेकिन स बजट से कोई इंटेंट नहीं हुआ। मैं समझना हुआ काफी सीरियस प्रटेन्ट है।

मेरा अपना ख्याल है कि प्राइवेट-सेक्टर को एक मौका मिला है। अब तक प्राइवेट सेक्टर को मिलने मौके मिले हैं हिस्ट्री यह साबित करती है कि उन्होंने बिहेव नहीं किया। जितना हम ते उन को प्रायं बढ़ाने की कोशिश की जितने उन का कमेन्स दिए उनसे उन के ऐटाल्यूड में कोई फर्क नहीं आया। इस बजट में भी उन को कुछ कंसेशन दिए गए हैं और मैं उम्मीद करता हू कि इस देश का प्राइवेट सेक्टर जो शानत देश में है और जो सामथर एक्स्ट्रान गवर्नमेंट कर रही है इन हानत को पेजे नजर रखने हुए ज्वाइ करेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर बिहेव नहीं करेगा तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए। हतना ही मैं कहना चाहता हू कि जो कमेन्स दिए गए हैं वह इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर अपना ऐटाल्यूड जो उन की हिस्ट्री रही है उस में बदलेगा और अपने रास्ते को बदलेगा।

एक बहुत बड़ी बात इस बजट में की गई है जिस की बहुत बड़े बड़े जो हमारे फाइनेंसियल एक्स्टेंस है वह भी उम्मीद

नहीं करते थे कि 31 परसेंट हू ब्लान का खर्चा बढ़ाए। यह एक बहुत बड़ी प्रोब्लेम है और बहुत ऐम्बीगस बात है। हू की हमें तारीफ करनी चाहिए और मैं इस की पूरी तरह तारीफ करता हूँ। बड़ी बारी प्रटेन्ट की गई है। मुझे बूद भी उम्मीद नहीं था। मेरा संदावा था कि 20 वा 25 परसेंट बढ़ाएंगे। 20 परसेंट, भी मैं समझना था कि सायद पासिबल न हो कि हम प्लान का खर्चा बढ़ाए। 31 परसेंट जो किया है वह एक बिन प्रोब्लेम है—इसके लिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नमेंट को बधाई देना चाहता हूँ।

एक बात मेरी समझ में नहीं आई। एक तरफ हमारा ऐटाल्यूड एग्जैक्यूटिव को डेवलप करने का है और दूसरी तरफ एग्जैक्यूटिव को प्राइवेट डाउन जा रही हैं। हम मार्केट में एन्टर नहीं हो रहे हैं। गूफर्नमेंट की प्राइवेट काउन की प्राइवेट डा न हुई है, बाली और प्रायल मीडस की प्राइवेट डाउन बई है और व्हीट की प्राइवेट भी डाउन जा रही है। इस मान जो टार्गेट रखा है, जो संदावा लगाया गया है फूड प्रोडक्शन का वह 115 मिलियन टन है जबकि प्रोडक्शन 106 मिलियन टन का था और 102 या 103 मिलियन टन आम तौर पर होता था लेकिन इस साल जो प्रोड्योमेंट टार्गेट रखा गया है वह मात मिलियन टन और साथ ही इन्वोर्ट का टार्गेट भी रखा गया है। ऐनी हालत में मैं नहीं समझता कि जब हमारे पास प्रोडक्शन है, प्राइवेट डाउन जा रहे हैं तो फिर आप प्रोड्योमेंट 15 मिलियन टन क्यों नहीं करते। ऐसे हालात बंदा करना हम देश में निम्न किसान महसूस करे कि सरकार हमारी पूरी तरह से हमारा नहीं कर रही है और उनको एक बेचारी की हालत में रखना मेरे ख्याल से बहुत गलत होगा। इस इन्वोर्ट में हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी ठेक है, स्टेट बवर्नमेंट्स भी काफी इन्वैट है, प्रोडक्शन भी है, किसान

देना भी चाहते हैं फिर क्या मजबूरी हो सकती है। पिछले सालों में आप किसानों पर लेवी लगाते थे, सपोर्ट प्राइस देने थे, बोनस देते थे फिर इस साल 105 रुपए में प्रोक्योर करने में क्या दिक्कत आ रही है और इम्पोर्ट करने में क्या सङ्कलियत मिल गयी है—यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इस बारे में जो हमारी पालिसी है उसको हमारी एग्री-कल्चरल प्राइस कमिशन समझे और जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में हमारे एक्सपर्ट्स हैं वह समझें। मैं इनमें कोई कम्प्यूजन नहीं समझना बल्कि में समझता हूँ जान बूझ कर किसानों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। मैं समझता हूँ हमारी प्रोक्वोर्मेंट पालिसी को लेज करने की जरूरत है। हम 15 मिलियन टन का प्रोक्वोर्मेंट कर सकते हैं। एक तरफ एग्रीकल्चरल प्राइस में डाउन जा रही है, व्हीट और दूसरी चीजों की प्राइस डाउन जा रहे हैं और दूसरे तरफ बिजली के रेट बढ़े हैं, ट्रैक्टर की प्राइस में बढ़ी है। मैं नहीं समझना किम तरह से बजट में पहले फरवरी में ट्रेक्टर के बॉम्बूकैन्वर्शन ने ट्रेक्टर के दाम बढ़ा दिए और टैरिफ कमिशन ने उनको क्यों इजाजत दी जबकि कोई नये टैक्स नहीं लगाए गए। 7, 8 और 10 हजार रुपए तक बढ़ा दिए गए। टैरिफ कमिशन ने उनको कैसे एप्रूव कर दिया। टैरिफ कमिशन में ऐसे लोग बैठे हैं जो उन लोगों की नुमाइन्दगी करते हैं और जो किसानों के दुश्मन हैं। वे लोग कभी नहीं सोचते कि कौन्सिलिट्रेशननेम में फायदा उठा रहे हैं, बेजा कीमतें बढ़ा रहे हैं जिसे किसानों का नुकसान हो रहा है। एलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेंस बढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनपुट्स में आपने एक रिस्किफ देने की कोशिश की है फर्टिलाइजर के दाम कम किए हैं लेकिन इनटर्नेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर की प्राइस में डाउन गई हैं। जबतक बड़ा प्राइसेज डाउन नहीं हुई आपने कम करने की बात नहीं सोची लेकिन जब इन्टरनेशनल मार्केट

में प्राइसेज डाउन हुई तो आप जो सब्सीडी दे रहे थे वह निकालकर कॅम्पत घटा रहे हैं। इसमें थोर थो कीमत घटाई जा सकती है और किसानों को बचाया जा सकता है। अगर एग्रीकल्चर को बचाना है, एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री की तरह से चलाना है तो फिर आपकी एग्रीकल्चर के बारे में एक फूनड्रूफ पालिसी अपनावानी होगी। इनपुट्स, प्रोक्वोर्मेंट, इश्य प्राइस जिन्से कस्टमर्स को दिना है—इन सारी चीजों के लिए एक फूल—फूल पालिसी बनानी होगी जोकि आज नहीं है।

15.00 hrs:

एक बात मैं खास तौर से इन मीके पर कहना चाहता हूँ—हमारे यहाँ देश में कुछ ऐसे रिस्कोर्सेज मोबिलाइज किये जा सकते हैं जिन से खर्चा कम हो सकता है और आमदनी बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पर—रिवर ट्रास्पॉर्ट—कोलीजिये। हमारे देश में रिवर ट्रास्पॉर्ट मिस्टम दुनिया के दूसरे मुलकों के मुकाबले सब में कम है—रोड ट्रास्पॉर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट दोनों ज्यादा कास्टवो है। अगर हम अपने रिवर ट्रास्पॉर्ट मिस्टम को इस ढंग में डेवलप करे, उस में 25-30 करोड़ रुपया लगा दे, तो देश में एक नया इन्कनाब ला सकते हैं। रिवर ट्रास्पॉर्ट मिस्टम रोड ट्रास्पॉर्ट के मुकाबले पाच गुना सस्ता होता है। इस लिये मेरी दरखास्त है कि इस की पोसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जाय।

जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है—मैं समझता हूँ पंजाब के साथ इन्साफ नहीं किया जा रहा है। हमारे यहाँ न कोई इंडस्ट्री लगाने की कोशिश की जा रही है और न हमारे इन्टर-स्टेट डिम्बूटम, जैसे बिजली और पानी, को हल करने की कोशिश की जा रही है। एक फिजा—सी सारी दुनिया में बनी हुई है कि पंजाब बहुत धाने है, इस को पीछे करने की जरूरत है...

को जी० एच० टिक्करी (खोपसबज) :  
पीछे क्यों किया जाय, दूसरे लोग यहाँ जाय  
उन को भी मौका मिले ।

श्री सतपाल कपूर : भ्राप चले जाइये,  
बहुत खुशी की बात है, लेकिन मुझ पीछे तो न  
किया जाय । यू०पी० और बिहार के लोग  
भ्रार भ्रपने यहाँ मेहनत कर लें तो फिर  
प्राबलम ही न रहे । इन की मेहनत करने  
की भावत नहीं है, उस की मजा हम को  
मिलनी है । पंजाब की प्राबलम की तरफ  
नैन्ट्रल गवर्नमंठ को पूरी हमदर्दी बरतनी चाहिये ।  
हम देश को व्हीट, राइम, ज्वार देते हैं,  
मुत्क की हिफाजत के लिये ज्वान देते हैं ।

श्री शिवनाथ सिंह: (मंजुनु) उपाध्यक्ष  
महोदय, इस साल जो बजट पेश हुआ है,  
बहु काफ़ी चतुराई से पेश हुआ है । इस बजट  
के द्वारा समाज के किसी भी सँकशन को यह  
कहना का भ्रवसर नहीं दिया गया कि हमारे  
ऊपर ज्यादाती हुई है और न ही कोई सँकशन  
ऐसा कह सकता है कि हमें छूट मिल है ।  
इस बजट में बहुत सी खूबियाँ हैं—जैसे  
फिक्सड सैलरीज वालों को इन्कम टैकम के  
स्लैब में 2 परसेन्ट की छूट दी गई है ।  
इसी तरह में डायरन्ठ और इन्डायरेक्ट  
टैकमेज में कई तरह के रिलीफ दिये गये हैं ।  
इस वर्ष बजट भ्राने से पहले देश में कहीं भी  
प्राइस में फलकचुएशन नहीं हुआ और एक  
अच्छा बजट हमारे भ्राने रखा गया ।  
इस लिये हम सब इस बजट का स्वागत  
करते हैं ।

लेकिन मैं भ्राप से एक निवेदन करना  
चाहता हूँ—हम जब इस बजट के सम्बन्ध  
में कुछ सझाव दें तो उस का मतलब  
क्रिडसिज्म नहीं समझना चाहिये । हमारे  
वित्त मंत्री जी प्राइवेट सैक्टर पर बहुत बड़ा  
बिश्वास कर के चले हैं और वे कहते हैं कि

मैं प्राइवेट सैक्टर को कुछ-कुछ केना च्चलता  
हूँ—प्राइवेट टैकमेज में, इन्डायरेक्ट टैकमेज  
में या एक्सिज की क में, लेकिन मैं उन से  
यह उम्मीद करता हूँ कि वे इन चीजों को  
बुडिट में रखते हुए ठीक तरह से रिपैक्ट करेंगे ।  
मैं उन से निवेदन करना चाहता हूँ—प्राइवेट  
सैक्टर बड़ा बचमाश है, वह कभी भी बिना  
हण्ड के भ्रानेवाला नहीं है, उस पर बिश्वास  
कर के चलना हमारे देश की इकानामी के  
साथ बहुत बड़ा खिलबाड होगा । उस को  
सञ्जी के साथ डील करने तो ठीक हो जायगा,  
यदि सञ्जी नहीं करेंगे, उस पर बिश्वास करेंगे  
तो वह ठीक रिपैक्ट नहीं करेगा । भ्राम  
स्मगलर्स को लीजिये, जो लोग टैकमेज का  
इस्तेजान कर रहे थे, उन में भ्राप ने बहुत भ्रपीलें  
की लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला,  
लेकिन जैसे ही भ्रा । ने सञ्जी की, दो महीने  
के भ्रन्दर सारा घन सामने भ्रा गया । इस  
लिये इन को कभी छूट नहीं दी जानी चाहिये ।  
पिछले दो सालों में हम देख रहे हैं—ग-  
मैटीरियल क प्राइस बहुत गिर गई है, लेकिन  
इन लोगों में फिनिश्ट गुड्स की प्राइसेज  
कम नहीं होने दी । भ्रभी भ्राननीय सदस्य  
श्री तनाल कपूर टैक्टर का बिक्र कर रहे  
थे । बार-बार साल पहले टैक्टर की कीमत  
28 में 30 हजार रुपये थी, लेकिन भ्रव  
55 हजार रुपये का बिक्रता है, जब कि भ्राप  
ने उस के ऊपर कोई टैकम नहीं लगाया है,  
उन को फिक्सड प्राइम पर स्टील देते हैं,  
उनकी सेबर ट्रबल को एकीएड कर दिया  
सब कुछ होने के बाद भी उन को इस तरह  
से प्राइम बढ़ाने की छूट मिली हुई है ।

इस लिये मेरा निवेदन है कि इन के  
साथ सञ्जी बरतिये । भ्राप ने जो छूट भी  
है—12 महीने देख लीजिये, लेकिन मेरा  
ऐसा ब्याव है कि भ्रान्त में भ्राप को सञ्जी  
भ्रानिमी को बिहार से रिवाइज करना पड़ेगा ।

हमारे बजट में हर साल नये टैक्स लगते हैं, नई प्राइट्स को टैक्स-बैंज में लाया जाता है, उन के क्षेत्रों में प्रॉव्हीन्ट्स दिये जाते हैं। कोई टैक्स हटाना पड़ता है तो उस के लिये प्रॉव्हीन्ट्स दी जाती हैं। मेरा निवेदन है कि हमारी कोई स्पेसिफ़ पासिसी नहीं है। पिछली बार हम ने बैंकों की ब्याज की आयवनी पर टैक्स लगाया था और इस के पक्ष में एक बहुत बड़ी प्रॉव्हीन्ट यह दिया गया कि बैंक ब्याज में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, इस लिये उन पर टैक्स लगाना जरूरी है। और अब की बार उन को छूट दे दी गई है कि लीग टर्म बेसिस पर जो लोग इंस्टीट्यूट को देंगे उस पर टैक्स नहीं लगायेंगे। बजट भाषण में कहा जाता है कि लखरी प्राइट्स को टैक्स करना चाहिये, गराब को टैक्स करना चाहिये, और बंकि कायतकार की इन्कम भी बढ़ गई है इसलिये फिटिलाइजर को भी टैक्स करना चाहिये। लेकिन दूसरी मान ही आप कहते हैं कि इन चीजों पर से टैक्स हटाना चाहते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट मर गई हैं। बिडला का हिन्दुस्तान मोटर्स का कारखाना है जहां एम्बेसेडर गाड़ी बनती है। अगर वह इंस्टीट्यूट मरती भी है तो उस से देश को कहां नुकसान हो गया? लेकिन यह कह कर कि वह उद्योग मर रहा है इसलिये उस को 5 परसेंट की छूट दे दी गई। दूसरी तरफ़ पम्पिंग सैंट, जिस को किसान इस्तेमाल करता है, उस पर प्राप टैक्स माफ़ नहीं कर रहे हैं। यह कहां का न्याय है? बड़ी बड़ी मोटर क्रीकटियों का प्राज मार्केट नहीं है इसलिये टैक्स रिवाफ़ देना चाहते हैं, और जो चीजें किसान काम में लाता है उपज बढ़ाने के लिये उन को प्राप रिवाफ़ नहीं देते। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमारी एक निश्चित पोलिसी होनी चाहिये कि हम किस प्रकार की इकोनामी को बढ़ावा देना चाहते हैं। आज हम इस स्थिति में आ गये हैं कि हमें एक तरह की पोलिसी तय करनी चाहिये।

आप ने टैक्स में जी रिवाफ़ दिया है उस से गरीब और मिडिल इन्कम के लोगों को लाभ मिला है, लेकिन मेरा निवेदन है कि इन रिवाफ़ के सब से अधिक लाभ बड़े पैसे वालों को मिला है।

एक बात में ऐग्रीकल्चर इकोनामी के बारे में कहना चाहता हूँ। आज हमारा देश अनाज के मामले में सेल्फ़ सफिशियेंट ही नहीं है बल्कि इस स्थिति में आ गया है कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अनाज का हम अतुल भंडार बना सकते हैं। इस बारे में वित्त मंत्री को देखना चाहिये या कि हमारे पास अन्न भंडारों की क्या व्यवस्था है। अनाज खरीदने के लिये आप एक० सी० आई० को कितना पैसा दे रहे हैं। वह किमान का पूरा अनाज नहीं खरीद सकता। किमान के पास जो अनाज है उस को खरीदने की हम ने क्या व्यवस्था की है? बार-बार स्टेटमेंट आते हैं कि किसान के अनाज की कीमत गिरने लगी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि गेहूं की कीमत 105 रु० प्रति किबंटल से नीचे गिर रही है। इसी तरह से काटन की, आयल सीडस की और जूट की कीमत भी नीचे है। आप कहते हैं कि किसान की प्रोड्यूस को मपोर्ट प्राइस से नीचे नहीं गिरने देंगे, लेकिन जो यह रहा है कि उस प्राइस से नीचे पर भी कोई खरीदने वाला नहीं है। इसलिये आप के बयानों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। आप को इस बारे में ठोस कदम उठाने होंगे और खरीद के मामले में पैसे की कमी को सामने नहीं आने देंगे। मेरा निवेदन है कि आप को इस बारे में ध्यान देना चाहिये।

एक बात किसानों के बारे में और कहना चाहता हूँ। डिबिटेंड बनकर आप ने फ़ीज किया। मेरा निवेदन है कि अगर आप के पास किसान को देने के लिये पैसा नहीं है तो आप किसान को बीडस दे दीजिये और और उस की वेजेन्ट बाह 12 महीने बाह

## [ श्री विपनाथ सिंह ]

इंडस्ट्रिज के साथ कीजिये और इस तरह उस का भनाय बड़ीजिये । किसान इस आधार पर भी राजा भनाय देने के लिये तैयार है, और वह इलिये तैयार है कि कम से कम उस को 20, 25 रु० प्रति किबंटल का बाटा तो रही उठाना पडेगा, जो कि अभी उस को हो रहा है । आप उन को बीडम दे दीजिये, किसान उन को लेने के लिये तैयार है ।

आप ने गृह लक्ष्मी के नाम से पहले बीमा योजना निकाली थी । आज भी वे बकिंग क्लास के लिये बिना पैसे के बीमा योजना निकाली है । हम इस का स्वागत करते हैं । लेकिन साथ ही आप को बरल सैक्टर की ओर भी देखना चाहिये । हाथकार और गांवों में रहने वाले लोगों के लिये भी कम से कम 2,000 या 5,000 रु० के आवश्यक बीमा की योजना भी आप को चालू करनी चाहिये । इस योजना का प्रीमियम रेट का कम रख कर देहानी क्षेत्र में इस को बढ़ाना चाहिये ।

हमारा बहुत बड़ा अनदेवलपड क्षेत्र है जहां रेगिस्तान है । उस के अन्दर पीने के पानी की बहुत कमी है । राजस्थान के नाल स्कीम को त्दी पूरा करना चाहिये, और जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है वहां उस का इंतजाम भी आप को करना चाहिये । साथ ही आप को बेलफेयर ऐक्टिविटीज की तरफ भी ध्यान देना चाहिये । आप को देखना चाहिये कि गांवों में कितने व्यक्तियों के पीछे एक डाक्टर है, कितने अस्पताल हैं, पीने के पानी की कितनी सहुलियत है । इन बातों का भी बजट में संकेत होना चाहिये । जो कि अभी तक नहीं हो पाया है । अगर स्पेशल सर्विसेज को आप नहीं बढ़ाविये तो जो मिडलान्ट हम से कर चले हैं कि समाज को ऊपर उठाना, गरीबों को ऊपर उठाना है, उन को राहत पहुंचानी है, वह उन को नहीं मिल पायेगी ।

प्रधानमंत्री का 20 सुजी प्राथिक कार्यक्रम सफल हुआ है और बहुत से लोगों को हाउस साइटस और भूमिहीनों को कायत के लिये जमीनों दी गई हैं । ऐसी क्लस्टर सैक्टर में भी बहुत बड़ा काम हुआ है, जैसे अण्डा बीज आपने दिये हैं, किसानों की क्रेडिट फ्रेविलिटीज को भी बढ़ाया है । इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा देश इतना बढ़ा और विशाल है कि यह सब सुविधायें समुद्र में बूद के समान हैं, और इस लिये कायतकार को कहना पडता है कि हमारे लिये कुछ नहीं हुआ है । वास्तव में यह जो आप ने किया है, उन की समस्याओं को देखते हुए बहुत कम है । आज देश में एक भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जोकि लोन लेना चाहे, उस को पूरा लोन नहीं मिल सके । लेकिन एचि क्षेत्र के अन्दर एचि परसेन्ट लोन की डिमान्ड को ही आप भीट आउट नहीं कर पाये है । इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि जो माजिनल फारमर्स हैं, बिग फारमर्स है या आप के छोटे फारमर्स है, जो कि उत्पादन बढ़ाने में सहायता देने है, उन की आप मदद करे और मार्केट फेवेलिटीज, क्रेडिट फेवेलिटीज और स्टोरेज फेवेलिटीज अगए आ । उन को देते हैं, तो समुचित विनाम हो पाएगा ।

इस शब्दों के साथ मैं बजट का भर्षन करता हूँ ।

श्री राज सहाय पांडे : (राजर्षद गांव) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट का एक ऐसा अवसर होता है जब हम देश की गिर्षित का, आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं और पिछले वर्ष और इस वर्ष को तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं ।

पिछले वर्ष का बजट बड़ा निराशापूर्ण था और कभी कभी इतिहास में ऐसा समय आता है जब कि निराशा के दिन देखने पडते हैं । उस का लाभ राजनीतिक दलों ने बहुत निया और प्रधानमंत्री



जी के कथनानुसार वी इस हद तक चले गये थे कि निराशा और अन्धकार का वातावरण उन्होंने उत्पन्न किया था और एक ऐसा प्रयास किया था कि उस से हम उभर न सके। उन का यह प्रयास था कि देश में विकास की गति न आए, एक आशा की किरण न बंधे। मूरज डूब सा गया था श्री गंगा वे दिखाते थे कि वह उदय नहीं होगा, लेकिन थोड़े दिनों के अन्दर कुछ प्रकृति ने सहायता की और कुछ समाज ने सहायता की और ऋषि उत्पादन बढ़ा, जल की वृष्टि हुई और निराशा का वातावरण दूर हुआ और आशा की किरण फूटी और आज अधिकांशपूर्वक यह कह सकते हैं कि अपने देश की जिम् गति में समाजवाद की ओर ले जाना चाहते हैं और अपने उद्देश्य की प्रति करना चाहता है, उस को उस तरफ ले जाने में हम मर्मथ हैं। इस लिए श्री सुब्रह्मण्यम्, प्रणव कुमार मुखर्जी और उन मन्त्रालय ने नमाम कर्मचारी और अधिकांश, सभी उस प्रकृतिकल एकांश के लिए, इस प्रत्यक्षदर्शी होने के लिए बधाई के पात्र हैं। आप ने उन ममम्याओं की तरफ बड़ी गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया और आयोजना में 31 परसेन्ट वृद्ध कर 7,652 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और इस तरह से देश को आश्वस्त किया है कि इस वर्ष 1976-77 में पिछले वर्ष के मुकाबले में हम 31 प्रतिशत और विकास की गति बढ़ायेंगे।

श्रीमन्, हमारा देश खेतिहार देश और प्रायः हम सभी लोग खेतिहार लोगों के बोटी में इस सदन में आते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि विकास की गति में हम उन्हें स्मरण करें। इस अवसर पर जबकि सर्वोच्च सदन में हम बजट की बातें करते हैं, आप ने उरवकों

के दाम कम किये हैं। इनपुद्स की कीमतों में कमी करने की दिशा में आप ने सब से पहले फाटिनाइजर्स को लिया है और इनपुद्स में जितनी उन के काम में आने वाली चीजें हैं, उन की तरफ ध्यान दिया है और उन को प्रोत्साहित किया है और साथ ही साथ इस के उत्तर में उन्होंने भी यह बताया है कि हम 114 मिलियन टन अनाज आप को पैदा कर के देंगे। इस में बकर स्टार्क भी बनेगा और भविष्य के बारे में जो एक निराशापूर्ण स्थिति रहती थी कि पाइपलाइन के लिए हमें अनाज चाहिए, वह भी समाप्त होगी। इस तरह में बकर स्टार्क बनाने का उन्होंने आप को अवसर दिया है।

श्री मनपाल कपूर ने अभी कहा था कि मपोटिंग प्रादम में उन को घाटा रहता है। आज जो किसान पैदा करता है, उस को लेने के लिए आप ने 105 रुपये क्वीटल गेहू का भाव रखा है और जैसा कि अभी किमी साहब ने कहा है कि उसको 110 रुपया कर देना चाहिए, मैं भी ऐसा समझता हूँ कि अगर इतना पैसा उन को दिया जाता है तो आज विकासोन्मुख गति लाने के लिए यह कोई अनुचित बात नहीं होगी।

किसान अगर कोई बात कहे तो उसको हमें गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए। मैं सुब्रह्मण्यम् जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रोक्सोरमेट प्राइस को वह पांच रुपये बढ़ा दें, इसको 105 में बढ़ा कर 110 कर दें। आपने किसान का आह्वान किया है। आपने कीमत बढ़ा दी तो किसान बोचें कि आप भी हमारी सहायता करते हैं और उसको भी परिश्रम करके और ज्यादा पैदा करके आपको देना चाहिए। जब उसकी प्रोड्यूस की प्राइस कम होती है तो

### [बी रात सद्भाव पाठ]

इसका उसको दुःख ही होता है। मैं आशा करता हूँ कि इस धीरे धीरे ध्यान देने से।

आप देखें कि प्रथम व्यवस्था का निर्माण कहाँ से होता है? धरती से होता है, जमीन से होता है। इस वास्ते लैण्ड रिफार्म की धीरे धीरे नीत सूची कार्यक्रम में जो ध्यान दिया है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। भूमि सुधारों की प्राथमिकता दे कर आपने उचित ही किया है। भूमि सुधारों के माध्यम से जो हमारा ध्यान सर्वहारा समाज की धीरे गया है उसके लिए आपकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जिन हाथों में धातु हल नहीं है, जमीन नहीं है, कोई माधन नहीं है, उनको धरत भूमि मिल जाती है तो इनसे प्रच्छा धीरे तथा काम हो सकता है। लैंडरिफार्मिंग का साथ साथ

In one booklet you have mentioned about the infra-structure, how the agriculture is to be built, developed and improved.

आपने इनको पांच श्रेणियों में बाटा है। इस में आपने तकनीकी ज्ञान की बात कही है। हाई ब्रिड फर्टिलाइजर, हाई ब्रिड मोडर्न आदि की बात कही है। उनमें आपने जागृति पैदा करने की कोशिश की है और जागृति पैदा करने के लिए ज्ञान देने की बात कही है। हमारे खेती करने का जो ढंग परम्परा में चला आ रहा है और उस में हमने कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं किए हैं, इस में धरत उनको तकनीकी ज्ञान करवा दिया जाएगा तो इसमें किसान को भी फायदा होगा और हमारी उपज भी बढ़ेगी। सायल के परीक्षण, अनुसन्धान की, एक्सप्टेशन नकिड की बात कही है जो उपयुक्त ही

है। एक्सप्टेशन कार्पोरेशन को एक्सप्टेशन सचिव से जोड़ देने का साथ यह हेतु कि पता चल सके कि किस जिले में क्या पैदा करने में फायदा है, पैदा ब्रिड क्या पैदा करने में फायदा है। पंजाब में बावल का उत्पादन बढ़ा है। वहाँ पांच हजार वीराइटीज के एक्सप्टेड किए गए हैं। इसको मैं शुभ सज्जन मानता हूँ और इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। पंजाबी बड़े बहादुर होते हैं, ताकतवर भी होते हैं। बुद्धि के सम्बन्ध में दूसरी बात कही जाती थी। लेकिन धरत उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि .

Punjabis are not only brave  
but also wise people

मैं यह भी कहूँ कि इनका स्ट्रक्चर पर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

एक बात कह कर मैं समाप्त कर दूँगा। परिवार नियोजन की तरफ आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। कहीं इससे एक्सप्लोशन न हो जाए। यह भ्रकले आपके बच्चे का काम नहीं है। सन् 2000 में हमारी आबादी 100 करोड़ हो जाएगी। आपके बजट और हमारी आबादी को जो आबादी होगी वं कहीं यह न कहें कि हम को भूखो मारने के लिए हम छोड़ गये हैं, सिखमगे बना कर हम को छोड़ गये हैं। धरती जो 44 करोड़ एकड़ है वह तो बढ़ नहीं सकती है। पापुलेशन बढ़ती जा रही है। इसके लिए आपने मत्तर् करोड़ का प्रावधान किया है। इसको आप बढ़ाए, धीरे इन्फिक्टिव स्ट्रेम लें नाकि आपका परिवार नियोजन का कार्यक्रम सफल हो सके।

धरत ने मैं, इतना ही कहना चाहता हूँ कि नीजकार्यों को प्रेरणा देने वाले संजय गांधी को हम भूल नहीं सकते। उन्होंने नैसर्गवादी के सम्बन्ध में धरत रची है

जिन में पेश लगाना और बंधन को बंधित करना भी है। इस प्रकार से तदर्थ समाज को जो उन्होंने आह्वान किया है और युवकों और युवतियों को जगाने का बीड़ा उठाया है इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और उनको बधाई दी जानी चाहिए। यह हमारे देश के लिए एक बहुत ही अच्छा लक्षण है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ और इसको पेश करने के लिए मंत्री महोदय की बधाई देता हूँ। साथ साथ देश ने जो उनका साथ दिया है, श्रमिक वर्ग जो विकास कार्य में जुटा हुआ है तथा दूसरे लोग जो इस काम में उनको सहयोग दे रहे हैं, उनको भी इस के लिए बधाई देना हूँ।

**श्री राज केश सिंह :** (महाराजगंज)  
उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट, जिसकी चर्चा माननीय सदस्यों ने की, जिससे समाजवाद को देश में लाने की बातें ये लोग करने रहे हैं, क्या यह बजट इस दिशा में अग्रसरित करता है? यह बजट क्या है?

यह बजट पूँजीवादी व्यवस्था देश में लाना चाहता है या समाजवादी व्यवस्था लाना चाहता है, क्या यह इस बजट से खुलासा होता है? यह बात समझ में नहीं आती है। यह बजट न नीतर है और न बटेर।

इस बजट में इन्होंने प्रोव्वेंट सैक्टर को छूट दी है और कहा है कि प्रोव्वेंट सैक्टर के लोग इससे उत्साहित हो कर काम करेंगे। आज इस देश का रहने वाला साधारण नागरिक समझता है कि यह जो बजट आया है, यह चुनाव बजट है। इससे आपने प्रोव्वेंट सैक्टर को

इसलिए छूट दी है कि धाने वाले चुनावों को लड़ने के लिए आपको उनसे करोड़ों रुपया लेना है। धाने वाले जिनों में चुनावों पर जो करोड़ों रुपया खर्च होना है, उसका मकैन ही तो यह बजट है जिसमें प्रोव्वेंट सैक्टर को आपने छूट दी है।

आप प्रोग्रेसिव बन रहे हैं और यह कह रहे हैं कि देश की प्रोग्रेस हो रही है। टपीलिए आपने यह प्रदर्शनी की है। आप गेडयो और समाचार-पत्रों से काफी इसका प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं बित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि सन् 1964 और 1965 में जो हम देश में एक व्यक्ति की पर-कैपिटा इनकम थी, वह आज सन् 1975 में बढ़ी है या घटी है। सन् 1964-65 में एक व्यक्ति को जितना कांडा एर्रेनेबल था आज उससे कम कांडा दे रहे हैं या ज्यादा दे रहे हैं?

आप इस बजट की खूबियों का डिंडोरा पीटिये हमकी तारीफ कीजिए लेकिन क्या हम इस बजट में प्रोग्रेस की ओर जा रहे हैं? जब आप एक-एक चीज को धाकते नव ही पना चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं।

एमरजेंसी के बाद पंचवर्षीय योजना को यह सरकार भूल गई। 20-सूखी कार्यक्रम इनके सामने आ गया उसका बडा ही डिंडोरा पीटा जा रहा है, उसकी मरुनता की बडी बडी कहानिया कही जा रही है। लेकिन मैं बित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से कहना कि वह गाव में चल कर देखे कि बहाँ पर 20-सूखी कार्यक्रम कैसे धरती पर उतर रहा है। किमी भी गाव में चल कर देखिए कि इसका उनार कैसे हो रहा है।

**श्री रघुनन्दन लाल नाटिक (धनुसतर) :**  
पजाब में देखिये।

श्री राज देव सिंह : पंजाब में मैं नहीं गया ।

आप कहीं जा कर देखिए, 20-सूजी कार्यक्रम का जो एलोगन है, उसका बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, बड़े बड़े चार्ट लगे हैं और पैम्पलेट दिये जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो प्रौद्योगिक चल रहा है, उसको भी जरा देखना चाहिए ।

हमारे राष्ट्रपिता पूज्य गांधी जी कहते थे कि इस देश के रहने वाले नागरिक बहादुर हों । इस एमरजेंसी के बाद बहादुरी की बात कौन करे, यह सरकार लोगों को कायर और बुद्धिमत् बना रही है । आज सुबह ही यहाँ अध्यक्ष महोदय ने एक रिपोर्ट पढ़ी किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की और बताया कि श्री रामावनार शास्त्री ज्ञाना में सीटिंग करने के लिए गये, उनको वहाँ पर पकड़ लिया गया है । अब श्री रामावनार शास्त्री अपने साथ बम, तोप या पिस्तौल ले कर तो गये नहीं, वहाँ कुछ लोग आते और वह मुँह से बान बोलते, लेकिन उनको पकड़ कर जेल में रख दिया गया । सर्वोच्च सदन का सदस्य जनता के बीच में जा कर अपनी बात नहीं बोल सकता है । यह सरकार इस देश को ले कर कहा जा रही है, कहा तक आ गई है, आप इन एक छोटी सी घटना से इसका अन्दाजा लगा सका हैं । खैर, इन लोगों को छोड़िए या जेल में रखिये, यह आपकी मरजी है, लेकिन इन हाउस के जो सदस्य जेल में बन्द हैं, कम-से-कम उनके बारे में एक बुलेटिन तो हर महीने दे दिया करें कि वह किन्त जेल में हैं और उनका स्वास्थ्य कैसा है, और स्वास्थ्य खराब हो रहा है या नहीं ।

एक माननीय सदस्य . आप बजट पर बोल रहे हैं ?

श्री राज देव सिंह : उपाध्यक्ष जी, आप देखेंगे, अभी एपीकल्चर की बात कह रहे हैं । यह सरकार इस देश को किधर ले कर जा रही है, यही बजट तो उसको गति देगा और दिशा देगा । तो जिस गति से हम चल रहे हैं, उसकी ओर हमने संकेत किया है ।

उहा तक एपीकल्चर का सम्बन्ध है, श्री अजजीवन राम अशरीका में जा कर अनाज की भीख मांगने के लिए तैयार हैं, और अन्न रखा ने वहाँ से सारा अनाज खरीद लिया, तो वह अनाज लेने के लिए रखा ने धाम आयेगे । लेकिन हमारे देश के वृषक अन्ने खेतों में जो पैदा करते हैं, वह उस को खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं और वह उन को उन के उत्पादन की रिम्पनरेटिव प्राइम देने के लिए तैयार नहीं हैं ।

श्री बी० एन० सिबारी (गोडलगज )

शायद माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि श्री अजजीवनराम ने कहा है कि जितना भी अन्न मिलेगा, मैं उस का मगोट प्राइम पर खरीद लंगा । उस के बाद भी माननीय सदस्य का ऐसी बात कहना कहा तक उचित है ?

श्री राज देव सिंह आज कहते हैं कि हम ने फ्रंटलाइजर की कीमत कम कर दी है । जग बताये कि कितनी कम कर दी है । सरकार ने न पम्पिंग सेट की कीमत कम कराई है और न ट्रैक्टर की । पीछे मॉमेंट की कीमत कम से कम 20 परसेंट बढ़ा दी गई है । क्या अन्ध औद्योगिक बस्तुओं की कीमतों और कृषि-अन्य बस्तुओं की कीमतों में कोई संतुलन रह गया है ? सरकार औद्योगिक बस्तुओं की कीमत तो बढ़ाती जा रही है, लेकिन एपीकल्चरल प्रोड्यूस की उचित कीमत वह किमानों को नहीं दे पाती है ।

भाज श्री शाहनवाज खा ने कहा कि किसानों का चार करोड़ रुपये चीनी मिल-मालिकों पर बकाया है। उन्होंने गलत-बयानी की है। गन्ना काश्तकारों की 50 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम मिल-मालिकों पर बकाया है। लेकिन इस सरकार ने मिल-मालिकों से किसानों को वह पैसा दिलवाने के लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं की है।

THE MINISTER OF STATE IN-CHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am very grateful to the hon. Members who have made their observations on the Budget while taking the opportunity of making a few observations on it.

This time, it has been noticed that almost 35 Members have made their observations till now while taking part in the General discussion of the Budget. Only a few of them, including the hon. Member who spoke just before me, have tried to and out certain deficiencies in the Budget. Nobody can claim; neither do we claim that this is a budget where there is no deficiency nor the Finance Minister nor anybody from the Government side, including the Party has claimed that this is an embodiment of perfection, and it has been possible for us to do whatever is needed for the betterment of the economic situation in the country. At the same time, it has been very correctly pointed out by distinguished economists like Dr. V. K. R. V. Rao, who made his observations on the Budget that in a situation like ours the Finance Minister had little option or rather very little space for accommodation to provide a budget on the one hand keeping his eyes on the need of growth and on the other to see that the peculiar economic situation, which has been created as a result of constant demand does not deteriorate further. In view of that, it has been admitted by almost all

the speakers including the distinguished Leader of the Opposition, Mr. Indrajit Gupta, that an increase in the order of 31.6 per cent in the plan outlay would go a long way and would create an investment climate which would ultimately be beneficial for the country.

Now, while making these observations, he expressed his doubt whether the unbridged gap on the revenue side would create further de-establishment factor on the price front. Keeping in view the situation as it is today and the economic disciplines and various measures which we have resorted to, perhaps, we can modestly claim, unless certain extraneous elements come into the picture, it would be possible for us to maintain the price stability, as it is today, and, at the same time, as it has been expressed by the Finance Minister in his speech, by reducing the taxes both on direct and indirect side, the total revenues of the country would not be reduced.

It is no use suggesting that the Budget is for the money bag and that the Budget is full of concessions for monopoly houses. The Budget is an instrument through which the Government tries to control and regulate the economy of the country for the current year and, in this year's Budget also, that exercise has been made. Nothing more, nothing less. Therefore, to categorise it either as a Budget of money bag or a Budget for monopoly houses is, perhaps, incorrect. In fact, by reducing the taxes, various categories of persons belonging to the community will be benefited.

One point has been raised by Shri Indrajit Gupta, that the percentages of reduction of taxes in the lower income group are not adequate while the percentages of reduction of taxes in the upper income group are more. In this connection, I would like to point out one aspect which should be kept in mind. If we come to a com-

[Shri Pranab Kumar Mukherjee]

clusion that taxation is the only instrument of doing away economic disparity, perhaps, it would not be correct. In a developing economy like ours, no doubt, taxation is a very important instrument of doing away economic disparity, but at the same time, there are certain other factors which also contribute for making the desired goal, such as, investment policy, industrial licensing policy and there is no denying the fact that for the last few years, the Government is trying to concentrate on those fronts. Therefore, when certain tax rates have been reduced, it would not be correct to come to a conclusion that we have given up our idea of doing away economic disparities which prevail in the society.

There also, I would like to submit that the basic objective of our taxation system is progression in the rate of taxes. Even in the present tax structure, as it has been pointed out by Shri Indrajit Gupta while making his observations that even on the income tax side he finds some justification for reduction but on the wealth tax side he does not find any justification, I would like to submit humbly and most respectfully that even in the revised rate of taxes on the wealth-tax side—I would quote only two sets of figures—the income derived from wealth and income otherwise are shared equally. In the case of income, at the level of Rs 3,20,000, the rate of tax is 69 per cent; at the level of Rs. 4 lakhs, it is 71.53 per cent; at the level of Rs 8 lakhs, it is 76.59 per cent. When the income is completely derived from wealth alone, at the level of Rs. 2 lakhs, the tax rate is 77 per cent; at the level of Rs. 2,40,000, it is 80.42 per cent and at the level of Rs. 3 lakhs, it is 82.20 per cent.

Some people may be wondering why we cannot have a higher percentage of taxes. Sir, from the experience that we have gained during

all these years, it has been established that a higher rate of tax, at a certain stage, becomes counter-productive; there is no denying the fact. At the rate of tax which prevailed before the revision was brought about by the Finance Minister, it was found that, at a certain level, for income of over Rs. 100, some people had to pay something more than Rs. 100/-. That does create distortion not only in one form but in many directions. That does not mean that if somebody has acquired income or wealth up to a certain level, he does not acquire wealth any more. But what happens is that he does acquire wealth, but that wealth or income is not brought onto the books—as a result of which all such ostentatious and vulgar expenditure is going on. There is no denial of the fact that the operation of black-money which went on and which is still going on in the country is the product, to some extent, of a system like this. Therefore we had to reconsider it and the Finance Minister, in his wisdom, brought out this revision in the rates of taxes.

While making his observations, Mr. Indrajit Gupta had said "well, you have dangled the carrots before the people, but are you going to apply your sticks also?". Sir, the sticks are being regularly applied, I would just like to quote a few figures about the seizures conducted by the Income-tax Department. In February, 1975, the total number of searches conducted were 119 and in February 1976 it was 175; the value of assets in the corresponding period of last year was 116 lakhs while in the current year it is 78.53 lakhs; from 1-4-1974 to 28-2-1975 the total number of searches were 1808 while from 1-4-1975 to 29-2-1976 they were 2068.

Perhaps the Hon. Members will agree with me that during the last one year we have intensified the searches and seizure operations and perhaps they will also agree with me that these

searches and seizure operations were made without any distinction between the persons, whether they were placed in the higher stratum of society or in the lower stratum of society. Our search operations include big newspaper tycoons, political leaders, big industrialists and all sorts of people who tried to indulge in this type of activities, without fear or favour. Our people belonging to the Income-tax Department and the Departments of Customs and Gold Control went on conducting searches and raids and, as some hon. Members have admitted, this is one of the important reasons why the success of the voluntary disclosure scheme had surpassed all our expectations. But, at the same time, it has to be kept in mind as to whether, merely by enforcing the penalty provisions and merely by conducting searches and seizure raids, it would be possible for us to rectify the distortions that have taken place in our economic life. For that, certain economic measures are needed, and these are the economic measures which we have taken

It has been claimed that there will be no reduction in the net revenue. Why are we making such a claim? We are making such a claim because of the fact that, in a country like ours where there are 600 million people, the total percentage of population brought under the tax net is less than one; till today the total number of income-tax assesses is not more than 36 to 37 lakhs of people. Therefore, there is quite a large number of people who are not within the tax net. Last year, as a result of the survey operation which went on, it was found, when two lakh new assesses were brought within the tax net, that quite a number of them belonged to the various professional categories, including lawyers, doctors, chartered accountants and so on and so forth. Therefore, if we can bring within the tax net, those people who

are avoiding taxes, who are not paying their due shares, it would be possible for us to augment our revenue.

Similar is the case with indirect taxes. Before I come to the particular items in respect of which the hon. Members made their observations, I would like to submit one general point for the information of the hon. Members. If we look at the revenue collection of the country just 26 years ago, we will find that in the Budget for 1950-51, the direct tax collection was of the order of Rs. 173 crores and the indirect tax collection, including customs and excise, was Rs. 231.30 crores, thus totalling Rs. 404.53 crores. In 1976-77, the direct taxes have increased from Rs. 173 crores to Rs. 2,152 crores and the indirect taxes have increased from Rs. 231 crores to Rs. 5,738 crores—almost sixty times. This is an area where we shall have to look into further. The Finance Minister has indicated in his Budget speech that, shortly, a Committee is going to be appointed to look into the tax structure of the country and at the same time to suggest certain measures, certain new technique or method which is known as the value-added method which has been accepted by certain developed countries of the world, whether those methods could be applied selectively in this country, and I hope that it would be possible for us to rationalise the tax structure on a more scientific basis; by that way, we will be able to plug the loopholes for evasion and avoidance.

In this connection, I would like to submit another thing for the information of the hon. Members. In the realisation of the indirect taxes, we have already taken some measures for plugging the loopholes for evasion. The SRP Committee had made detailed recommendations; their report has been laid on the Table of the House and the hon. Members are aware of these. Similarly, on the excise tax, on tobacco, the Committee had sub-

[Shri Pranab Kumar Mukherjee]

mitted their report, and we have taken various measures, and certain measures are already under consideration to see that evasion is plugged. At the same time, it should be kept in mind that merely by taking certain enforcement measures certain preventive measures, evasion cannot be stopped completely until and unless they are supported by adequate economic measures. Therefore, the present tax rates proposed by the Finance Minister in both direct and indirect areas, indicate the measures in that direction.

Regarding reduction of income-tax in the lower income bracket, it has been suggested that the incentive is not sufficient. Here I would like to submit only one thing for the consideration of Mr. Indrajit Gupta who has made his observations that we have given more relief to the higher income bracket, even percentage-wise. If I am permitted, I would like to quote a few lines from his observations. He says:

"If you see the reduction in income-tax rates, you will find that in term of percentages, the reductions are much lower in the lower brackets and much higher in the higher brackets".

Sir, it is not correct. Upto Rs 8,000, there is no income-tax; in the income group of Rs. 10,000, the percentage of tax to be paid is 3.3 per cent and in the income level of three lakhs, the percentage of tax to be paid is 58.37. If I quote these figures, you will find that at every stage, there has been progressive increase. At the same time, it has to be kept in mind that we made some changes in the direct tax side in the lower income group only in the month of July last year and the exemption limit was raised from Rs. 6,000 to Rs. 8,000. It is not a fact that we have not considered that aspect. We have considered that aspect, but at the same time we have tried to see that the tax

relief is equitably distributed. It is to be kept in mind that in the tax structure which we have been following till today, at a certain level of income when the tax percentage is so high, naturally if you want to give some relief, the quantum of relief would also be higher and perhaps that is the reason, why he has come to the conclusion that we have given more concessions to these people, and lower income group people have not been provided with sufficient concessions.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, another observation has been made by certain hon. Member, why we have given certain concessions so far luxury items like television, refrigerator etc. are concerned. I do not rule out the possibility and it is a fact that in a country like ours these items are used by relatively affluent class of the community. But at the same time, in a country like ours when you invest some money for establishing an industry, it is prudent and wise to see that the capacity of that industry is fully utilised. We have established certain television units and we have established certain refrigeration units. As a result of the demand constraint when it was found that these industries are not being properly utilised, their capacity are not fully utilised, we found that certain concessions were noticed. There too, perhaps you have noticed that we are giving concessions not only in the form of reduction of excise duty, but also at the same time, we are trying to see that the cost of these articles comes down. Therefore, the concession relating to television sets is provided so that the ex-factory cost is brought down to Rs. 1,800 which would act as an incentive to the manufacturers to produce and manufacture cheaper varieties of television sets. Therefore, I think, this is a welcome feature of the budget and which should have been welcomed by hon. Members of the House.



15.50 hrs.

[SHRI G. VISWANATHAN in the Chair]

Regarding the car industry, some hon. Member has made some observations. I would like to tell the House what happened when the Hindustan Motors were facing some difficulties. The Chief Minister, West Bengal convened a meeting in which I was also present. Most of the trade union leaders there advocated the same reasons for reduction of excise duty, because a large number of people were going to be thrown out of work. Therefore, this is very peculiar. They say something in camera, they advocate something in camera and when it comes to public, they say something different. If the cars are not sold, if the factory is closed, the problem is that quite a large number of people will be thrown out of job. It is true. I do not rule out the possibility that the bad shape of the industry is primarily the responsibility of the inefficient management. But, at the same time, when we are confronted with some situation we ought to take certain measures, I can tell you that quite a large number of trade union leaders who were present at that sitting, very strongly advocated the reduction of the excise duty on cars as a result of which when I straightaway refused to reduce the excise duty, the West Bengal Government reduced the Sales Tax. Therefore, this benefit is given to not only any one particular unit but to all the manufacturers of these types of cars and other types of vehicles. Therefore, that would create some demand, as a result of which the industrial units may not face that difficult situation which they are facing today.

श्री विष्णु मिश्र (मोतीहारी) :

जब आप से वे एक बात करते हैं और बाहर जा कर दूसरी बात करते हैं, तो जब से आप दस्तकृत करवा लिया करें।

SHRI PRANAB KUMAR MUKHER-

JEE; ऐसा करना पड़ना I would like to touch upon another aspect. Some hon. Members have made their observations about the bank rate. Here, I would like to submit for the consideration of the hon. Members that banks are also to work under a very difficult situation, under constraints. It is known to the hon. Members that out of every hundred rupees, the bank is to invest straightaway in approved securities to the extent of 33 per cent at the rate of 6 per cent interest and for 3 per cent they do not get any interest and even for certain areas, differential rates of interest prevail. Therefore, ultimately you will find that the scope of accommodation for banks is extremely limited. We have made just one small calculation from which we find that the banks' income out of the interest charged by them is in the order of 11.5 per cent. The bank is to pay at an average of 5.5 per cent. So, the balance is only 6 per cent and out of that 6 per cent the bank is to operate and there too, we charge 1 per cent tax. Therefore, it is really difficult for the bank and they have no other option but to adhere to the rate of interest which are prevailing. But, at the same time, it has to be kept in mind. I answered a question on the floor of the House, this very House that 83-84 per cent of the total bank advances is in the interest zone of 16 per cent or less. And only 15-16 per cent of the total advances are in the interest zone of 16-17 per cent interest and there too, it includes penal rate of interest. At the same time, I do feel that there is an area where the banks' efficiency could be improved and as a result of increased efficiency, if the costs would be reduced, that should have its reflection. Perhaps hon. Members are aware that already the Reserve Bank of India have taken a decision and reduced the interest rates and fixed a maximum of 16.5 per cent....

SHRI RAGHUNANDAN LAL BHATTIA: Reduce their expenditure.

**SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE:** That is true. At the same time, there too comes the question of trade unionism and all sorts of agreements.

Certain hon. Members have made their observations that banks' assistance is not available, particularly, for the development of rural economy. I would not like to bother the hon. Members with all sorts of statistics but I would like to humbly submit that it has been possible after rationalisation to increase the banks' branches in the rural areas considerably. Since 1969 to December 1975 it has been possible for the commercial banks to establish 46 branches in the rural areas out of every 100 branches, as a result of which on the day of nationalisation the number of rural branches was in the order of 1700—1800 but today it is more than 7000....

**SHRI K. NARAYANA RAO (Bobbili):** What does the Minister mean by rural banks? What exactly is the definition of a rural bank?

**SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE:** What I am talking of is the branches of commercial banks and public sector banks and private banks in the rural areas

There is another institution called rural bank. I do not know whether the hon. Member is mixing one with the other. Rural bank is a separate institution.

So far as credit requirement is concerned, previously, on the eve of nationalisation the total credit requirement from the commercial banks for the agriculture sector was Rs. 54 crores and by the end of June, 1975 it was more than Rs. 540 crores. The credit requirement increased 10 times. Percentage would be much more. I would not like to go to that. That is the area where we should improve. At the same time I do feel there is a

very big gap. The total rural credit requirement is of the order of Rs. 3,000 crores or whatever, it may be and if the rural credit co-operative sector and the commercial banks coming together cannot give beyond Rs. 1,400 or Rs. 1,500 crores, the big gap that is still there has to be bridged. That is the reason why a third institution—Regional Rural Banks—has to come up. When this Regional Rural Banks Bill was passed by the hon. House, we explained in detail the scheme of the Regional Rural Bank. I am glad to tell that the hon. Finance Minister promised before the country that within 31st March, 1976 we shall be able to establish 15 Regional Rural Banks. Till today 12 banks have already been established and 4 banks have been cleared. They are expected shortly. Perhaps, all of them may come within 31st March. If not all, they may come within a week or so thereafter. We have kept the promise of the Finance Minister and it has been possible to establish 15 rural branches of Regional Rural Banks within 31st March, 1976

These Regional Rural Banks will also help to fulfil the credit requirement of the rural areas. By merely opening branches it would be possible for us to take the credit to the rural people of the country. The rural population requires supporting agencies like Primary Service Societies, Co-operative organisations, etc., and the area is so vast that there is no question of proliferation of institutions. Many more agencies can function in these areas because the requirement is so large, gap is so wide, for filling that gap, we require many more supporting organisations in the form of farmer societies and all that.

It is known to the hon. Members that when we had a meeting of the Chief Executives of the Nationalised Banks, we made it quite clear that they ought to play the most important and vital role so far as 20 point socio-economic programme is concerned. Almost

12 points out of the 20 points are directly or indirectly linked with the functioning of these banks.

Before I conclude, I would like to make one more submission. Certain hon. members sometimes raised a question why banks are adhering to this 10 mile formula. The formula is not something golden and it is not a fact that it cannot be changed. But the whole question is when a branch of the bank is to operate, it is expected to operate efficiently and whether it would be possible for them to manage an area wider than that which is being prescribed. But at the same time here we have given options to the banks and by having the sense of the hon. House, we will instruct them that they can go beyond the prescribed limit of 10 or 12 miles. At the same time this is to be kept in mind that the ultimate answer to the question is not by extending the jurisdiction, but the ultimate answer to the question is the expansion of the branches, establishment of the branches in the un-banked areas and the three year rolling formula which has been taken by the various public sector banks. It is expected that it would be possible for us to bring the un-banked area within the range of the commercial banks and at the same time with the establishment and strengthening of the co-operative movement, establishment of the Regional Rural Banks, it would be possible for us to take care of the requirement of the rural population to some extent.

**SHRI VASANT SATHE:** The other day Acharya Vinoba Bhave made a suggestion saying that in regard to returns to be made to the Government, in regard to repayment of loans given by banks, etc. these may be taken in kind. For example, you may give a loan to a man producing leather goods. He can return to you something in the form of leather goods produced. Can you think of some such thing so that some of your problems of having securities, etc. might be covered?

**SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE:** To some extent the problem is covered by the sort of crop loans which we are giving to them. But the wider question is something which I cannot just answer off-hand. This requires some sort of detailed examination and consideration. But, before I conclude, I would say, we have taken certain steps. But at the same time we are quite aware of the inadequacy of the steps, we are quite aware of the shortcomings etc. But I have every reason to believe that with the state of the economy as it exists today it would be possible to fulfil the expectations which have been expressed by the hon. Finance Minister in his Budget speech.

**श्री राजदेव सिंह (जीनपुर) :**  
सभापति जी, किसी देश का बजट वहाँ के लोगों को बिना प्रभावित किये नहीं रहता है। हमारे इस बजट पर देश के भीतर के लोगों के एक्शन और रि-एक्शन आये हैं। लेकिन अभी भी देश में बहुत बड़ी जनता इस बजट को समझने की क्षमता नहीं रखती है। उसके एक्शन और रि-एक्शन क्या हैं, यह हमें मालूम नहीं हो सके हैं। यह बजट और बजटों से कुछ आगे बढ़ा हुआ है।

हमें यह देखना है कि "गरीबी हटाओ" और "निरक्षरता हटाओ" की दिशा में यह बजट कितना कामयाब होता है। कामयाबी में यह बजट कैसा है, इसे हम नापने की कोशिश करेंगे। जब हम इन बजट की बात करें, तो हमारे देश का जो इकनामिक स्ट्रक्चर है, वह हमारी प्रांशों से प्रोत्सल नहीं होना चाहिए। हमारे देश का वार्षिक डॉचा कई दर्जन इकनामिक कार्यक्रमों में बंटा हुआ है। ब्रिजवादी मिलने के 25 साल बाद भी 40 फीसदी लोग ऐसे हैं हमारे देश में, जो कि भूखमरी की साइन पर खड़े हैं और यह सब नहीं है कि उन्हें दोनो कमत खाना

[श्री राजवेन सिंह]

मिलता है या नहीं, पता नहीं उनके पास कपड़ा है या नहीं धीर रहने के लिए मकाम है या नहीं। आज लोगों की यह हालत है। जिस वक्त बजट की बात कहने हैं, उस समय यह तस्वीर हमारे सामने जरूर आती है।

आज भी हमारे देश में जाड़े के दिनों में 80 फीसदी लोगों के बदन पर कपड़ा नहीं होता है। 60, 70 फीसदी लोग ऐसे हैं, जिनकी पूरी जिन्दगी बीत जाती है, पर पैर में जना पहनने को नहीं मिलता है। यह बजट उनके लिए क्या दे रहा है, जो कि इन्फ्लेमेटिव डेवलपमेंट के लैंडर पर सबसे नीचे की सीढ़ी पर खड़े है ?

बहुन सी चीजों पर से टैक्स हटा कर उनको मस्ता किया गया है। लेकिन जैसी कि चर्चा हो रही है, कितने लोग "रेक्रीजरेटर का इन्वेन्शन करने है, कितने लोग कार का इन्माल करने हैं ? हम तो यह कहने हैं कि कितने लोग सावन का इन्वेन्शन करने हैं। मिडिल क्लास के अलावा 40 परसेन्ट लोग वे हैं, जिन्हें खाना नसीब नहीं होता। जिन चीजों पर से एक्साइज हटा कर इस बजट में मस्ता किया गया है, वह उनके इन्वेन्शन की चीजे नहीं है उनमें उनको कोई फर्क नहीं पडता है।

अभी फिनांस के मिनिस्टर आफ स्टेट ने कलकत्ता के हिन्दुस्तान मोटर्स कारखाने का जिक्र किया, जिस के बारे में मांग की गई है कि इस बान का खयाल रखा जाये कि वहां छटनी न होने पाये। लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हू कि सरकार द्वारा एक्साइज इयूटी को 2,000 रुपये कम कर के कार की कीमत को सस्ता करने के बावजूद कारों की बिक्री नहीं बढ़ेगी। अगर सरकार पेट्रोल को सस्ता नहीं करेगी,

तो पैसेजर कार की कीमतियां बढ जायेंगी। दिल्ली में पेट्रोल 3-38 रुपये लिटर के हिसाब से मिलना है। इस में 2-36 रुपये सिर्फ टैक्स है। रिफ़ाईनिंग, ट्रांसपोर्ट और एजेंट का कमीशन, यह सब मिला कर पेट्रोल का दाम 1.02 रुपया होता है। कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस को मेन्टेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेट्रोल के दाम बहुत उपादा हैं। इसलिए जब तक सरकार पेट्रोल को सस्ता नहीं करेगी, तब तक कार इंडस्ट्री को जिन्दा नहीं रखा जा सकता है—बढ़ बैठ जायेगी, इस में कोई दो गये नहीं।

मेरे पास यह सैट्रल इन्स्टीट्यूट आफ रिमर्च एण्ड ट्रेनिंग इन पब्लिक को-आपरेशन की एक रिपोर्ट है। उस के कहा गया है कि हमारे देश में छ करोड बच्चों को परवरिश नायक भूराक नहीं मिल रही है और उन में से ढाई करोड बच्चे हर साल अश्वे हो जाते हैं। प्रश्न यह है कि इस बजट में उनके लिए क्या किया गया है। सरकार कहीं कहीं एक्म-पेक्टेट मदज़ें और छोटे बच्चों के लिए नरिशिंग फूड की व्यवस्था कर रही है, लेकिन वह इतने छोटे पैमाने पर है कि हमारे देश में बच्चों को पीण्डिक आहार न मिलने के कारण जो तबाही हो रही है, उनमें उस को रोकना नहीं जा सकता है।

हमारे यहां एक आर्गनाइजेशन है इंडियन टाक्सीकालोजिकल रिसेर्च सेंटर। उस की एक रिपोर्ट में यू० एन० प्रो० के एक एक्सपर्ट ने कहा है "दि होल जेनीरेशन आफ इंडियन्स हैव गोन थ्रु बिदाउट नोइव दि टू टेस्ट फ़ाक फूड"। इस से हमारे देश की हालत का अन्दाज़ लगाया जा सकता है।

पेटेण्ट मेडिसिन्स पर एक्ससाइज ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। मिनिस्टर साहब और माननीय सदस्यों को मालूम है कि अस्पतालों में जो पेटेण्ट मेडिसिन्स तथा अन्य दवायें आती हैं, वे ज्यादातर बाहर ब्लैक में बेंच दी जाती हैं। अगर कोई अमीर पीसे वाला आदमी अस्पताल में जाता है, तो उस को वहाँ से दवायें मिल जाती हैं, लेकिन गरीब मरीज को बाजार में जा कर दवायें खरीदनी पड़ती हैं। इसलिए पेटेण्ट मेडिसिन्स और दूसरी दवायों का दाम बढ़ाना गरीब जनता के हित के विरुद्ध है। इस स्थिति में मैं यह अनुरोध करूँगा कि पेटेण्ट मेडिसिन्स पर जो ड्यूटी बढ़ाई गई है, सरकार उस को वापस ले ले, वरना इस देश का गरीब मारा जायेगा, जिसे अस्पताल जाने पर भी बाजार से दवायें खरीदनी पड़नी हैं, क्योंकि अस्पताल वाले उस को दवायें नहीं देने हैं।

हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर में गल्ला खरीदने में लग जाता है। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में जितना गल्ला पैदा होता है, अगर हम उस के लीकेज को बन्द कर दे, तो हमें बाहर से बिलकुल गल्ला नहीं भगाना पड़ेगा। अगर दो चार माल में ही हम अपना इनना बफर स्टॉक बना ले कि हमें कभी दिक्कत न पड़े। कभी सूखा पड़ जाय या कभी कुछ और हो तो हमें दिक्कत न पड़े। इसके लिए एक एग्जिक्टिव डाइरेक्टर मिस्टर एम० थार० बरुआ हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उसे मैं पढ़ रहा हूँ, यह एक कटिंग है अखबार की।

"The damage done by rates is estimated at 4000 million, both in storage and other things. Thefts turned out to be about ten per cent, a loss of about Rs. 1500 crores in terms of international price of wheat."

यह उन का कहना है और उन का यह भी कहना है कि इस देश में जितनी पापुलेशन है उसके सात गुने चूहे हैं। कल हूँ एक अखबार की कटिंग पढ़ने को मिली थी कि अकेले एक जिल में 296 चूहे मिले हैं जिसमें से 103 एडल्ट थे और बाकी बच्चे थे। उसी जिल में 30 किस्को पैडी भी मिला है। तो समझ लीजिए चूहों की तादाद हमारे देश में बहुत बड़ी है और इसे जब तक खत्म नहीं किया जायगा, तब तक यह पन्द्रह सौ करोड़ का जो साल में लीकेज है वह समाप्त नहीं होगा जिस की वजह से कि हम मेल्ट रफिजेंट नहीं हो पाते हैं। इस के लिए गवर्नमेंट को बार बेमिग पर कोई कदम उठाना चाहिए। जैसा कि हम ने एक जगह और भी कहा था चूहों को मारने के लिए रेडियो, टेलीविजन, अखबार और विम्पलेट आदि में हमें इन्सैटिव देना चाहिए कि जो एक चूहे को मारेगा उसे आठ प्राप्ति देंगे। इस तरह आप देखेंगे कि गाँवों के अन्दर जितने नेकार लोग है वे मारे चूहों को मार डालेंगे। किन्ही किन्ही देशों में ऐसा हुआ है।

धन में उत्तर प्रदेश के बारे में बोड़ी सी बातें कहूँगा। हमारे उत्तर प्रदेश में जब प्लानिंग शुरू हुई तो अर्बर्ड हालत थी। लेकिन चार पंचवर्षीय योजनाओं और कई एक मान्यता योजनाओं के चलने के बाद उत्तर प्रदेश की हालत दिन-प्रति दिन बिगड़ती गई। पहली और दूसरी योजना में उत्तर प्रदेश को सेंटर में कोई क्राइटेन्जियल अतिस्टेंस नहीं मिली। 51 में यह पोजीशन थी उत्तर प्रदेश में कि वहाँ के लोगों की प्रति क्यपिग प्राय 259.62 थी।... (अव्यक्त)

SHRI C. H. MOHAMED KOYA (Manjeri): Sir, I rise to support the budget which has given a ray of hope in an otherwise dark horizon of the fin-

[Shri C. H. Mohamed Koya]

ancial position of the country. The hon. Minister announced certain concessions in taxes on consumer goods. More things could have been thought of. I do not know whether this will arrest the price rise. Today's news is a little disturbing, prices are not coming down inspite of the fact that concessions had been announced. What we appreciate is the deviation from the policies hitherto followed. Every year in the past there were more and more taxes and no tax concession at all. Now the government is thinking of tax concessions and the lot of the poorman. We are now having the 20 point programme for the uplift of the downtrodden. It is necessary that the price of foodgrains and other essential articles of common use must come down. In countries like Soviet Russia the prices are comparatively high but the price of bread is low. You must encourage the production of coarse cloth which is used by the common man. I am reminded of a suggestion made by the late Rajagopalachariar that dhoties and lungis should be confined to the handloom sector.

I am coming from a state which is chronically deficit in food. The local produce is sufficient only for two or three weeks. Our Government has requested the Central Government to supply rice to the Kerala State at the rate of 160 gram per adult per day. Now about 95,000 tonnes of rice are required for the State. With the increased procurement in the country and the build-up stock of foodgrains in the Central pool, it will be possible for the Government of India to increase the supply of rice for the State. If sufficient quantity of foodgrains is not allotted to the Kerala State, then the prices of other articles would go up. You have already controlled the movement of foodgrains from one State to another. You have not allowed our State to purchase foodgrains from the neighbouring States instead of going to a far off country like Nepal. If the Centre does not allot foodgrains in

sufficient quantity, then our position will be very difficult.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): You ask for it from the Andhra Pradesh. We will give you the foodgrains.

SHRI C. H. MOHAMED KOYA: But the Centre have got a dog in the manger policy. It is gratifying to note that the Government is trying to reduce the price of fertiliser and the farmers will surely be benefited by that. But in Kerala, coconut is the main product. Kerala's main economy is based on coconut. The State Government has requested the Central Government to have a floor price for coconut. But this is not even thought of and we find that there is not much response from the Government.

Then, Sir, we are giving importance to the hydroelectric power. Kerala has not got much of mineral wealth, but its wealth is rivers with which we can produce electricity. Now, work on the first stage of Idikki project is over. Yesterday I was really surprised to read that the engineers working on this project have already started moving on transfer to other departments, because there are no funds available for taking up the second-stage of this project in hand. We have the capacity to produce power and supply the same to the neighbouring States like Tamil Nadu and Karnataka. If the Central Government comes to our rescue, we will produce electricity and we can run the trains and make the wheels of the factories in Karnataka and Tamil Nadu move.

Sir, great stress is laid on the earning of foreign exchange. But Government must relax various restrictions which have now been put on the export of timber and other things to the foreign countries. Then, there is the question of unemployment. Kerala is really having the problem of educated unemployment. We used to send educated people to other States in India. But when our national integration has reached at such a level, it has become

very difficult for our people to go to other States in India for employment. They want to go to foreign countries. But there also there are a lot of restrictions and discouragement. Our people are wanted in the Middle East countries, Gulf countries, Iran, etc. But unfortunately Government of India has put restrictions on this and they have been allowed to be recruited only through the Department of Personnel, Government of India. Again there is another handicap in the Ministry of External Affairs in recruiting personnel for foreign assignments. They have been a stumbling block for those who want to go abroad and earn foreign exchange which can be remitted to our country. But our government is following an unhelpful policy. They forget the fact that if we put restrictions on our people from taking up employment abroad those countries get the manpower from Pakistan and African countries also. Some countries have got oil, some technical know-how or other wealth, but our wealth is our man-power. If our government makes an earnest effort to see that our people are enable to go to foreign countries where they are needed, we will not only earn enough foreign exchange but also solve our unemployment problem. I would request the government to follow a lenient policy in this regard. The present bureaucratic approach which does not look at things from a humanitarian or practical point of view will not help.

There is popular enthusiasm for the 20-point programme and because of discipline, production in our factories has gone up. This should not be allowed to slacken as time passes. Government should be careful that there is no deterioration in discipline.

People expected that there would be some reduction in petrol prices but they have been disappointed. Not only the aristocratic people but the poor man also is affected indirectly by high petrol prices. So, I hope that the Finance Minister will reconsider this point and announce some reduction in petrol prices.

With these words, Sir, I support the budget and the policies underlying it.

**THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K RAGHU RAMAIAH)** There are a number of speakers on both sides of the House who want to speak. Shrimati Sushila Rohatgi also wants to intervene for 15 minutes at 5 O'clock I, therefore, propose that the House may sit till 7 O'clock today if necessary. I have consulted the opposition members also and they are agreeable.

**MR CHAIRMAN** I take it that the House agrees to this suggestion. Shri Ram Gopal Reddy.

**SHRI M RAM GOPAL REDDY (Nizamabad)** Sir, the Finance Minister and his young and able colleague, Shri Pranab Mukherjee deserve all congratulations for the excellent budget they have presented. I congratulate them on delinking the rupee from pound sterling providing decent allocation for defence, science, technology and research, reducing prices of fertilisers and for not reducing the petrol prices. If some people find petrol too costly, let them travel by bus or bullock cart.

Sir now I give some of the proposals. Just now, the Member from Kerala said that there was food shortage in Kerala and he wanted 95 000 tonnes of rice. My district alone is in a position to supply 95 000 tonnes of rice or one lakh tonnes to Kerala.

**SHRI C K CHANDRAPAN (Telichery)** You will give us but the Centre will not allow that.

**SHRI M RAM GOPAL REDDY** These restrictions must be removed immediately. All these zones must be done away with. At some places, rice is selling at Rs 6 a kilo but in our part, we would not get even at Rs 1.25. That is the fate of the thing. Godowns are full with foodgrains. I am afraid, all these things may get deteriorated and they will become unfit for human consumption and then it will be

[Shri M. Ram Gopal Reddy]

sold as cattle feed. Before such a situation comes. I would request the Government to abolish all barriers so that food can flow smoothly from one area to another.

Once the production target is reached, under no circumstances it should be allowed to go down next year. Last year, sugar production was 45 lakh tonnes. But this year it is going to be less by four lakh tonnes. Only Maharashtra is giving 2 lakh tonnes extra. All the other States are giving less. If four lakh tonnes of sugar is not exported, Government of India will lose about Rs. 100 crores by way of foreign exchange. This is a very serious thing. The agriculturists of this country are very clever. Last year in Andhra Pradesh the price of sugar was fixed at Rs. 117 per bag. Out of that Rs 117, Rs. 10 will go to the States in the form of taxes and Rs. 6 will go for gunny bag. The Andhra Pradesh industry has to supply sugar at the rate of Rs. 117 per quintal. This is the cheapest thing and that is why, this year, the production is going down by 1.5 lakh tonnes. Even if the sugar production is going down, we have to tighten our belts and we should export as much as possible. We should export at least 15 lakh tonnes. If that is not done, all the estimates which the Finance Minister has made, will go wrong.

Tax collection out of one rupee is like this: 24 paise from excise, 12 paise from customs, 8 paise from corporation tax, 2 paise from It, 2 paise from other taxes, 15 paise from non-tax revenue, 12 paise from loan recoveries, 9 paise from market loans, small savings, provident fund and 6 paise from external loans. I take serious objection to that. Why such a big country should go on begging only for 6 per cent of our Budget? This money must be made good from our own resources. Only 2 paise remain uncovered. I would like that this 6 paise plus 2 paise must be made good from our own resources.

Not more than 20 per cent should be spent on the salaries of the Government employees. I am really shocked to learn that 70 percent of our Budget is spent on salaries alone either in the States or at the Centre. The curious thing in this context is that some State Governments are drawing huge amounts as over-draft and they are increasing the salaries of their employees. The other day, the Agriculture Minister has said that all the prices of foodgrains and other agricultural commodities have gone down by 24 per cent. In spite of that, some States have increased the salaries of their employees. I want to know whether the Central Government have any control over the States. I want that the Centre should have all the details about the finances of the States so that such things are not repeated. And in one State, an increase of Rs. 100 crores has been made in two years. I do not understand the sanctity behind spending money like this. On the one hand, Government is squeezing the people to make them pay more; on the other, they are giving so much of money to the employees. Prices have now fallen; and I would ask the Minister to tell me whether he is going to reduce the D.A. or not. Taking some amount from the employees, keeping it on deposit for sometime and later on refunding it along with 12 per cent interest, will not help. The people in our Services are very patriotic. They should also ask the Government to reduce their salaries in proportion to the fall in the cost of living. The cost must be calculated every month and reductions made in the salaries.

Everybody says that banks should go on giving loans. There are two types of losses incurred by these banks. Co-operative banks advance money. When that money is not recovered, their official is in a position to attach the property of the defaulter concerned; but scheduled banks and nationalized banks have to stand in the queue in the courts of law and fight cases endlessly. Is the Government going to



enact at law similar to those followed by the cooperative banks? It may be wrong on my part to say this; but I don't care as to what people would say about it. After all, defaulters constitute only 5 per cent or 6 per cent in business. But they can destroy any bank, if they choose to. There must be a law framed for this purpose. Banks also, like the cooperative banks, should be able to attach property.

Now about the fall in the prices of agricultural produce. If the Government does not come to the rescue of the people, the latter are not going to produce more. There is sufficient water in the reservoir in my constituency already and sufficient fertilizer available. Even then when they were asked to plant cane in 35,000 acres, they have planted it in not more than 25,000 acres, because the prices are not remunerative. Water and electricity charges have gone up, prices of everything else have gone up; but people are being paid on the basis of the position which prevailed during the previous year.

**SHRI K. GOPAL (Karur):** But you want Government servants' salaries to be reduced.

**SHRI M. RAM GOPAL REDDY:** Yes. You have to calculate. Two years back, I used to pay Rs. 100 per acre towards land revenue; I am now asked to pay Rs. 200.

**SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore):** You should pay Rs. 300.

**SHRI M. RAM GOPAL REDDY:** I will pay Rs. 300.

**MR. CHAIRMAN:** Don't interrupt him. Time is short.

**SHRI M. RAM GOPAL REDDY:** In Maharashtra, they have introduced a system whereby, if in a village, ten educated unemployed persons join together and form a society and approach the district collector, the latter will give some work to it. A similar thing should be introduced in the whole of

India. I congratulate the Maharashtra Government. There is a persistent demand that the exemption limit for income-tax which is at present Rs. 8,000, should be raised to Rs. 10,000 or Rs. 12,000. Anybody coming within the net of the Income-Tax Act gets an income which is 10 or 12 times the per capita income in the country. Therefore, the income-tax exemption limit should not be raised beyond Rs. 8,000.

श्री परिपूर्णचंद्र पेंसुली (टिहरी गढ़वाल) : महापति जी, मैं इस बजट का स्वागत करना हूँ और श्री मंत्री के माध्यम से वित्त मंत्री जी को यह कहना चाहता हूँ कि इस देश की करोड़ों जनता ने इस बजट का स्वागत किया है। यदि यह कहा जाए कि यह जनता का बजट है, तो गलत नहीं होगा। वही वित्त मंत्री श्री मुद्रहराण्यम, जिन्होंने इस समय बजट प्रस्तुत किया है, पिछले वर्ष भी वित्त मंत्री थे और वही वित्त विभाग के अधिकारी थे जिन्होंने इस बजट को बनाने में उन्हें सहायता दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस अच्छे बजट के बनने में बहुत कुछ श्रेय आपातकालीन स्थिति को है। इपजैमी के बाद प्रजातंत्र मंत्री जी ने जो बीस सूची आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की उसके पश्चात् देश में जो वातावरण पैदा हुआ इस ने बहुत कुछ चीजों के दाम बढ़ाने में सहायता की। बेरोजगारी कुछ हद तक दूर होने लगी है। हर भावनी अनुशासन में रहने लगा है। इस एमर्जेंसी को मैं बहुत कुछ इसके लिए जिम्मेदार समझता हूँ।

विरोधी पक्ष के कुछ मित्रों ने और बास तीर पर चावड़ा साहब ने बेरोजगारी बढ़ने की बात कही है। और भी बहुत सी धारासंघिक बातें भी उन्होंने कह डाली हैं जो कि विवेक मन्त्रालय या दूसरे मन्त्रालयों से सम्बन्ध

[श्री परिपूर्णानन्द पैन्ग्लो]

रखती थीं। उनका बजट के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। मैं स्वीकार करता हूँ कि बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ी है। सरकारी प्रांकों के अनुसार गत सितम्बर 1975 में बेरोजगारों की संख्या 92 लाख 54 हजार थी। उस अवधि में 7.1 प्रतिशत एक वर्ष के भीतर बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। इस सन्दर्भ में देखने की आवश्यकता यह है कि बेरोजगारी बढ़ने के लिए किस हद तक हमारी जनसंख्या में वृद्धि है। एजुकेटिड अनएम्प्लायड की बात कही जाती है। मैं कहूंगा कि मिस-एजुकेटिड अनएम्प्लायड परसन्ध हैं। उनको शिक्षा गलत तरीके से दी गई है। इस कारण से पढ़े लिखे बेरोजगारों के नाम पर उनकी संख्या में बहुत वृद्धि होती चली गई है। मैं समझता हूँ कि शिक्षा के सारे कार्यक्रम को बदलने की आवश्यकता है।

बजट जो बनता है वह पांच वर्षों के हमारे कार्यक्रम की एक रूपरेखा का एक अंग होना चाहिये। उसी प्रकार से हमारी जो पंचवर्षीय योजना बनती है उसको भी आगामी पचास वर्षों में देश का हम भविष्य क्या करना चाहते हैं उसका एक अंग होना चाहिये। इस सन्दर्भ में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमारा जो एक वर्ष का बजट होता है उसका पचास वर्ष या पांच वर्ष की योजना के साथ कोई तालमेल नहीं हो पाता है।

उद्योगों को कुछ कंसेशन दिए गए हैं, प्रत्यक्ष करों में कमी की गई है उत्पादन के लिए कुछ इंसेंटिव देने की घोषणा की गई है। लेकिन इसके बावजूद बाजारों में बहुत सी चीजों के भाव कम नहीं हुए हैं। किसान भी इस बजट से बहुत ज्यादा परेशान हैं। आज अखबारों में आया है कि श्री पार्स ने घोषणा की है कि ये जो कंसेशन दिए गए हैं वे उपभोक्ता को राहत पहुंचाने के लिए दिए गए हैं न कि उद्योगपतियों को राहत पहुंचाने के लिए।

आसन को बढ़े कदम उठाने चाहिये ताकि इन कंसेशन का लाभ उपभोक्ता को पहुंच सके।

हम देखते हैं कि पब्लिक सैक्टर अंडर-टेकिंग का उत्पादन 35 प्रतिशत बढ़ा है किन्तु प्राइवेट सैक्टर का उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ा है। प्रायको कदम उठाने चाहिए कि उसका उत्पादन भी इसी तरह से बढ़ सके। इसके लिए नीति सम्बन्धी घोषणा में या कानूनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो वह भी अवश्य किया जाना चाहिये।

रोजगारों की आवश्यकताओं की जो चीजें हैं, जैसे साहुन हैं, तेल हैं, जूता है या दूसरी वस्तुएं हैं इनको बड़े बड़े कारखाने वार न बनाएं और गृह उद्योग ही इनको बनाएं, इसकी धोर भी अंगर बित मन्त्री जा ने संकेत किया होता तो अच्छा होता। इन धोर भी प्रायका ध्यान जाना चाहिये।

कमजोर, वगैरे, हरिजनों, धार्मिकताओं, पिछड़े क्षेत्रों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए जितना प्रावधान किया जाना चाहिये या खर्च नहीं किया जा सका है। प्राय तो भली भांति परिचित हैं कि वहां जो खर्चा होता है उसमें 51 या 52 या 53 प्रतिशत एस्टे-ब्लिशमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन पर ही हो जाता है और वहां की जनता के विकास के नाम पर जो खर्चा होता है उसका छीजन होते होने वह दस प्रतिशत भी नहीं रह जाता है। इन कारण उन इलाकों का अभी तक विकास नहीं हो पाया है। इस धोर भी प्रायका ध्यान जाना चाहिये।

बीस सूची कार्यक्रम में कई बातें बहुत अच्छी हुई हैं। स्पनलब के खिलाफ प्रायने कार्रवाई की है और उसके प्रांकों पेस किए हैं। इसके लिए मैं प्रायको बधाई देता हूँ। इनकम टैक्स की चोरी जो होती है उन लोगों की तरफ भी प्रायका ध्यान जाना चाहिये। जो इनकम टैक्स देने वालों की श्रेणी में आते

हैं उनकी क्या उससे कहीं अधिक है जो आपने बताया है। मैं आपके नोटिस में इस चीज को सा चुका हूँ। शायद आपका जो समझन है वह इतना मजबूत नहीं है या कोई और बातें हैं जिनकी वजह से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। मैं चाहता हूँ इसको भी आप देखें और चोरी जो होती है इनको रोकने की कोशिश करें।

बीस सुवी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होनी चाहिये कि जितने साधन हम जुटाते हैं उन साधनों के साथ जन-शक्ति का तालमेल भी बिठाए और देखें कि किस प्रकार से जनता को अपने पैरों पर खड़ा करने के काबिल हम बना सकते हैं। उदाहरण के लिए खादी कमीशन गृह उद्योग का धाम करता है, किन्तु मैं यह कहना हूँ कि यह जितनी निकम्मी मस्या है, करोड़ों रुपया इस पर खर्च हो रहे हैं लेकिन अनुपात में इसका काम करीब-करीब नगण्य है।

पर्वतीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ कि कौश-काप सब्जी, फल और सब वरीर पैदा होते हैं। आपने एक ब्लैकट स्कीम बनाकर अनाज के उत्पादन का जो पैमाना मैदानों के लिये बनाया है पहाड़ों में भी उसी के सम्बन्ध में घोषणा की है, किन्तु इस प्रकार के क्षेत्र में, जिसमें हिमाचल प्रदेश और काश्मीर भी आते हैं, जो कौश-काप पैदा करने वाले लोग हैं, उनके क्विय न इतने सपोर्ट दिया है और न खरीद की मारप्टी की घोषणा की है। आपको मालूम होना चाहिये कि इस तीनों प्रान्तों—उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के हिस्से, हिमाचल प्रदेश और काश्मीर—में इससे सम्बन्धित सब करोड़ के लगभग जनता गरीब है। अगर हमें अनाज बाहर से खरीदना पड़े और हमारी जब में पैसे न हो, हमारी अर्थ-व्यवस्था ठीक न हो तो हम क्या कर पायेंगे ? यह क्षेत्र आपके लिये धार-स्वरूप बन जायेंगे।

हमारे देश में बाढ़ और सूखे का प्रकोप हर साल आता है और हर साल बजट में इसके लिये प्रावधान किया जाता है, किन्तु मूल में जाने का अभी तक प्रयास नहीं किया गया। अभी तक उसकी रोकथाम की व्यवस्था सक्रिय रूप से नहीं की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बजट में आपके विशेष रूप से इसके लिए प्रावधान करने की आवश्यकता थी।

नदी के कैचमेंट एरियाज हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें एफास्ट्रेशन अर्थात् वनोत्पादन को और विशेष ध्यान देना चाहिये या और वन-सम्पदा पर आधारित गृह-उद्योग स्थापित करने चाहिये, क्योंकि लोगों के पास गृह-उद्योग न होने के कारण उन्होंने जमीन खोदी, और उससे भू-स्खलन बढ़ रहा है। देहरादून और मसूरी क्षेत्र में चूने के पत्थर की खान हैं जो कि प्राइवेट सैक्टर के लोगों की हैं। उन्होंने बेतहाशा वहाँ पर खनन किया है, जिससे हर साल सायल इरोजन बढ़ता जा रहा है, लेकिन शासन इस सम्बन्ध में खामोश लगता है।

अन्त में मैं बुन्देलखण्ड की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए तीन साकों में से एक है। मध्य प्रदेश में कन्नड़ द्वारा प्रति व्यक्ति जो सहायता दी जाती है बुन्देलखण्ड में उससे आधी सहायता दी जाती है। मैं वित्त मन्त्री और प्लानिंग कमीशन को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूँ उन्होंने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिये आगामी वर्ष के लिये वही केन्द्रीय सहायता पर-कैपिटल सहायता देना स्वीकार किया है, जो हिमाचल प्रदेश को मिलता है। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि उत्तर देश के जो दूसरे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड, उनके साथ भी सीतेला व्यवहार न किया जाये। उनको भी उतनी ही सहायता दी जाये, जो कमजोर क्षेत्र को देते हैं। जब तक उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है।

[श्री परिपूर्णानन्द वैष्णवी]

इन शब्दों के साथ मैं बजट का स्वागत करता हूँ और समर्थन करता हूँ।

**SHRI C K. CHANDRAPPA** (Telli-cherry) This is the first Budget which this Government has introduced after the emergency has been proclaimed and also after the 20 point programme has been announced by the Prime Minister. So, there was a great expectation among the people that it would be basically different from the other Budgets that the Government had introduced in the past

The hon Minister will say that there are so many kinds of relief offered to people in this Budget and also that there is a new approach. I agree that there is a new emphasis on planning and also that there are attempts to give some reliefs to certain sections of the common people. I will also not say that deliberate attempts have been made by the Government put more burdens on the shoulders of the common people. But that was not enough, that would not by itself fulfil the expectation that the common people had of this Government at this time

My complaint is that this Budget depends so heavily on foreign aid. The Government expects that the uncovered gap in the Budget can be filled by taking money from the banks, that is, the money kept by way of D.A. and so many other things. Now, this Budget will have also an inflationary effect on the economy in the coming period. This tax on policy which the Government is pursuing, I think, will perpetuate and accentuate the economic inequality. These are our complaints that I have put in short about this Budget

Another thing is that the Government, in a big way, have failed to come forward with such schemes by which the common man would have been benefited. The hon. Minister had just now claimed that your taxation policy

is such that it gave relief to the common people and also to the people who are paying higher income tax. But I would like to draw your attention to some of the facts. If you remember Mr Salve, from the other side, and others who spoke when we were discussing the voluntary disclosure scheme referred to a new approach to the taxation policy. I have seen how that lobby was operating for reduction of taxes for the people who are giving high taxes, and at the same time, you said that it would be considered. Now, I have seen that you have not done that. That is the point.

In 1971-72, the maximum marginal rate of income tax was 93.5 per cent. Later on, it was reduced to 82.5 per cent. Last year it was 77 per cent and this year, it is being reduced to 66 per cent. This is the ladder by which you have descended and that is what Mr Indrajit Gupta had mentioned. It is not that you have given small concessions to people who deserve and whose income is being eroded by an inflationary trend.

With regard to calculations, you have used a stick and that stick has helped you, to some extent, to get hidden and undisclosed wealth. But that stick is used in a selective manner. Why did you not use that stick in an effective manner against Jaipur Sugar in Andhra Pradesh whose income arrears run into millions of rupees. Then, against at the time of voluntary disclosure, we had seen that your income tax officials caught hold of people and asked them to disclose their wealth voluntarily and they had become socially conscious capitalists. That is not the way. We do not agree with that approach. That is why Mr Indrajit Gupta had said that we would not support your Budget unconditionally. This is a deficit Budget. I must say that the Finance Minister is trying to dupe the whole world by saying that there is a small deficit. If you take the words of our Finance Minister, Mr. Chairman, the Finance

Minister, while introducing the Budget had said as follows

“Budgetary deficit of Rs 490 crores could have been Rs 100 lower had we taken advantage of the special borrowing to that extent from the Reserve Bank of India envisaged in the original Budget”

Last year, the uncovered gap presented was much less but it increased to Rs 490 crores. Your suggestion, this year, is that you will borrow from the banks to the tune of Rs 450 crores. Last year, they claimed that they had taken Rs 100 crores the deficit would have been Rs 490 crores minus Rs 100 crores. If the same standard is applied you are taking Rs 480 crores from the banks then you add to it the uncovered deficit of Rs 320 crores that you are leaving. So the deficit by the end of this year, according to the Finance Minister's own logic, will stand at Rs 800 crores. That is why we say that this is a deficit Budget. But the Government is trying to dupe the people by not saying that fact. It will lead to inflationary situation in the country if no preventive measures are taken.

There are other aspects also. In a country like India where the Government often claims that they are building an egalitarian society and that, ultimately, they are taking the country to socialism, the direct taxes should be more and indirect taxes should come down proportionately. But what happens in our country is that direct taxes are increasing. The indirect taxation never comes down, the proportion is on the increase. When we oppose the concessions given to people in higher income brackets, the Government says that such high taxation rate would lead to evasion and also black money. We do not agree with that principle. We have made it clear many times. Take for example the United Kingdom, a country which often is quoted as an example of democracy and everything. Even there, today the people belong-

ing to the highest income bracket pay 80 per cent as tax. Here, you have reduced it to 66 per cent.

Last year, the Government brought another taxation measure on poor bidi industry. The bidi worker, the poorest of the poor is further taxed. But the Biras and Tatas and other rich people are given relief. That should not be the approach. In our country, we are now in a better situation in relation to food. We hear very often about the bumper harvest and all that. But even today, we are living on imported food. What about the procurement? You are never reaching the target. You are still depending on imported food. You expect the foreign aid to cover your uncovered gap. You are supplying imported food through public distribution system.

My point is that when Emergency has been declared and the 20-point economic programme has been announced, the great expectations of the people have been aroused that this Government will take bold action, bold decisions by which the economic foundations on which the fascism has come up would be shattered. I am sorry to say that they are giving more and more concessions to those elements who create the danger of fascism in our country.

Then I should strike a note of warning that by emergency alone you will not be able to fight these reactionary forces. If you are to fight these reactionary forces, you must have a positive approach by which the socio-economic foundation of Fascism can be shattered. To that extent, the Government has failed. There is an economic survey spoken of and the strength of our economy lying in the strength of our public sector, but there is no talk of any nationalisation. Mr Ram Gopal Reddy speaks of the sugar barons and their difficulties. But why did the Government fail to nationalise the textile, jute and edible oil industries? Why could they not do it? And why is there no programme for massive construc-

[Shri C. K. Chandrappan]

'tion of houses for the poor to whom they are giving house-sites? Wherefrom can they build houses? And why is there no positive programme, though there are wishes expressed by the Minister, to fight unemployment? I also don't understand why there is no scheme for the Government to have a concrete programme. They have this 20-point programme; in June they claimed that the land-reforms will be completed and that the ceiling law will be implemented. But has it measured to what extent it has been successful? If it has not been successful, then the additional amount that you will invest in power generation etc. will only generate a kind of rural rich who, again, cannot be an asset to our democracy and democratic system.

So, these are the points on which we disagree with this budget.

श्री कुशक बाकुला (लद्दाख) : सभापति महोदय, माननीय वित्त-मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है वह जनता के लिए बड़ा लाभदायक बजट है—इसमें कोई गुंवहा नहीं है। हमारी महान् नेता, प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने जो आपात स्थिति की घोषणा की उसके बाद इस देश में बहुत सुधार हुआ है। साथ साथ बीम मुखी कार्यक्रम चलाया जिससे हमारे देश को उन्नति के रास्ते पर चलने में बड़ी सहायता मिली। यह कदम एक बहुत अच्छा कदम है, इसके लिए मैं प्रधान मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी का हार्दिक समर्थन करता हूँ।

अब मैं अपने हलाके की तरफ धित्त मन्त्री जी का ध्यान खीचना चाहता हूँ। मैं इस देश के उस राज्य से आता हूँ जिसको जम्मू कश्मीर राज्य कहते हैं। इस राज्य के तीन भाग हैं—जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। इसमें जम्मू और कश्मीर का नाम तो आता है लेकिन लद्दाख का नाम भी नहीं आता। जम्मू कश्मीर के नाम से ही सब चलते हैं। हमारे क्षेत्र का जिसना

विकास होना चाहिए उसका विकास नहीं हुआ है—इसमें कोई त्रक नहीं है। मैं 1967 से इस सदन में बोल रहा हूँ। कई सदन कमेटी की खोरे से वहाँ पर बहारे होने करना वहाँ पर कोई जाता नहीं है। इसलिए वहाँ की जो सही रिपोर्टें हैं वह नहीं मिलती हैं। मन्त्री महोदय तो कोई वहाँ पधारे नहीं। प्रधान मन्त्री जी आई हूँगी और डिफेंस से ताल्लुक रखने वाले मिनिस्टर आये होंगे लेकिन हमारे क्षेत्र के विकास की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि 68 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के लिए मिले हैं उनमें से लद्दाख को कितना मिलेगा? जम्मू और लद्दाख के लोगों के कहने पर गजेन्द्र गडकर कमीशन मुकरर हुआ था। वह कहते थे जम्मू में ज्यादा खर्चा होता है, कश्मीर में उतना नहीं होता और लद्दाख में कुछ नहीं होता। दूसरी जगहों पर बड़े बड़े पुल बनते हैं लेकिन हमारे यहाँ एक पुल भी नहीं बनता। हम लोगों ने आवाज उठाई तो उन्होंने गजेन्द्र गडकर कमीशन बैठा दिया। गजेन्द्र गडकर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बहुत अच्छे सुझाव दिये और जोर दिया कि लद्दाख के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये। आज जो रुपया केन्द्र से मिलता है, उसमें लद्दाख का कितना हिस्सा है, इसका उल्लेख न बजट में किया गया है और न ही वे हम को बताते हैं। जो पैसा केन्द्र से हमारे लिये दिया जाता है, वह कहाँ जाता है, किस काम पर खर्च होता है—कुछ मालूम नहीं होता। इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार के मन्त्रिमण्डल की एक कमेटी बनाई जाय जो हमारे मामलों की देखभाल करे।

17.00 hrs.

आप सब जानते हैं कि लद्दाख एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, हमारे सामने एक तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है, दूसरी तरफ बाकिस्तान बैठा हुआ है। यह ठीक है कि पाकिस्तान

हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन चाइना, जो हमारे सामने बैठा हुआ है, वहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। इसके मुकाबले में यदि आप लद्दाख में देखें तो कुछ नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं—आप शुरू से लद्दाख की स्थिति को देखें 1953 के बाद वहां क्या हुआ, 1959 के बाद क्या हुआ, 1970 के बाद क्या हुआ—कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट लद्दाख 49000 वर्ग मील में फैला हुआ है, इस के चारों तरफ दुश्मन खड़े हुए हैं। लिहा इसका डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर है, वहां मे केवल 150 मील की दूरी पर चाइना बैठा हुआ है। उनके इलाके में जो तरबकी हो रही है, वह हम सुनते रहते हैं, उसका असर यद्यपि अभी हमारे लोगों पर नहीं पडा है, लेकिन पड़ सकता है। आज लद्दाख में सबसे पहले बिजली की व्यवस्था होनी चाहिये—लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लद्दाख के तीन तहसील हैं—कारगिल, लेह और जंसका। लेह और कारगिल में छोटे डीजल इंजिन हैं, जिनसे बिजली पैदा की जाती है, लेकिन एक दिन बिजली भ्रानी है इनके दिन नहीं आती। एक पन-बिजली योजना—स्टकना प्रोजेक्ट आपने वहा पर शुरू किया, उसके लिये तीन करोड़ रुपया आपने खर्च किया, उभर भी बनाई गई, लेकिन पिछले साल 1975 में उस योजना को बन्द कर दिया गया। पहले तो हमारे वहा कोई योजना ही शुरू नहीं होती, अगर कोई शुरू होती है तो हम तरह से उसको बीच में ही रोक दिया जाता है। इसके बारे में मैं प्रधान मन्त्री जी, होम मिनिस्टर साहब और पन्त जी से मिला। उनसे चालू करने के लिये निवेदन किया, लेकिन अभी तक उसको चालू नहीं किया गया। कहते हैं कि एक दूसरी योजना—उपमी प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा। इस पर भी काफ़ी रुपया खर्च होगा। स्टकना योजना पर 40 करोड़ रुपया खर्च होगा, इसलिये इसको अभी बन्द कर दिया है। मैं जानना चाहता हूँ—स्टकना योजना भी तो आपके

इंजीनियरों ने बनाई थी, इसमें क्या कमी है, इस पर तीन करोड़ रुपया खर्च करने के बाद रोक देना कहां तक उचित है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस पर फौरन गौर करें और इसको चालू कराने की कृपा करें।

[SHRI C. M. STEPHEN in the Chair]

17.03 hrs.

आप देखिये—जगह जगह पुल बनाये जाते हैं, करोड़ों रुपया पुलों पर खर्च होता है, लेकिन हमारे यहां एक भी पुल नहीं बनाया गया। जो कुछ पुल बने हैं वे मिलिट्री के अपने लाभ की दृष्टि से बनाये हैं। यह ठीक है कि हमारे यहां पैसे की कमी है, लेकिन बीस मूनी कार्यक्रम में कहा गया है कि देश में बिजली का जाल बिछा देंगे, यह विकास लद्दाख में भी होना चाहिये। वहां बिजली की जो एक योजना थी, वह भी बन्द कर दी। कारगिल में ज्यादा मुमलमान रहते हैं, बड़ा गरीब इलाका है, वहां शुरू दरिया पर पन बिजली की एक स्कीम थी, लेकिन वह स्कीम अभी तक शुरू नहीं हुई है। स्टेट गवर्नमेंट कहनी है कि वह स्कीम जेरे गौर है। जम्मू-कश्मीर सरकार तो देखती नहीं, हमारी केन्द्रीय सरकार भी लद्दाख की तरफ नहीं देखती। अगर इसी तरह से लद्दाख की प्रब-हेलना हुई तो इसका खराब असर हो सकता है। मेरा निवेदन है कि स्टकना पन बिजली प्रोजेक्ट को आप पूरा करें। हो सकता है कि उससे लिफ्ट इर्रिगेशन न हो, लेकिन हमें बिजली तो मिल सकती है। आप कहते हैं कि डीजल इंजन लगाने तार्थिक हर गांव को बिजली मिल सके। मैंने इस बारे में कश्मीर के मुख्य मन्त्री से निवेदन किया तो वह कहते हैं कि केन्द्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, हम क्या करें। और जब वहा कहते हैं तो हमको जवाब मिलता है कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो हम किससे कहें। इसलिये

[श्री कुशक बाकुला]

हम चाहते हैं कि हमारे जिले में एक, दो जगह पर बिजली से बड़े प्रोजेक्ट लगा दें जिससे लदाख की तरक्की हो सके। वहाँ तरक्की न होने का सबसे बड़ा कारण बिजली का न होना है।

दूसरी बात यह कहनी है, मैंने पहले भी बिल मन्त्री जी से निवेदन किया था कि लेह में आकाशवाणी का केन्द्र है, वहाँ के कर्मचारियों को पूरा अलाउन्स नहीं मिल रहा है, जबकि कश्मीर सरकार के कर्मचारियों को जो लेह में रहते हैं, उनको 75 परसेंट अलाउन्स मिलता है 6 महीने के लिये क्योंकि वह इलाका काफ़ी ठंडा है। लेकिन आकाशवाणी के लोगों को नहीं मिल रहा है। आपको इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये जिससे उन लोगों को भी 75 परसेंट अलाउन्स मिल सके। जो लोग आकाशवाणी में काम करते हैं उनको सुबह 6, 7 बजे से रात के 10 बजे तक काम करना होता है, और लदाख ऐसी जगह है जो काफ़ी ठंडी है, इसलिये उनको जाई का अलाउन्स जरूर मिलना चाहिये। वहाँ एक बुडिस्ट फ़ैलोशिप स्कूल है जो केन्द्रीय सरकार का है, वहाँ लोगों को अलाउन्स मिल रहा है 75 परसेंट लेकिन आकाशवाणी के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। मेरा निवेदन है कि उनको भी मिलना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ इन्कम टैक्स लग रहा है। जबकि वहाँ बड़े बड़े व्यापारी नहीं हैं, चाहे वह लोकल हों या नान-लोकल। वह सब छोटे छोटे व्यापारी हैं, इसलिये मेरा सुझाव है कि उन लोगों पर 4, 5 साल तक कोई इन्कम टैक्स नहीं लगना चाहिये। वहाँ कोई व्यापारी इतना बड़ा नहीं है कि जो टैक्स की चोरी करे। मैंने इस बारे में दरकारत की हुई है और मुझे आशा है कि आप उस पर जरूर गौर करेंगे ताकि लदाख में 4, 5 साल तक इन्कम टैक्स न लगे।

आपको लदाख का विशेष ध्यान रखना चाहिये क्योंकि पास में ही आइसबीज स्टैंड हुए हैं। आपने 20 सूची प्रोग्राम में कहा है कि पिछड़े इलाकों की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। हमारा लदाख सबसे पहले पिछड़ा हुआ इलाका है हर क्षेत्र में। लेकिन फिर भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यह बड़े थ्रूसोस की बात है। हमारा लदाख गेड्यूल ट्राइब और गेड्यूल एरिया में नहीं आता। मैं जब से इन सदन में आया हूँ नब ने बराबर कह रहा हूँ कि लदाख को गेड्यूल ट्राइब और गेड्यूल एरिया घोषित करना चाहिये। ऐसा हो जाने से हमारे लोगों को बहुत सी सुविधायें मिलने लगेंगी जिनको प्राप्त करके वह भागे बढ सकते हैं। हमारे लोग पढना चाहते हैं, लेकिन उनको सुविधायें नहीं मिल रही हैं। इसलिये मेरी मांग है कि लदाख को गेड्यूल ट्राइब और गेड्यूल एरिया घोषित किया जाये, और साथ ही दूसरा निवेदन यह है कि सेप्टन गवर्नमेन्ट की एक कमेटी बनाई जाये जो लदाख की समस्याओं को अच्छी तरह से देखे और उनका हल सुझाये।

THE DEPUTY MINISTER IN THE  
MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI  
SUSHILA ROHATGI): While thanking  
each of the hon. Members who have  
participated in the discussion, with  
your permission, I would like to focus  
the attention of the House to another  
aspect. I think it is only natural that  
each of the hon. Members should make  
a plea for greater expenditure and  
budgeting for their own particular  
areas so that the country as a whole  
can prosper and go faster with an  
accelerated speed towards our economic  
goals. We need resources for all these  
purposes and how far we have been  
able to meet them depends upon vari-  
ous reasons. But we have to accept  
the fact that the nation as a whole  
will have to prosper and the regional  
imbalances and disparities should be  
brought down to the maximum extent.



Here, apart from direct taxes as also indirect taxation, there is another instrument of saving to which I would like to take the attention of the hon. House.

These instruments like the insurance schemes and national savings scheme have been able to mop up the savings of the people and how these savings are being utilised for more fruitful purposes for which we need money whether it be the insurance or the life insurance or the national savings. I would like to say, each of these has been contributing its humble mite in the larger task of national development and for building up a stronger India which thinks not only of the urban masses but very much more of the rural areas and which thinks of the common man as a whole and which has tried to implement the policies which have been enunciated recently in the 20-point economic programme. The very concept for which insurance was nationalised and much earlier life insurance was nationalised and one of the main objectives was that the regional disparity must be obviated to the maximum extent and the policy holders' money should not only yield the maximum return but at the same time, it should subserve the common man's interest. We find according to the investment pattern of the LIC, a large proportion of the money has been phased out in such a manner that either through the central government securities through the Central Government securities much of the money, really goes in building up the basic sections which are necessary for the total economy as a whole. Therefore, we help irrigation, power, or housing or any of these schemes aimed to help people in the rural areas. So, it has been the endeavour and constant endeavour of the LIC that more and more money goes not only to these traditional things but also non-traditional things and mostly to the rural sector which has great potentialities and that way a larger amount of money has been put into the 20-point programme recently.

Without taking much time of the House, I would like to point out some of the recent achievements though I am very much aware of the shortcomings. I think we have to see these things very carefully wherever the difficulties lie, wherever some anomalies lie or wherever delay lies either in claims or in some other things, we have to sort them out and see that the service is improved. By and large, we see that the number of policies now is much greater than it was sometime back and because of the acute inflationary trends sometime back there was a set back last year, but with the proclamation of emergency, there is a greater discipline all round the country, there is a greater punctuality and a greater determination and with the co-operation of all involved we find that there has been a reduction in the expense ratio and as such, I think there has been an overall improvement. The number of policies both individual and group has gone up and the very fact that the group insurance now covers more than 11 lakhs of people, people who really belong to the weaker sections, is itself a service and it really shows how the savings of the people can really be utilised for the benefit of the common man. Much of these policies embraces those who are in hazardous professions and also members of the Armed Forces. The new Grihalaxmi policy was started last year, thanks much to the imagination of our Finance Minister and the LIC itself.

We find that the International Women's Year saw the bringing in of another new policy which will cover non-earning women who have to fall back upon bad days in the absence of their husbands who, unfortunately are no more sometimes. Grihalaxmi Policy will also come to the succour of the needy class of people—widows, ladies in the old age, when they reach 55 and above. This is in the form of Annuity scheme and, therefore, I think there should be benefit from it.

[Smt Sushila Rohatgi]

There has been rise in D A in the last couple of years. Thank God, it is no more now. We find it is not possible to increase bonus. For some time it has been made stagnant. Sometimes, Members do ask very legitimate questions, why there should not be rise in bonus or reduction in bonus.

**SHRI R S PANDEY** Taking into account the commercial rate of interest, you are giving Rs 17/ per thousand in order to make the policy more attractive. If you make it attractive by offering more profit, it will produce wonderful result.

**SHRIMATI SUSHILA ROHATGI** This is the point which I am stressing. The hon member has caught the point. I am always open to any suggestion that the hon members may throw and it is entirely our endeavour that we should make the policy more attractive. We have also to see that the premium is also reduced. This will make it more attractive. Since emergency we are glad to note that there has been reduction in expense ratio and we think by and by there will be better days for the LIC policy holders.

On 31-3-1975 total amount for Housing stood at Rs 410 crores. Indirectly, it also flows in various channels. With the vigorous drive that has been made recently to cut down the claims and to remove delays etc we find that economy has been brought to a certain level. I think with all these factors, there will be better future.

About GIC only, a couple of years back 100 insurance companies were taken over many of them not Indian. It took a little time and it may have taken a little longer for rationalisation of pay scales and service conditions. Now things have started doing well. This year it has shown very good profit. In a couple of years it may speak volumes for the Corporation. As such the main concern of the Government at present is how the GIC can expand to the Crop Insurance Scheme. This is being studied in great depth and

an institute in Lonewala, Maharashtra, has been given this task. As it is, 7 schemes have already been taken up under Crop Insurance, mostly wheat, potato. We find there are other States like UP who want it in Sugar Cane, Himachal Pradesh wants it in apple. We are awaiting a report in this which will give us sufficient insight and a comprehensive picture as to how to make it at a wider & viable scale.

Another feature which speaks well for the GIC is the recent introduction or expansion of the Cattle Insurance Scheme. I think this is on a very modest scale. Personally, I feel, there is much scope for it. The income was fixed at Rs 1 crores. This has been accepted and we are at a stage that we can take it up at a much faster pace.

Another policy which GIC will be inaugurating on 31st of this month for the poor persons Janta Accident Policy. Though we have already a policy like this we find in this that the premium will not only be less but the benefits also will be more. In case of any accident or death or loss of eyes or limb, God forbid, in case of insurance for Rs 10 000 for the loss of one limb it will be in a graded way it will bring some relief to the commuters or those who go by buses and other things in the streets. These are some of the attempts and even on the Agriculture side we find pump sets are also insured. Rs 60 a year as premium can be paid on a set costing Rs 1500. This has already made an indent on the rural economy.

These are some of the steps to see that our insurance money that is being used is utilised for the common man and with the bias on the rural areas.

Apart from that, Sir, we find that much of the money also goes even into the G I C, in other words, for business, because earlier it was confined mostly to the urban and to the affluent section but with the focus on the non-traditional items the other aspect is also not suffering and I am happy to tell the House that the reputation or image built by the G I C is not only

applauded here but it is being applauded even abroad. At a recent session of UNCTAD we have received good comments from them, especially in the Fire Protection Week or Seminar that was held in Bombay recently which I personally attended. It was attended by many people from outside with good experience. Therefore, insurance education, insurance facility and insurance knowledge in general in India have been appreciated even by people outside. The money which comes from the policyholders is really attempted to be put in the right channels and therefore I would like to draw the attention of the House to this point. Of course there may be some shortcomings and we may be going slow. We do want to go much faster and especially in regard to the Crop Insurance there are many factors to be taken into account and once this report comes out I hope we will be able to make decision on those lines.

About small savings, I wish to say this. It is called 'Small Savings' only in name but its content is something very big. Now, I would like to pose one question on this. At a time when there was raging inflation, when there were refugees of about a crore in the country, when there was drought, in the fourth plan, against a target of Rs. 789 crores the small savings movement was able to collect Rs. 1384 crores. Therefore, I am saying, this is the fantastic importance of this movement. The only thing is, people are not giving due attention. With only 7 per cent of the population being covered by this scheme we were able to collect so much. Therefore my humble plea to the Members of the House who represent the country as a whole is this that during the course of their addresses from various platforms and meetings, whichever community they address, if they could just highlight the importance of this movement which is known as the savings movement I think this will be one of the biggest resource mobilisation in our country also.

We have a strength of 10 crore of students in the country right from the secondary stage to the university stage and if only each of the student could collect one rupee a month we can make a tremendous success. I know with the subsistence level, poverty line etc., they cannot do it and about 40 per cent might find it very difficult. But there is also the upper strata who can easily save Rs. 5 a month and the average could work out to one rupee a month. I am sure it will easily fetch Rs. 100 to Rs. 120 crores a year which will come to the exchequer which could be used for development purposes of this country. This is one appeal I would like to emphasise. This is one way of raising our resources and this is one way in which our resources could be mobilised and harnessed for use in the priority sectors. With these words I close.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandl-wash): Mr. Chairman, Sir, perhaps this is the only budget after John Mathai's Budget that deserves congratulations. All sections of the people in this country have complimented the Finance Minister for his realistic budget. The Prime Minister has won military victory against Pakistan. She has won political victory against her opponents in the party. Now she is fighting her battle on the economic front and I think she has found a very good field-marshal in Mr. Subramaniam. I have not much time at my disposal and so I am trying to give only points.

Regarding income-tax I am very happy that he has reduced the highest slab from 77 to 66 per cent. I think the richer classes should understand this welcome step and they should have the wisdom now not to avoid any taxes, not to dodge any taxes, but try to bring all their transactions in their books. I would like to draw the attention of the hon. Minister to the necessity to bring in more and more people under the income-tax net. Now lakhs of people who should pay income-tax are not paying it, self-employed

[Shri G. Viswanathan]  
persons, workshop owners, mechanics and so many other people. For this I would like the Finance Minister to see that all the cash transactions should be reduced to the minimum and the entire transactions are done through cheques and drafts. Then only the income of the individual could be found out.

For this we will require more banks. I was fortunate enough to hear the Minister of State, Shri Pranab Kumar Mukherjee. He was telling us that the rural banks are going to come. The question is 'When?' As early as possible either you should open the rural banks or open the branches of the commercial banks in the rural areas so that the people in the villages can be compelled to have their dealings in cheques and drafts and not in cash. Only then you can widen your tax net. At present—because of certain measures to save the debtors in the rural areas—the rural credit is completely frozen. I want the Finance Minister to take urgent steps to provide credit to the rural people. Although I do not have much faith in cooperative banks, even the cooperative banks are not giving jewel loans. I want the commercial banks to serve the people in the rural areas.

Again talking about the nationalised banks I want to know from the Minister as to why those banks which have crossed the Rs. 50 crore limit have not been nationalised. We had laid down the policy that those banks whose assets cross the Rs. 50 crore mark will be nationalised. I want the Government to take immediate steps to nationalise all such banks and afterwards the Act should be so amended that in future any bank which crosses the Rs. 50 crore mark may be automatically nationalised just by an executive order and you need not have to come before the House for that.

As far as the bank loans are concerned I am pained to see that the industrial sector corners about 57 per cent of the bank loans and the agricultural sector gets only 9 per

cent. I think the Finance Minister and his able deputies should concentrate on this and at least one-third or one-fourth of the bank loans should go to the agricultural sector.

As far as the food front is concerned we are in a very happy position this year but as far as Tamil Nadu is concerned Government has stopped procurement. There are a number of farmers who want to sell but there is nobody to purchase. The Food Corporation of India or the State Civil Supplies have purchased grains but there are no storage facilities and you can find thousands of tonnes of food-grains lying on the roads. I want the Government to take immediate measures to create storage facilities in the country so that we can build a heavy buffer stock.

The relief which the Finance Minister has given in many of the excise duties and other sectors has really given relief to the common man and especially the middle-class. There is a criticism that this concession should not have been given. I think, Sir, we have slowly moved our economy and we should reach the 'take-off' stage so that the poor class may slowly become middle-class. No doubt, this budget is aiming at the accelerated growth of our economy and I am happy that this year our growth rate has gone to 8 per cent. I hope next year when the budget is presented, we will be one of the few countries in Asia that will compete successfully with the other countries of the West as far as economic growth is concerned.

MR CHAIRMAN I want to make a request: I have got before me a list of 20 more hon. Members and if everybody took only five minutes, more could be accommodated.

SHRI M. C. DAGA (Pali). The budget takes six months to prepare and you want us to speak only for five minutes? How can one speak for five minutes on a budget which takes six months to prepare?

AN HON. MEMBER: At least ten minutes each.... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : We are already short of time ; let not even this available time be wasted on this matter. I was only giving an indication to the House, which was already given, that hon. Members may confine their remarks strictly to points. Unless hon. Members co-operate, I will not be able to complete the list.

**श्री नागेश्वर द्विवेदी (मजदुरीशहर) :**

सभापति महोदय, मैं इस 1976-77 के सामान्य बजट का स्वागत करता हूँ और वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद यह पहली बार देखने में आया कि किसी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगा बल्कि कुछ मामलों में छूट ही दी गई। कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए और बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए जिसकी वजह से पिछले वर्षों में काफी परेशानी किसानों को हो गई थी, विशेष ध्यान दिया जा रहा है और भूमि की सिंचाई की काफी व्यवस्था की जा रही है। उर्वरक के मूल्य में भी कुछ कमी का संकेत दिया गया है जिसका हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। लेकिन इस सिलसिले में एक शंका पैदा हो गई है। आम तौर से किसानों में चर्चा रही है कि अभी तक सरकार ने अन्न के भावों का निर्धारण नहीं किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे चल कर जिस मूल्य पर आज तक किसानों का गल्ला लिया जा रहा था जो वैसे ही उनकी समझ से कम दाम था, कहीं उससे भी कम दाम न किया जाय, इसकी बड़ी भारी शंका पैदा हो गई है। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि किसानों का लागत मूल्य देख कर वीज का दाम, खाद, सिंचाई, जिसका रेट पिछले दिनों काफी बढ़ा है और मजदूरी का मूल्य, यह सब कुछ देख कर अगर मूल्य निर्धारित किया जाय तो उससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। अन्यथा हमने देखा है कि बहुत से किसानों

ने गेहूँ का बोना कम कर दिया है, दूसरी खेती की तरफ वह झुके हैं।

इस साल हमारी तरफ आलू का उत्पादन अच्छा हुआ लेकिन वह इतना सस्ता जा रहा है कि पांच किलो, छः किलो प्रति रुपये की बिक्री हो रही है। यद्यपि सरकार ने घोषणा की कि वह 45 रुपये क्विंटल तक आलू खरीदेगी लेकिन यहां कहां हो रहा है और किस किस प्रकार के आलू की खरीद हो रही है इसकी जानकारी नहीं लगी। आम तौर से हमारे यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाजार में चार पांच किलो प्रति रुपये आलू बिक रहा है। इस तरह से किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है बल्कि उनको एक निराशा सी हो रही है। असल में अगर किसान सुखी नहीं रहेगा, किसान की हालत अच्छी नहीं रहेगी तो देश की अर्थ व्यवस्था पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार को इस बात पर ध्यान देना ही चाहिए।

आशा की गई है कि रबी की फसल अच्छी होगी। देखने में रबी की फसल जैसी थी उससे बड़ी भारी आशा थी लेकिन इस बीच से ठण्डा हवा ऐसी बही है कि जिसने देखते देखते फसल को सुखा दिया है और इसका असर फसल पर पड़ेगा। देखने में चाहे भले ही लगता हो कि पैदावार अच्छी हो रही है लेकिन खलिहान में उस तरह अन्न की पैदावार नहीं मिलने वाली है जैसी कि उम्मीद की जाती है। इसलिए इस पर भी हमें बड़ी भारी आशा बांध करके ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अन्न का उत्पादन बहुत हो रहा है और उससे हम बहुत आशान्वित हो जायं।

एक बात जरूर कर्ता चाहता हूँ कि अपनी गल्ले की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सरकार बाहर से गल्ला मंगाती थी और अब काफी भण्डार अन्न का अपनी

## [श्री नागेश्वर द्विवेदी]

आवश्यकता के लिए बना हुआ है। जगह जगह गोदाम बन रहे हैं, जगह जगह खरीद भी हो रही है। मेरा निवेदन है कि अगर सरकार किमान से उसके लगान के रूप में, मिचवाई के रूप में उर्वरक के दाम के रूप में गल्ले की उगाही करती तो किमान को भी लाभ होता, किसान को भी आसानी होती उसे भुदा करने में और सरकार को गल्ला संग्रह करने में भी कं ह परेशानी नहीं होनी। सारी मशीनरी सरकार की काम कर रही है लेकिन पना नहीं सरकार का ध्यान दम तरफ क्यों नहीं जा रहा है? सदन में इस तरह की बात उठाई गई और और भी बहुत से लोगों ने इस तरफ ध्यान दिलाया। अगर भण्डार बनाना है, गल्ला खरीदना है और विमान में ही खरीदना है तो फिर क्यों न किसान में जो कुछ वसूल किया जाये वह गल्ले के रूप में ही लिया जाये ताकि किमान को भी आसानी हो और सरकार का भी मंगल करने में मन्दिवा रहे। इस प्रकार अच्छी तरह से भण्डार बनाया जाये। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे और इस बात की व्यवस्था करे कि किमान में जा कुछ लिया जाये, लगान के रूप में या किसी दूसरे रूप में देना हो, वह गल्ले के रूप में ही लिया जाये।

बिजली के रेट तो बढ़ाये गए, सिंचाई के रेट भी बढ़ाये गए हैं जिससे किसान के लागत खर्च में बढ़ती रही हुई है और उसके हिमाब में, जो सरकारी रेट तय हुआ है, किसान को कम कीमत मिलती है। इस बात पर सरकार चाहे और किसी दृष्टिकोण से विचार न भी करे लेकिन सरकार के पास बहुत से फार्म हैं जहां पर अच्छा उत्पादन किया जाता है, बड़े बड़े विशेषज्ञ वहां पर हैं वहां पर लागत खर्च निकाल लिया जाये और देखा जाये कि अनाज का क्या भाव पड़ता है और फिर वही भाव किसानों के लिए तय कर दिया जाये। जैसे न तो किसान उस तरह से बेहतर कर सकता है

और न उतनी सुविधायें ही उसके पास हैं जिससे उस सीमा तक वह अन्न का उत्पादन कर सके फिर भी यदि इस प्रकार से अन्न का भाव तय कर दिया जावे तो किसान को संतोष होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय बैंकों के द्वारा सहायता देने की बात कहीं गई है लेकिन अनेक कारणों से इसका लाभ अभी तक किसान उठा नहीं सके हैं। मैं चाहूंगा सरकार एसी स्थिति पैदा करे जिससे वास्तव में किसान इन बैंकों का लाभ उठा सकें और महाजनों के बांगुन से छुटकारा पायें।

किसानों की आय का बहुत बड़ा हिस्सा बैल खरीदने में खर्च होता है क्योंकि अभी सब जगह ट्रैक्टर नहीं हैं। जो ट्रैक्टर हैं वह बड़ बड़े होते हैं। इसलिए छोटी कोमन वाले ट्रैक्टर बनाये जायें जो कि छोटे छोटे किसानों के लिए, जिनकी होल्डिंग्स छोटी होनी जा रही हैं, उपयोगी हो सकें।

इस बात की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी तक ज्यादातर काम बैलों से लिया जाता है। मैं देश के और हिस्सों की बात तो नहीं कह सकता लेकिन हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह हालत है कि अगर बैल मर जाता है तो आम तौर पर जो पहले मुर्दा जानवर उठाते थे उन्होंने उठाना बन्द कर दिया है। इसका परिणाम यह है कि मर जानवर इधर-उधर फेंक दिए जाने हैं जिससे एक तो गन्दगी पैदा होती है और दूसरे हमारे देश में बनने ही जो इतनी जरूरत है और विदेशों में भी बनना मेजा जाता है उसका मुकसान हो रहा है। इस सम्बन्ध में सरकारी स्तर पर कोई व्यवस्था होनी चाहिए ताकि

उसका लाभ किसान को भी मिले और जो हमारे यहां चमड़े का नुकसान हो रहा है उसको बचाया जाये।

मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास तौर से सुल्तानपुर, जौनपुर और प्रतापगढ़ जिलों के बारे में कहना चाहता हूँ कि वहां पर कोई नये उद्योग-धंधे नहीं खुले हैं। इस क्षेत्र की आबादी बड़ी घनी है और उसका दारोमदार खेती पर ही है। चाहे मजदूर के रूप में, छोटे छोटे काष्ठकार के रूप में लोग अपना गुजारा करते हैं या फिर नौकरी चाकरी के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं। आजकल नौकरी की हालत यह है कि लोग कलकत्ता और बम्बई से नौकरी छोड़ कर चले आ रहे हैं। ऐसी हालत में जबतक उस क्षेत्र में छोटे और मध्यम दर्जे के नये उद्योग-धंधे खड़े नहीं होंगे तब तक काम नहीं चल सकता है। इस तरह का कुछ काम शुरू भी हुआ है लेकिन जौनपुर, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ उससे बिल्कुल वंचित है। इस बात को तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। बहुत से ऐसे पेड़ हैं जिनके बीज से तेल निकाला जाता है और वह बड़े काम का होता है लेकिन उसको उपेक्षा हुई है। उसको तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसकी तरफ भी देना चाहिए।

सरकार ने बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक उन्नति का जो प्रयास किया है उसमें भूमिहीनों को जिनके पास निवास नहीं है भूमि दी जा रही है। खेती के लिए भी उनको भूमि दी जा रही है। शराबबंदी के लिए बारह सूत्री कार्यक्रम बना है लेकिन उस कार्यक्रम पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

यहां शराब का खूब प्रचार हो रहा है। यह ठीक है कि सरकार को इससे कर के रूप में कुछ आमदनी हो जाती है,

लेकिन शराब पीने वाले इस तरह का अनाचार, झगड़ा फिसाद करते हैं कि उन से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए पुलिस का प्रबन्ध करना पड़ता है। इस लिए आप शराब बन्दी की दिशा में अधिक प्रयास करें तो इसमें सन्देह नहीं की आमदनी में जरूर कुछ कमी होगी, लेकिन देश में अमन और शान्ति कायम रखने में जो खर्चा होता है, उसमें जरूर कमी आ जायेगी।

एक बात में बेरोजगारी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ—इसमें सन्देह नहीं कि सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन जो हमारी शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा का केवल यह परिणाम निकला है कि लोग शिक्षित हो जाने के बाद खेती के या दूसरे काम नहीं कर सकते, वे केवल नौकरी कर सकते हैं या उन की नौकरी करने की आवृत्त पड़ जाती है। इस कारण से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि नौकरी मिल नहीं पाती है। ऐसे लोगों को काम पर लगाने की कोई ठोस योजना बनाई जानी चाहिए। ऐसे पड़े लिखे लोगों को काम न मिलने से वे गलत रास्तों पर जा रहे हैं, आप देखेंगे कि बहुत सी चोरियाँ और डकैतियों में पड़े लिखे लोग पाये गये हैं। इस लिए बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को ठोस उपाय करने चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ।

DR. MAHIPATRAY MEHTA (Kutch) : Sir, generally the budget is the reflection of the fiscal policy of the government, i.e. the economic policy prevailing in the country. We know

[Dr. Mahipatray Mehta]

since independence we are following a policy of mixed economy in this country. Today everybody is saying that it is a very good budget, but it has to remain consistent with the policy of mixed economy, which is the basic policy of the government. The test of the cake is in the eating. I ask the Finance Minister, after 23 years of independence, where has it led us to? Has the percentage of people living below the poverty increased decreased? Has the percentage of people selling their blood and body for their maintenance increased or decreased? Everybody is praising the budget, but where does it lead to?

It is said that the plan outlay has been increased by 31 per cent. It is very good investment, but what about the distribution of this outlay, which is most important? In the fourth plan, Rs 42,000 crores were invested for development out of which Rs. 33,000 crores or 80 per cent went to the urban areas with big industries which give 8 per cent of our national income and 10 per cent employment whereas only Rs 9,000 crores or 20 per cent went to rural areas which give 80 per cent of our national income and 50 per cent of the employment. There is so much increase in generation of electricity, but what about the distribution? 80 per cent of it goes to urban areas and just 20 per cent to rural areas. We hear everybody on the treasury benches shouting about the rural areas. I would like to ask the Finance Minister: what is the distribution of the 31 per cent that has increased the plan outlay? We are taking measures, I do not doubt that. But at the same time, we shout at the top of our voice that we want to reduce the disparity, we want to narrow down the gulf between man and man in India. Does this Budget lead us anywhere? Sir, this Budget, as I told you, is basically faithful to the mixed economy that is prevailing over here. I support this Budget because it is faithful to the policy. I will give you one example. In 1973-74 the textile industry was

asked to produce standard cloth. They did not produce anything. They paid their penalties. But what was their profit? Their profit was Rs. 83 or 87 crores. Nobody talked to the textile industry as to what they should do, but the Government increased to double the price of the standard cloth. So, the ultimate motive to give cheaper cloth to the people was marred. Similarly, look at 1973-74. We were giving development rebate. The Finance Minister, Mr. Chavan, over here declared that that was abolished. But next year, along with the development grant, depreciation allowance was given and thus Rs. 35 crores were just given to them as gift to these people. This year also plenty of relief is given to them. This thing goes on.

If we really want to change, as it is called fight against economy of India two steps, according to me, will be just sufficient. India's real wealth is its manpower. How many man-hours we are wasting today? Crores of rupees worth of man-hours we are wasting daily and not per year or anything. Unfortunately, unemployment increases. Why not divert our economy so that compulsory employment should be the main thing and every able-bodied man must be utilised for development purposes. It will have social advantage also. Then, smuggling will go away, begging will go away and prostitution will go away. If every man has to work, it will give more production and more development. China has shown us the way. It is a phobia to us if we speak about China. There was no money. It was the poorest country the world has ever seen. On top of it, they were opium eaters. Mao has said only one sentence: "Give me the multitude of the man and I will revolutionise China: I will give China the bread it want". We are not utilising our man power, that is the main difficulty.

After manpower, second is water—river water. What is the plan of distribution? How much river water we are utilising? China is utilising 66 per cent of their waters but we are utilising only 10 per cent. I come from an



area which is absolutely drought stricken. I know the pangs of the drought; I know the difficulties of the people and that is why I say; why Narmada water is being wasted? Thousand of canals of water is being wasted daily.

Emergency is there. It has brought wonderful results. Here is our leader who is very dynamic. She has taken all possible steps today. Why not the machinery, the Finance Department, should go and suggest that this manpower should be utilised and that water should be utilised?

Now, the last but not the least thing. Why do not you confiscate gold? Why do not you stop public circulation of the gold.

Only 37 lakhs of people pay income tax today. In India, only 37 lakhs of people, out of a population of 60 crores—not even  $\frac{1}{2}$  per cent pay income-tax. How many people will be affected? All the problems relating to inflation will be solved within 24 hours. Government can take all the money that it wants. Here are heaps of money. Government should take them. These are the only two steps. The disease is a very serious one. In India, people below the poverty line are gradually increasing in number. What are the measures taken? I was shocked to learn that the Bihar Government has passed a law saying that the accessories and parts required for the industries located in that State would be used only which are maintained by the factories located there. I want to ask the Central Government: do the public sector projects located in Bihar, belong only to Bihar? They belong to the whole of India. They can be used for the benefit of the whole of India. Similarly, I am shocked at the theory that only the sons of the soil should work there. It is a parochial outlook. Lastly, about textiles. The excise duty on the printing made on clothes has been increased, from  $7\frac{1}{2}$  per cent to 12 per cent. I think that somebody sitting somewhere in the Secretariat has got a naughty idea about it. They

think that rich people wear clothes having more of colour in them. Contrary is the case. The more gaudy the colour of the cloth is, more will the poor people wear it. Moreover, who run these factories? In some areas one or two persons print on the cloth. They just sell it; Government have increased the duty on such clothes. On the other hand, they have given relief on clothes made for rich people who make huge profits.

SHRI M. C. DAGA: Rajasthan is also affected.

DR. MAHIPATRAY MEHTA: Yes, It is a home industry. It is the only small industry which has been subjected to excise duty.

MR. CHAIRMAN: Dr. Mehta, please wind up.

DR. MAHIPATRAY MEHTA: I am just winding up. This is political budget. When Gandhiji wanted to fight the British, he sought cooperation from everybody. We in India want to fight reactionary and fissiparous tendencies. I, therefore, support this budget and appeal to everybody to stand hind it. All are happy. We will be able to remove these fissiparous tendencies.

श्री अक्षरनाथ विश्वकर्मा (धरमपुर) :  
सभापति जी, जो बजट इस सवाल का पेश हुआ है यहाँ पर सभी सदस्यों ने उसका समर्थन किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश में इमर्जेंसी के बाद जो एक तरह का अनुशासन पर्व शुरू हुआ उसके अनुकूल बिल्कुल यह बजट है।

हमें इस बात की ख़शी है कि पहले जो हम यह महसूस करने थे कि इकोनॉमी पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका है, आज इस बजट से ऐसा महसूस होता है कि हमारी इकोनॉमी पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है और वह पूरी उसके ग्रिप में है और हमारे जित

[श्री अमर नाथ विशालंकार]

मंत्री जी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं।

हमारा देश पहले इन्फ्लेशन का शिकार था और दूसरे देश भी इन्फ्लेशन के शिकार हैं लेकिन आज हमारे देश ने इस पर काबू पाया है और आज वह स्थिति नहीं है जोकि पहले थी। आज बहुत सी चीजों के, जोकि ग्राम लोगों की चीज हैं, दाम गिर रहे हैं। यहां पर जो ब्लैक मार्केट चलता था और यह कहा जाता था कि एक ओपन मार्केट है और दूसरा ब्लैक मार्केट है, उस ब्लैक मार्केट का कन्ट्रोल आज खत्म हो गया है और आज ब्लैक मार्केट हमारी इकोनोमी को कन्ट्रोल नहीं करता है बल्कि आज गवर्नमेंट के हाथ में पूरा कन्ट्रोल है। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है।

हमारे विरोधी दल के कुछ भाइयों ने सुबह कहा कि बहुत से लोग अन्दर हैं और बाहर हैं। कोई अन्दर है या बाहर, यह सवाल नहीं है। देखना यह चाहिये कि ग्राम जनता खुश है, जनता सन्तुष्ट है या नहीं है। जनता से आप बातें करें तो आपको पता चलेगा कि जनता सन्तुष्ट है कि हमारी प्रधान मंत्री ने देश में ऐसा युग आरम्भ किया है जिस में एक गरीब आदमी दुखी आदमी महसूस करता है कि उसे भी गहल मिलने वाली है उसके दिन भी फिरने वाले हैं, उनके भी भले दिन आने हैं और उसके लिए प्रयत्न हो रहे हैं। ठीक है कि एक दम तमाम दुख दूर नहीं किए जा सकते हैं, तमाम धातू एक दिन में पोंछे नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिस दिशा में हम आ रहे हैं जिस तरह से तेजी

से प्रगति कर रहे हैं, हम लोगों के अन्धे दिन भले वाले हैं जो एक नया युग आरम्भ हुआ है उसके अनुकूल में समझता हू कि यह बजट है और इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ।

यह ठीक है कि कीमतें कुछ घटी हैं। लेकिन और भी कुछ बातें हैं जिन की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके लिए ज्यादा प्रयत्न होने चाहिये। ग्राम लोगों के उपयोग की चीजों के दाम कम होने चाहिये। कुछ के कम हुए हैं लेकिन कुछ की कीमतें बढ़नी भी जा रही हैं। आपको देखना चाहिए कि कौन सी शक्तियों के कारण ऐसा हो रहा है। माल की कीमतें कुछ बढ़ी हैं, प्याज की बढ़ी हैं, फल की, ईंधन की, पावर की बढ़ी हैं। ये चीजें ग्राम लोगों के इन्वेन्शन की हैं। इनके दाम भी कम होने चाहिए।

यहां यह मसाल उठा है कि बजट मध्यम वर्ग या नीच वर्ग वाले वर्ग या छोटे आदमी को राहत कम अनुपात में दी गई है और जो ज्यादा धनी वर्ग है उसको राहत ज्यादा अनुपात में दी गई है। मुखर्जी साहब ने इसका उत्तर दे दिया है। उनसे मैं कुछ-कुछ सन्तुष्ट हू। लेकिन एक बात को फिर से देखना चाहिए। उनको जो राहत दी गई है उसका एक कारण यह हो सकता है कि पहले बने वर्षों में हमारा जो इनकम टैक्स लगाने का तरीका था उसके अन्दर उन पर ज्यादा रेट से लगाया गया हो और नीचे वालों पर कम रेट से। अब चूंकि उनको ज्यादा कुछ कर्सेशन दिया गया है इस बास्ते हमें महसूस होता है कि हमने ज्यादा राहत उनको दे दी है और नीचे वालों को कम दी है हाकिमिक करने बरकती

का तरीका अख्तियार किया है। लेकिन सबसे बड़ा नहीं है कि उनको ज्यादा राहत दी गई है या कम। मैं समझता हूँ कि हम यह देखें कि वे हमारे काबू में हैं या नहीं हैं। क्या घनी वर्ग गवर्नमेंट की लगाम ढील होने से समर्थता नहीं है? क्या वह पूरी तरह से हमारी कन्ट्रोल में है, क्या गवर्नमेंट के डिजिटल प्लान से वह बहर तो नहीं चला जाएगा? पहले की तरह पूरी और बिल्कुल खुली छूट उमठो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब ऐसी बात नहीं है और इसका सब पुरा यकीन है कि आप ऐसा अब होने भी नहीं देंगे।

वैल्यू टैक्स में भी आपने कमी की है। आपने हिन्द अनाडिवाउडिड फ़ैमली के लिए सीमा का 2 लाख से घटा करके 1 लाख कर दिया है। मैं समझता हूँ कि यह 2 लाख ही रहनी ता अछूत होत न कि कम सघन वालों को ज्यादा राहत मिल सकनी।

इसी तरह से इनकम टैक्स की लिमिट को 8 हजार के बजाय अगर आप 10 हजार कर देने तो ज्यादा अछूत होता उमसे थोड़ी सी गहल मध्यम वर्ग को मिल जाती। अभी भी कीमतों की अवस्था बहुत अछूती नहीं है।

आपने कुछ चीजों में एक्साइज ड्यूटी कम की है। रेफ़िजेशन की बात की गई है टैबल फ़ैम में आपने पाच परसेंट, रेफ़िजेशन के अन्दर 10 परसेंट टी वी में 15 परसेंट कमी की है। टैबल फ़ैम एव मध्यम दर्जे का प्रदमी इस्तेमाल करता है। आपको इस वक़्त चाहिये कि इस में आप ज्यादा राहत देने और रेफ़िजेशन में कम परसेंट। ऐसा आप करते तो ज्यादा अछूता होता। जहा तक रेफ़िजेशन का सम्बन्ध है इस पर अगर आप राहत न भी देते तो काम चल सकता है। जो डीप

फीजर है और जो अकमर इडस्ट्री के यूज में आता है या अस्पतलों में इस्तेमाल होता है उमके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी की छूट होनी चाहिये थी। ये मडीमिन्त में दूसरी चीजों के उत्पादन में इस्तेमाल होने हैं। इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी इस समय बहुत अधिक है। वह अवश्य कम होनी चाहिये।

18.00 hrs.

हमने काफी प्रयत्न किया है लेकिन अभी भी हमारी कूल इकनमी बहुत कमजोर है, उसे मजबूत करने के लिये हमें अभी बहुत कुछ करना है। मैं इसकी तफ़्सील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मध्य बहुत कम है। मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट को भी इस बात की फ़िक्र है।

20-सूची कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने लोगों के कर्जे माफ़ किये हैं जो राहुकार पहले लोगों को कर्जा देने थे वह अब उनको कर्जा नहीं देने है। उमकी वजह से देहत के लोगों को काफी दिक्कत होनी है, यह नहीं होनी चाहिये। बैंकों में कर्जे आदि की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये।

हमने योजना में काफी पैसा बढ़ाया है, लेकिन कोई नये प्रोजेक्ट हमने नहीं बनाये हैं। रेल मंत्री ने कहा है कि हम कोई नई रेल नहीं बढयेगे क्योंकि पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि रोड्स के लिये पैसा नहीं है, इसलिए नई सड़कें नहीं बढायेंगे। अगर हमने ख़या बढ़ाया है और नये प्रोजेक्ट नहीं बनये तो जो कम-से-कम पिछड़े हुए इलाके हैं, उनकी तरक्की में बहुत रुक-बट रहेगी। तो जो रुक्या बढा है, उसका लाभ पिछड़े हुए इलकों को नहीं होगा, इसलिए इस बात का ख़ास प्रयत्न होना चाहिये कि उन पिछड़े हुए इलकों के जो प्रोजेक्ट हैं, उन पर जोर रहना चाहिये।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने शासन के खर्चों में कमी करने की कोशिश नहीं की है। हमारा कास्ट घाफ़ एव-

[श्री अमरनाथ विद्याभलंकार]

मिनिस्ट्रेशन अभी भी ज्यादा है और इन-प्रोपॉजिटेड है, उसमें कमी करनी चाहिये और देखना चाहिये कि हम जनता को अच्छा शासन दे सकें। इस बात का बहुत कम प्रयत्न हुआ है। हमें इसकी तरफ विशेष प्रयत्न करना होगा। धन-यबाद।

श्री स्वामी ब्रह्मानन्दजी (हमीरपुर) : सभापति महोदय, मैं इस बजट को ध्यान में रखते हुये अपने वित्त मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ। आपकी मार्फत मैं सभी से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री कोई रसायन नहीं बनाते हैं, जितना रुपया उनके पास आता है, उसका वितरण करते हैं। सम्पत्ति माने श्रम है और उसे श्रम से पैदा करना होता है।

श्रम की चोरी करके पूँजीपति लोगों ने जो धन अपनी घरों में रखा है, इसको कौन निकाले? अणु कानून बाधक है, तो विधान को बदल देना चाहिये इन लोगों ने करोड़ों रुपये की जो सम्पत्ति रखी हुई है, वह वित्त मंत्री को निकालकर देनी चाहिये, इसमें कौन सी दिक्कत है?

सोना कोई खाने की चीज नहीं है, घरबों और खरबों रुपये का सोना भरा पड़ा है। यह कानून बना देना चाहिये कि जिस आदमी के पास सोना निकलेगा, उसको फाँसी दे दी जाएगी। देखिये मारा सोना आपके पास आ जायेगा।

अभी एक उदाहरण चीन का दिया, वहाँ अफीम खाते थे। वहाँ अफीम खाना एक स्राव जोड़ दिया गया। आप यहाँ एक दम रोक दीजिये कि कोई शराब नहीं पियेगा, कोई तम्बाकू नहीं पिया जाएगा और तम्बाकू की जमीन में खेती की जाएगी।

अमरीका जैसे पूँजीपति मूलक में एक राष्ट्रपति होता है। यहाँ एक प्रधान मंत्री हैं और एक राष्ट्रपति भी हैं। यह बर्बाद क्यों है? इस गरीब देश में राज्य-सभा भी एक यतीमखाना सी बनी है, और आप की काउन्सिलें और परिषदें जो बनी हैं, वे क्या हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या हैं? बकील लोग बार-बार हजार रुपये पैदा करते हैं जब कि मजदूर दिन भर मिट्टी खोदता रहता है, तब उसको 4 रुपये मिलते हैं। तो यह बजट का तमाशा करने रहने से क्या फायदा। आपकी सम्पत्ति का गणनीय-करण कर देना चाहिये। मेरा कहना तो यह है कि अगर ज्यादा रुपया लेकर पूँजी-पतियों से ही सरकार चलाना है तो इन पूँजी-पतियों से बजाय आप डाकुओं को छुट्टी दे दीजिये और कहिये कि वे 50 फीसदी रुपया लाकर जमा कर दें। डाकू लोग इनसे ज्यादा इमानदार हैं। अगर वे डाका डालेंगे तो 50 प्रतिशत आपके घर में रुपया आ जाएगा। पूँजीपतियों से वे डाकू ज्यादा अच्छे हैं।

अपने जमीन की सीलिंग की है, यह अच्छा हुआ। और हमारे गरीब हरिजनों को वो जमीन मिली। लेकिन सवाल यह है कि क्या पैसे व मकान वालों पर जमीन की सीलिंग की तरह कानून लागू किया गया? यहाँ पर जो फौज की फौज मिनिस्टर बैठे हुये हैं, क्या उन पर सीलिंग का कानून लागू किया गया? आखिर इतने मिनिस्ट्रों की क्या जरूरत है। इससे बहुत खर्चा बर्बाद होता है। मैं तो सन्ध्यासी हूँ मैं पैसा नहीं छूता हूँ और केवल भिक्षा से अपना निर्वाह करता हूँ। हाँ, गृहस्थ को खपना चाहिये। एम० पी० को क्या सुविधायें हैं? और बेचारे एम० पी० भी क्या करें? उनके क्या अधिकार हैं? उनके पास एक बरौजा के बराबर भी अधिकार नहीं हैं। वीथ के

सभापति से ले कर राष्ट्रपति तक को, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, क्या अधिकार प्राप्त हैं ? उसके पास कोई अधिकार नहीं है । उनका यही काम है कि निफारियों करते हूँ । उन को अधिकार मिलने चाहिये ।

आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तथा किसी भी अदालत की कोई जरूरत नहीं है । पचायतों, जिला परिषदों, विधान सभाओं और पार्लियामेंट को अदालतों के अधिकार दिये जायें । हम यहां देखते हैं कि यहां पर लोग बैठे बैठे गर्पें मारते हैं । इतने बड़े दिमाग के लोगों को कोई काम दिया जाना चाहिये । उनको अदालतों का अधिकार दिया जाये ।

ये बातें ऊबड़-खाबड़ लगती होंगी, लेकिन अन्त में उन्हीं के अनुसार काम करना पड़ेगा । मैंने कहा था कि जयप्रकाश नारायण को पकड़ो । उस वक्त लोग मुंह बनाते थे । लेकिन अन्त में सरकार को उन्हें पकड़ना ही पडा ।

यह संविधान पूंजीपतियों का बनाया हुआ है । पूंजीपतियों के वोटों से चुने हुये कांग्रेस और राजाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा यह संविधान बना है । वही संविधान अब भी चालू है । आठ साल पहले मैंने कहा था कि इस संविधान को दियासलाई से घाग लगा दो और नया संविधान बनाओ । यह सुन कर लोग मुंह बनाते थे, लेकिन अब श्री गोखले कहते हैं कि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है । पहले पचायतों में पांच मिनट में फैसले होते थे, लेकिन अब हाई कोर्ट में अठारह साल तक फैसला नहीं होता है ।

शिक्षा में सुधार कौन करेगा ? राष्ट्र भाषा हिन्दी क्यों नहीं बनाई जाती ? क्या खूदा करेगा ? आखिर यह सुधार क्यों नहीं किया जाता है । पार्लियामेंट में बैठ कर यह काम दो दिन में हो सकता है ।

उत्तर प्रदेश के लोग बड़े अग्रग्रा हैं । वहां यह अच्छा काम हुआ है कि एक संयुक्त विरोधी दल खड़ा किया गया है । मैं विरोधी सदस्यों से कहना चाहना हूँ कि हमारे विचार के लोग उधर आ जायें और जो लोग पूंजीपति विचारों के हैं, वे उधर रहे । आखिर क्यों हमारे देश को बदनाम कर रखा है ? चीन एक अफीमकी देश था, लेकिन वहां क्रान्ति हुई । इसी तरह रूस में भी क्रान्ति हुई । हमें भी अपने देश के हित के लिए यहां आवश्यक परिवर्तन करने चाहियें । ये बातें ऊबड़-खाबड़ लगती हैं, लेकिन उन्हें करना पड़ेगा ।

शराब पीने वाले न तो गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं और न क्रान्ति के रास्ते पर । लेनिन ने रूस में क्रान्ति की । हम गांधी के अहिंसावादी रास्ते पर चले । तो फिर हम शराब क्यों पीते हैं ? शराब को छोड़ना चाहिये । हमने शराब-बन्दी के लिए धरने दिये हैं और जेल गये हैं ।

राज्य सभा भी पूंजीपतियों की बनाई होगी । जो हार जाता है, उसको वहां रख दिया जाता है । क्यों इसको यतीमखाना बना रखा है ?

धरम सरकार इन बातों को करेगी, तो धरनों रुपयों की मर्यादा बाहर निकल आयेगी और श्री मुखर्जी उसको सब विभागों में बांट देगे फिर कोई शिकायत नहीं रहेगी ।

SHRI D. K. PANDA (Bhanjanagar):  
 "The combined impact of a large budgetary deficit and credit liberalisation could be substantially expansion of money supply. This is the harbinger of inflation. The Finance Minister has obviously opted for 'well calculated risks' instead of hard decisions". So, has been pointed out. So, I want to know whether a statement has

[Shri D. K. Panda]

been made by our Finance Minister; whether a hard decision can be taken on this aspect and whether we can prevent inflation. I am drawing the attention of the hon. Minister through our Chairman.

My first point is, whether we can prevent inflation in future or whether we will simply say, it is a well-calculated risk, or whether we will be able to take some hard decisions about it. Can the hon. Minister give a specific answer while replying to the debate on the General Budget.

Secondly, I want to know whether there is any fundamental change in the ideological concept about income-tax policy. The Finance Minister, five years ago, in his Budget speech said:

“if we are going to make an effective dent on the problem of income inequality in our society, we cannot flinch from deploying increasing the instrument of direct taxes.”

Now, the Finance Minister, Mr. C. Subramaniam and, in support of that, the Minister of State, Mr. Pranab Kumar Mukherjee, has also said the same thing. The more the taxes, the more will be the investment and the more will be collection of revenues. When five years ago there was an uncertain ideological concept and a statement had been made like that, how is it that a change could be made now in that concept? What are the factors due to which a reduction of tax on the rich and monopolists has been made? Why has that concession been given to them?

Thirdly, there is the public sector. We know, in the public sector undertakings, there is a massive and huge investment. That is quite a welcome feature. But we want to know whether the industries which are now sought to be hampered and fostered will get the maximum benefit out of these investments. We welcome massive investments in the public sector.

But we want to know whether the hon. Minister can give a guarantee that the maximum benefit goes to the rural sector and the poor sections, the weaker sections of the society and not to the affluent, the rich and the monopolists.

Fourthly, in order to reduce the economic disparity or inequality or uneven development in the country, I want to suggest one or two things. When we go to the people in our areas, can we say, “Yes, you have got so much relief”? We have absolutely no answer. It is the rich, the affluent sections of society which have got so many concessions. Several concessions have been given in the past and the present concessions which have been given to them are quite in conformity with the policy of drift that has been followed in the last six months. The liberalisation of credit, giving concessions, like, investment allowance of 25 per cent and all that are some of the things. I am not going into them in detail. It has been said that this Budget has a specific role to play to accelerate growth with social justice. What social justice has been given to 62 per cent of the people who mainly depend upon agriculture?

About the 20-point economic programme, out of 20 points, 7 points are entirely meant for the rural poor people. Out of Rs 2,160 crores which are set apart for the entire 20-point programme, Rs. 1,285 crores go to the generation of power. Similarly, Rs 145 crores go to minor irrigation works and Rs. 606 crores go to major and medium irrigation works. This shows that out of Rs. 2,160 crores, about Rs. 2000 crores go towards power and irrigation. That is also a welcome feature. But are you not going to tax the rural rich who are getting the maximum benefit?

Another question that arises is this. Take, for example, Orissa. There, 1,62,000 acres of wasteland have been distributed to the landless people as per the report of the Orissa Government—in spite of several challenges they have said that this is the correct thing, 1,62,000 acres have been distributed to the landless poor. But there are no budgetary provisions to develop those lands by way of cooperative farming, through collective effort. So much of hope is aroused among the rural poor, but there is no allocation in our investment for that sector to develop those lands and also the surplus land—over and above the ceiling—that will be distributed to the landless. As a matter of fact, there is absolutely no credit available. Unless the people get more and more credit, they will not be in a position to develop those lands, they cannot go in for rabi and other crops. Therefore, my point is that, if our attention has to be diverted to the rural sector to regenerate or to have a self-oriented growth of our economy, then certainly we have to develop the rural sector; money has to be invested in those areas.

Then I come to the point of uneven development. Take, for example, the backward States. How can they be developed? We have been uttering mantras saying:

गङ्गे च यमुने च व गोदावरी हरस्वती ।

That means, we view these rivers, the Ganga, the Godavary, the Yamuna, the Cauvery and so on, from the national concept; we treat them as our own, but you do not treat Bihar or Orissa that way. For power generation, there are innumerable projects in Orissa; they are being neglected. We need Rs. 518 crores for the development of medium and major projects. The Central assistance flows to other States, but not to Orissa. We generate all the power at the State's cost, and a major portion of the power 52 per cent. is being utilised for all Central projects. Therefore, Central assistance for power projects in Orissa should be given.

Therefore, I insist that these things should be taken into account, so that the uneven development can be minimised.

श्री मूल चन्द्र झाग (पाली) :  
सभापति महोदय, 15 मार्च, 1976 के दिन एक ऐसी बात होनी चाहिये थी कि हिन्दुस्तान के 22 करोड़ लोग जो गरीब हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं वे यह बात कहते हैं कि हिन्दुस्तान कि आर्थिक नीतियों में एक बुनियादी परिवर्तन आया है और दुनिया यह मानती है कि आपान काल में ऐसा बजट आया कि कुतुब मीनार पर बैठे हुआ आदमी नीचे आ गया और नीचे वाला आदमी ऊपर हो गया लेकिन वह परिवर्तन नहीं आया। हमारे देश में सब बड़ा काम विषमता (डिम्पैनिटी) को दूर करना है। आज दुनिया में महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अमीर और गरीब के बीच का जो अन्तर है वह कम हो। अगर अमीर और गरीब के बीच का यह अन्तर बढ़ता गया तो कभी शान्ति नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे बड़ा काम यह है कि हमें विषमताओं का उन्मूलन करना होगा। यह हो नहीं सकता है जब तक कि ऐसा बजट नहीं आता और अपनी नीतियों में हम परिवर्तन नहीं करते। मैं समझता हूँ गरीब लोग इमानदारी से कहेंगे कि आपान काल होने के बाद भी शान्तिकारी बजट पेश नहीं किया गया। आप देखें यहाँ पर कितना अन्तर है। स्वीटजरलैण्ड में अधिकतम और न्यूनतम मजदूरी में 1 और 6.5 का अन्तर है, अमेरिका में 1 और 25 का अन्तर है लेकिन हिन्दुस्तान में 1 और 200 का अन्तर है। जहाँ इनका बड़ा अन्तर होगा, शान्ति वहाँ नहीं आ सकती। इस लिये इस शीके पर आपका सबसे बड़ा काम यह था कि आप आय और व्यय पर कोई संकुश लगाते जो लोग धन का प्रदर्शन करते हैं, भाषणा प्रदर्शन करते हैं उन पर संकुश लगाते। 15 मार्च को ऐसा बजट आना चाहिये था।

[श्री मूल चन्द्र डागा]

जिससे उन धनवानों के हाथों में शराब की बोतल वहीं एक जाते वे अपने बड़े-बड़े मकानों से नीचे आ जाते। इसलिये जब तक आप खर्च पर रोक नहीं लगायेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये भ्रमीर लोग जो खर्च करते हैं, अपनी धारास-तलबी पर खर्च करते हैं, इसमें परिवर्तन आता तब मैं मानता कि वाकई आपने बहुत अच्छा काम किया है। श्रीमान, यह एक साधारण नियम है—जितना भ्रमीर होगा, उतना उनका विकास ज्यादा होगा। एक भ्रमीर को और ज्यादा भ्रमीर बना दिया, तो वह विकास की और ऊंची मंजिल पर पहुंच जाएगा और जो गरीब है, वह और ज्यादा नीचे रेंगने लगेगा। एक भ्रमीर को ज्यादा कैमिनिटीज मिलेंगी तो वह और ज्यादा भ्रमि बढ़ जाएगा, गरीब को विकास के साधन नहीं मिलेंगे तो वह भ्रमीर पर रेंगने लगेगा। आज हिन्दुस्तान को उस गरीब जनता की हानत को कौन सुधारेगा? मेरे ब्याल में यह ऐमः समय था, समय का तकाजा था, देश का तकाजा था, आज एक क्रांतिकारी बजट आता, जिससे हिन्दुस्तान के पूंजीपति, बड़े-बड़े वकील, बड़े-बड़े डाक्टर नीचे आ जाते, लेकिन भ्रफसोम यह है कि आपने फिजूलखर्चों को रोकने के लिये कुछ नहीं किया।

आप बैंकवर्ड एरियाज को ले लीजिये—आज यहाँ आदिवासी बसते हैं। लेकिन आदिवासियों के जन्म कट गये, आपकी रिपोर्ट बातलाती है कि वहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देना चाहते हैं। सुबहप्रथम साहब ने जो बात कही है—मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाता हूँ :—

"What is most significant is the new physal fiscal thesis propounded by Shri Subramaniam. He tells us that the high rates of income tax and wealth tax do not lead to any

"significant reduction of inequality of income and wealth." But five years ago, the Finance Minister told us just the opposite. He had said in his budget speech: "If we are going to make an effective dent on the problem of income inequalities in our society, we cannot flinch from deploying increasingly the instrument of direct taxes."

इस बात को कोट करते हुये मुझे दुःख होता है। फिजूलखर्च को रोकने के लिये आपने क्या किया? मैं कुछ झाँकते आपने सामने पेश करना चाहता हूँ—हिन्दुस्तान की सरकार ने रेलवे में 50 करोड़ 50 लाख रुपया लगाया हुआ है, जिसमें 16 लाख आदमी काम करते हैं, फिर भी आपने उनको 120 करोड़ रुपया उधार दिया है। दिल्ली ट्रामपोर्ट कारपोरेशन को आपने 27 करोड़ रुपया दिया हुआ है फिर भी उनको 1969-70 में 2 करोड़ 33 लाख, 1970-71 में 3 करोड़ 53 लाख का और 1971-72 में 3 करोड़ 73 लाख का घाटा हुआ। मुद्रा बाजार में 60 लाख रुपये का घाटा हुआ। आपके हर सैक्टर में घाटा हो रहा है। आपने हिन्दुस्तान में जितने महकमें लिये सब घाटे में चल रहे हैं। करोड़ों रुपये की पूंजी नीकर-शाही की दो बातों से जूड़ी हुई है—पूँजीवाद और तानाशाही मनोवृत्तिया। अभी भी ये पब्लिक सैक्टर सर्वेन्ट नहीं हैं, पब्लिक मास्टर हैं, इनको पब्लिक सर्वेन्ट कहने का गुनाह कौन कर सकता है। हिन्दुस्तान में डेवलपमेंट के नाम पर जो फिजूलखर्चों होती है मुखर्जी के साथ, उनके झाँकड़ों को देखें तो एक नफरत सी पैदा होती है। आप देखिये—पंचायतों में क्या हो रहा है, वहाँ कितने आदमी काम करते हैं, उनकी क्या हालत है। हिन्दुस्तान में पंचायतों की संख्या 2, 19, 812 है, जिला परिषदें 201 हैं—इन पर 10 करोड़ रुपया खर्च होता है इन्हारी आदमी निकम्मे बैठे हैं। जो काम एबीएलएन डिपार्टमेंट करता है वही कर



कम्प्यूटरी क्लिपबोर्ड करता है। आप देखें कि कितना इन्फ्लिकेशन आप वर्क है। हजारों, आठसौ गांव बेकार हो रहे हैं। मैं आपको बताऊँ कि हमारे राजस्थान में लोग गांवों में काम करते हैं और बन्दरी बनाते हैं और छाई करते हैं। यह सब काम हाथ से होता है। आपने यह कर दिया कि पाच रंग लगेगे बहू टैक्स लग जाएगा। मतलब यह हुआ कि हाथ से काम करने पर भी उनको टैक्स देना होगा। मेरी मांग यह है कि आप उस पर टैक्स न लगायें। चूंकि अब समय नहीं है, मैं केवल यही कह कर अपनी बात खत्म करना हूँ कि आपके भाषण में परमात्मा जाने कब देश में अममानताएँ खत्म होंगी।

श्री बन्धुलाल बन्धुकार (दुर्ग) सभापति महोदय, बजट खानी जमा और घटा की पुस्तिका नहीं है, बल्कि यह एक मागदर्शन करना है कि देण की क्या समस्यायें हैं और उन को हल करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं। हम में कोई शक नहीं कि बजट में इस बार अन्य मंत्रों की तुलना में कई क्षेत्रों में ग़रत मिली है। लेकिन फिर भी आज जो आवश्यकता है वह यह कि बेरोजगारी का हल निकाला जाय, और खाम कर ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी बढ़ रही है वह इतनी है कि आकड़े चाहे उसमें 50, 60 लाख हों, उस पर मुझे कतई विश्वास नहीं है। जिन गाव की आबदी एक हजार की होंगी वहाँ पड़ लिख लोगों की संख्या 150, 200 होगी जो कि बेरोजगार हैं। अनाप लोगो की तो गिनती क्या। वैसे कहा गया है कि छोटे-छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा जिस से कुछ रोजगार मिलेगा। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता है वैसे मागदर्शन इस बजट में नहीं मिलता है। इस के लिये आवश्यक है कि इस तरह से इन्फ्लेट्रकबर तैयार किया जाए कि ग्रामीण लोगों में जो पड़े

लिखे और अनपढ़ लोग हैं उन को अपने काम खोलने के लिये सुविधायें मिल जायें। उस के लिये वैसे अग्रत्यक्ष रूप से कुछ बार्ने कही गई हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से यह कह दिया जाना चाहिए कि हमारी इस अर्थ-व्यवस्था में जो अभी योजना बनाई गई है एक वर्ष के लिये उस में प्राथमिकता निश्चित रूप से एक तो सिचाई को ही और दूसरी प्राथमिकता बिजली की ही। केवल इन्हीं दो चीजों के लिये अलग में पंचवर्षीय योजना बनाई जाय जिस में हर एक गाव में जहा सम्भव हो सके वहाँ सिचाई की व्यवस्था हो सके। इसी तरह में बिजली की व्यवस्था की जाय। अगर यह दावा की जा सकती है तो गाव के पड़े लिखे लोग खद अपना काम कुछ सकते हैं और रोजगार खोल सकते हैं। लेकिन हम और, जैसा अभी पूर्ववक्ता ने बताया, ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली के मामले में उद्देश्य होनी शायी है, हालांकि पञ्जाब, हरियाणा इस मामले में आगे बढ़ा हुआ है लेकिन जो बड़े-बड़े राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में बिजली की बहुत कमी है। और हम देखते हैं 67,000 गावों में से केवल 6,000 गावों में ही बिजली पहुँची है। तो कैसे बेरोजगारी दूर हो सकेगी? तीन बातों के लिये, बेरोजगारी दूर करने के वस्ते, बड़े पैमाने पर योजनायें बनाई जानी चाहिये—पहली सिचाई की, दूसरी बिजली की और तीसरी ग्रामीण सड़कों की। साथ ही साथ हर गाव में जानवर अग्रिक होने के कारण गोबर बाफ़ी पंदा होता है। और देशों में गोबर गैस का बाफ़ी उपयोग किया गया है, लेकिन हमारे देश में अभी बसा नहीं हुआ है। कह रहे हैं दो माल से, और योजना मंत्रालय में भी इस बात की खर्चा है कि गोबर गैस का ज्यादा उपयोग किया जाय। लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया है। वस्ते में गोबर गैस को सरकार की

[श्री चन्दु लाल चन्द्रकार]

और से हर एक गांव में पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिये। और आज तो आवश्यकता इस बात की है कि एक आदमी अपने ही घर के गौबर से गैस न बनाये, बल्कि सम्पूर्ण गांव के गौबर को एक जगह इकट्ठा करके गैस बनाई जाये और हर एक घर में गैस को सप्लाय किया जाय। अगर ऐसा हो जाय तो न केवल खाद की समस्या हल हो जायगी, जो कि आज हम रसायनिक खाद बनाने के लिये करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, उस में भी बचत होगी। इस से खाद भी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो हमारे देश में जंगल कट रहे हैं, उन की रक्षा हो सकेगी।

इस के साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज गांवों में बेरोजगारी है और इस में कोई शक की बात नहीं है कि अनाज का उत्पादन भी सारे क्षेत्रों में बढ़ा है लेकिन साथ ही साथ यह बात भी सही है कि उत्पादन करने में जो व्यय होता है, वह भी बढ़ा है। गांवों में बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं, सिंचाई की दरें बढ़ा दी गई हैं, रासायनिक खाद का दाम भी बहुत बढ़ा हुआ है और कीटाण नाशक औषधियों के दाम भी बहुत बढ़े हुए हैं। इस तरह से उत्पादन व्यय बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मेरा सुझाव यह है कि प्रति एकड़ उत्पादन व्यय कितना हुआ है उस की जांच करने के बाद और किसान को कितना लाभ मिलना चाहिए यह तय करने के बाद उन चीजों के दाम निर्धारित करने चाहिए। आज चाहे वह अनाज हो, चाहे सब्जी हो और चाहे फल हों, हरेक की कीमत कास्ट आफ प्रोडक्शन, उत्पादन व्यय को ध्यान में रख कर निर्धारित होनी चाहिए। आज जबकि और चीजों के दाम, चाहे वे छोटे-छोटे कारखाने तैयार कर रहे हों या दूसरे कारखाने, कास्ट आफ प्रोडक्शन को देख कर निर्धारित किये जाते हैं। इसी तरह से अगर आप किसानों की उपज के दाम भी तय करें, तो उन की शिकायत

दूर हो जायेगी। जब तक यह चीज नहीं की जाती है, तब तक ग्रामीण क्षेत्रों के साथ आप न्याय नहीं करते हैं। मैं अपने वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि उत्पादन व्यय जो बढ़ा है, उस को ध्यान में रख कर किसानों की उपज के दाम तय किये जाएं।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ। हमारे यहां जो राइस मिल्स हैं, उन में 40, 45 हलर्स होते हैं। इन हलर्स से धान में से केवल 52 परसेन्ट चावल निकलता है। अगर एक किंटल धान होता है तो उस में केवल 52 किन्तो ही चवल निकलता है और जो बड़े मिल हैं उन में 100 किन्तो धान में से केवल 65 किन्तो चवल निकलता है। अभी बरी सेक्टराग्राम से एक छोटी सी—उसे यंत्र तो नहीं कह सकते—चीज निकली है जिसे 'दरिया' कहते हैं। उस में 75 परसेन्ट चावल निकल सकता है। उत्पादन बढ़ाने के अथ-ज्ञाय हमें यह भी देखना चाहिए कि जो चावल पैदा होता है उस का दुष्प्रयोग न हो। आज तो धान से चावल निकालने में बहुत रूढ़ी में फिंज जाता है। इसलिए अगर आप चवल निकालने के लिए 'दरिया' को प्रोत्साहन देंगे, तो काफी मात्रा में चावल निकलेगा। दूसरी बात यह है कि आज चावल को बहुत ज्यादा पालिश कर दिया जाता है जिस से उस का प्रोटीन खत्म हो जाता है। अज दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां इतना ज्यादा चावल को पलिश किया जाता है जितना कि हमारे यहां किया जाता है और इस तरह से उस का प्रोटीन निकल जाता है।

अब मैं गांवों में बेरोजगारी दूर करने के लिए दो नए सुझाव देता हूँ। एक सुझाव तो यह है कि हर दस लाख की अबादी के बीच में एक मशीन-रान एग्रिकल्चरल फार्म होना चाहिए जहां पर हर तरह के अनाज के लिए सब्जी और फलों के लिये नये-नये

तरीके अपनाए जाएं जिस से लोगों को बिलेंस कृत्र मिले और साथ ही साथ कुछ नया रोडेशन जाक कोष हो ।

इसी तरह से हर दस लाख की आवादी में एक मन्दी परपल इन्डस्ट्रियल इस्टेट होनी चाहिए जहाँ पर पड़े निखे लोग काम सीख कर छोटे छोटे उद्योग घों लगाएँ और उन को बी. में कर्ज मिले । इस तरह से दस लाख की आवादी में छोटे छोटे कारखाने अगर खुल जाते हैं और इन तरह की व्यवस्था हो जाती है, तो बेरोजगारी बहुत हद तक दूर हो जाएगी ।

इसका कह कर मैं बजट का समागन करता हूँ ।

**SHRI MALLIKARJUN (Medak):**  
 Mr. Chairman, the current budget with an increase of 31.6 per cent of annual Plan outlay and of a deficit of Rs. 368 crores has been received and welcomed by various cross sections of the society. However, I disagree with the allegation made by my friend Shri Chandrappan that the Finance Minister has presented the budget with the intention of duping the country. He has further said that the budget is going to increase inflation. I totally disagree with him.

The budget lays emphasis on investment and savings. Increase in production in agriculture and industrial sector is indicative of the Government policy to achieve stable economy in this country. In the reconstruction of the nation with the ultimate objective to establish an egalitarian society, the budget plays a great role. This budget is not merely for us who are present here but it gives incentives to the people outside in various sectors of production. Our beloved Prime Minister is utilising every calorie of energy and she is dedicating herself for building up a socialist society where the Government machinery has been actively participating in her new

20 point economic programme enunciated a few months back. It is not merely the administrative machinery which is responsible for achieving this economic objective for the growth of our country. It is the people who are also playing equally responsible role. When I say the people, I mean, particularly the youth. Now, the youth's role has been really appreciable in bringing down the prices. We may say amazingly how youth can play a role in bringing down the prices. Their vigilance and alertness towards the hoarders and blackmarketeers is a clear indication in bringing down the prices, checking the inflation and other factors. Sir, the youth has got tremendous energy. In the past there was lack of channelisation. Now their energies are being channelised under the dynamic leadership of Mr. Sanjay Gandhi. We are fortunate in this, Sir; Mr Sanjay Gandhi, with all his genetic influence and inherent leadership qualities is constructive in looking into the problems of the poor people of the country. He believes in it. He dedicates himself. He has a vision and with that vision if the youth's energies are channelised, properly utilised, I am fully confident, there will be the uplift of the common people of this country and the poor peasants of the country. There could be augmentation in the agricultural production, in improving the rural economy, in industrial production, in increasing the national economy, so much so, to ultimately help in the national economic development.

With all this view, still, Sir, I have my own reservations. The Government has given a good incentive in order to increase the inputs like power, coal and other factors like fertilisers, pesticide and so on and so forth which will help both industry and agriculture. Sir, lack of time is one of the impediments in this august House and I have to just draw the attention of the hon. Minister to some important points. I wish to say something with

[Shri Mallikarjun] regard to agricultural production. I express my feelings whether the agricultural economy is going to be a stabilised one in future or not. Apart from the economic policy which has been evolved along with fiscal policies, economic discipline, as has been mentioned by the hon. Minister is an important factor. All these are linked up with discipline they have got a mutual relationship. Let me re-emphasise on the subject of agricultural economy. Is the Government keenly interested in the matter of improving the economy of agriculture? Take for example, transplantation, weeding, supplying fertilisers and so on, for example, for one acre of land. We have got legislation regarding minimum wages, removal of bonded labour, etc. We all welcome these steps, but the question is, what is produced out of one acre of land? Is it in proportion with the investment of that farmer or not? This is the question. Now, my personal feeling is this. The farmer cultivates a single acre. He has no money left at all after meeting the expenses. In this difficult situation how he is to live is the question. Suppose the Government does not take care of these things; what will happen is this. In future I visualise this in a decade or even before that. Our agricultural economy will be more adversely affected than anything else.

Therefore, Sir, supporting the Budget, I wish to reemphasise this point. The Government must constitute at least a cell to look into the agricultural activities and particularly the policy should be price-oriented. They must see what is the production, how is he going to live, what incentive the Government has to give in order to involve the agriculturist more fully and to improve the economy. To give that incentive, if necessary, Government must come forward with the subsidy to fertiliser and other things.

And, above all, Sir, I think, under the present socialistic structure, it is

very necessary for the Government to think very wisely about the co-operative farming at otherwise we will be a great loser in the future.

**SHRI SHANKERRAO SAVANT** (Kolaba): Mr. Chairman Sir, budget is a fitting culmination to the decade of progress which we have recently celebrated. While congratulating the Finance Minister for presenting a realistic and more or less non-controversial budget, I want to give certain suggestions.

It is contended by many hon. Members—both from this side as well as on the other side—that the disparities between incomes are not going to be removed by the present policy of taxation. I would like to point out that taxation policy cannot cure inequalities of income. Inequalities of income arise from the fact that the instruments of production are in the hands of a few hundred people while the rest of the crores of people have to live on wages. As long as that continues and we continue accepting the mixed economy it is impossible that disparities in income can be done away with merely by taxation proposals. In that connection I would like to request the Finance Minister to see that the lower exemption limit for income-tax is raised to Rs. 12,000, in view of the inflation. This is necessary because we were suffering and are still suffering from a runaway inflation. Therefore, although the incomes have gone up the expenditures have also gone up. Realism, therefore, requires that exemption limit should be raised to Rs. 12,000 per year to give relief to the middle class.

My second suggestion is that in the budget they have made a provision that new buildings with plinth area of 81 sq. metres will be exempted from wealth tax for five years. As a matter of fact a building with a plinth area of 81 sq. metres will normally cost less than Rs. 1 lakh at least in the maffasil. That means there is no con-

cession at all. Therefore, if they want to encourage building activity, they should exempt buildings with plinth area of 150 sq. metres. Then only there will be real concession.

Thirdly, the nationalised banks are not doing the services which they were expected to do to the agriculturists and the village artisans. What has happened is that as a result of 20-point programme so many money-lenders are going out and their place has to be taken only by the nationalised banks. Therefore, they should be asked to give more credit to the agriculturists and particularly to the village artisans and the rate of interest should be much lower than what it is today. The present rate of interest is prohibitive. Further, I would like to say that prices of agricultural produce, viz., rice, wheat, milloes, pulses, etc. are going down but the prices of manufactured goods are not going down proportionally. It is absolutely necessary in the nature of things that the rate of interest should be lowered and that can be done only by the Government by fixing a lowered rate of interest. The present rate of interest which is charged is extremely high and it gets reflected in the cost of production. Therefore, prices of manufactured goods are not coming down as rapidly as the prices of agricultural goods are coming down.

So far as TV sets are concerned their taxes are reduced but it is for the Government to see that this reduction does not lead to reduction in the quality. Government must see that the quality of the T. V. set is at least the same, if not improved. The Manufacturers should not take advantage of only the reduction in the tax. The benefit of reduction should go to the consumer. With these words I support the budget.

श्री देवा उराव (जल तटवर्ग): नवापति मंडोदर, मैं इस बजट का लक्ष्य से समर्थन करता हूँ।

मैं सरकार का ध्यान खास तौर पर चाय बागान के मजदूरों की ओर खींचना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि उन लोगों को प्लांटेशन लेबर एक्ट, 1951 के अनुसार जो सुख-सुविधाएँ मिलती हैं, उन में घर बनाने, स्कूल खोलने और चिकित्सा की व्यवस्था आदि शामिल हैं। इस कानून के मुताबिक चाय बागान के मालिकों को हर वर्ष 8 प्रतिशत घर बना कर मजदूरों को देने चाहिए। लेकिन वे लोग ऐसा नहीं करते हैं। मेरा कहना है कि चाय बागान के मालिक कभी भी मजदूरों का भला नहीं चाहते हैं और इन लिए वे उन लोगों के लिए कभी मदान नहीं बनायेंगे। उत्तर-पूर्वी अंचल में काफी वर्षा होती है। अगर किसी मजदूर का घर गन भर चूना रहे, तो दूसरे दिन वह कैसे काम कर पायेगा? मालिक लोग कहते हैं कि चूक सीमेंट और लोहा आदि नहीं मिलते हैं, इस लिए हम घर नहीं बना सकते हैं। लेकिन यह उन का फिर्क बहाना है। मेरा अनुरोध है कि सरकार स्वयं भकान बनाये और मालिकों से उन का खपता वगूल कर ले।

उप क्षेत्र में बेकारी की बड़-बड़ समस्या है। रिजर्व के अनुसार वहाँ प्रति एकड़ 1.2 आदमी बहाल होने चाहिए, लेकिन वास्तव में इन के अनुसार आदमी बहाल नहीं निये गते हैं। शाहनबाख खा फसेटों की रिपोर्ट के मुताबिक एक एकड़ के लिए 1.4 आदमी बहाल होने चाहिए। इस भिफारिश को कार्यान्वित करने से वहाँ बेकारी की जबर्दस्त समस्या का समाधान हो जायेगा।

वहाँ कई मालिक दिनों-दिन मजदूरी की संख्या को घटाने के फेर में हैं। उहाँ पर हर एक मजदूर पर प्रतिशतन तीन या चार व्यक्ति डिपेंडेंट हैं। चाय बागान में जो ट्राइकालर काम करते हैं, वहाँ मजदूरी करने के अलावा अपनी खेतीका खताने के लिए

[श्री टूना उराव]

उन के पास कोई दूसरा काम नहीं है । इन लिए मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि उन लोगों की क्रम-शक्ति को बढ़ाने के लिए वहां खादी और कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाये । इतना ही नहीं, बल्कि वहां ट्रेनिंग-कम-माडकशन सेंटर खोले जायें । तभी उन लोगों की क्रम-शक्ति बढ़ेगी ।

उस क्षेत्र में शराब की बिक्री बहुत है, जिस से वहां के मजदूरों को बहुत हानि होती है । मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि सारे देश में शराब को बन्द किया जाये । लेकिन कम से कम ट्राइबल इलाके में तो उस को ज़रूर बन्द कर देना चाहिए । पेमेंट वाले दिन तलब का कम से कम पचास फीसदी पया शराब पर खर्च हो जाता है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि उस क्षेत्र में शराब की बिक्री बन्द कर दी जाये ।

सरकार की यह पालिसी है कि भारत के पूरे भाग का 1/3 और पहाड़ी इलाके में कम से कम 50 या 60 प्रतिशत एरिया जंगल होता चाहिए और मैदानी इलाके में 20 प्रतिशत एरिया जंगल होता चाहिए । आप जानते हैं कि आदिवासी लोग जंगल में, या जंगल के किनारे रहते हैं । उन में से बहुत से लोगों का इन्फ्लिगल आकुपेशन हो सकता है । अगर इमर्जेंसी में उन को वहां से हटा दिया जायेगा, तो लाखों आदिमी बेकार हो जायेंगे, क्योंकि उन की जीविका का कोई अन्य साधन नहीं है । मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि वन पालिसी को लागू किया जाए, लेकिन उन की आर्जविका के लिए उन को वहीं और बसाने का बन्दोबस्त करना चाहिए ।

मेरे क्षेत्र में एक हाइवे नं० 31 है जिसके बीच में एक सिलतुरसा नदी है जिस पर पुल बनाने की बात बहुत दिनों से चल रही

है लेकिन अभी तक वह पुल नहीं बना है । ऐसा सुनने में आया है कि उस के लिए डेढ़ करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया था लेकिन वह अभी तक नहीं बन रहा है । तो मेरी जबरदस्त मांग है कि वह पुल बनाया जाय ।

आदिवासी जितने हैं उन की जमीन उन से छीनी जा रही है । मेरा अनुरोध है कि वह ऋण से ग्रस्त हैं, उन को उस से बचाने के लिए वहां रुपया जल्दी से जल्दी पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए जिस से वे सहाजनों के चगुल से मुक्त हो सकें ।

SHRI PAOKAI HAOKIP (Outer Manipur) : Mr. Chaimran, Sir, I congratulate the Finance Minister for this budget of 1976-77. This budget has come as a great relief to the three classes of people, namely, the rich, the middle-class and the poor people. But I may hasten to say that today the small and marginal farmers are experiencing greater difficulties in the matter of getting facilities. I would like to say that in the midst of big rich farmers, these small and marginal farmers are not enjoying the facilities which the rich farmers are enjoying. In this context, I would like to point out that Government should see that the interest of the small and marginal farmers are protected. After all, these are the people, these are the two sections of people, in the agricultural field, in the field of agricultural production, who should be given a fair chance to produce adequately with sufficient inputs. I would like to stress on the Government that they should look into this matter.

The second thing which I would like to emphasise is that the pensioners today are also one of the important sections of Indian people who are very strong to withstand the sufferings but at the same time so weak to plead their cases over the years. Wages of other workers and Government employees have increased many fold but these pensioners pay has not been

increased. I therefore request that these unfortunate pensioners should be taken care of by the Government. These pensioners are the ex-Servicemen and loyal Government servants who have given the best part of their life in the service of the nation. They should therefore get adequate facilities as other Indian people get. They are one of the most hard-hit sections in times of scarcities and natural calamities.

The third thing which I would like to stress is that in the budget there is a mention about the development of hill areas and tribal areas. In this connection, I would like to say that I come from the North-Eastern region which is indeed one of the opulent regions in natural resources. It is very distressing to point out that due to lack of adequate finances, the function of the North-Eastern Council which came into existence in 1971 has not been upto the mark so far.

The north-eastern region has many things to offer for the application of scientific methods of development. Unless this region is developed quickly, we cannot claim that the whole country is developing. Backwardness of any part will be the backwardness of the nation. Therefore, I would again appeal to the Finance Minister to pay great attention to the development of this region by being more liberal in the grant of finances to the North-Eastern Council, so that the schemes which have been formulated over the years are implemented in the near future in keeping with the 20-point economic programme initiated by Prime Minister.

With these words, I support the budget.

SHRI M. S. SANJEEVI RAO (Kakinada): Sir, I rise to support the budget presented by our dynamic Finance Minister with emphasis on rapid economic growth coupled with consolidation and stabilisation. Thanks to the purposeful and resolute leadership of Shrimati Indira Gandhi, an unprecedented discipline and dedication has been generated in all walks of life throughout the country. I congratulate

the Finance Minister on taking advantage of the situation and stepping up the tempo of development to a record level of investment by increasing the plan provision from Rs. 5,960 to Rs. 7,852 crores. I congratulate him on his foresight because whatever he predicted in the last year's budget has almost come true, particularly regarding his twin priorities of agriculture and industry. It is indeed gratifying to note that the record buffer stock of foodgrains to the tune of 11 million tonnes and the increase of industrial production to the tune of 25 per cent; this itself is an indication of his success.

As our great Mahatma Gandhi used to remind us many times, India lives in its villages. Therefore, the foremost priority must be given to agriculture and its supporting industries like power, fertilisers, pesticides, etc. I congratulate our Finance Minister on providing Rs. 434 crores for fertilisers as against Rs. 290 crores. It is indeed gratifying to note that he has made enough provision not only for on-going fertiliser factories but also for the new factories at Bhatinda, Panipat and Phulpur. I request him to use his good offices to see that adequate funds are provided also by the IDBI for the only new private sector factory—Nagarjuna Fertiliser Factory—at Kakinada in Andhra Pradesh.

19.00 hrs.

He is well aware that Andhra Pradesh has contributed nearly one million tonnes of rice to the Central Pool. I am also happy that he has created a great impact by providing as much as Rs. 120 crores in the Central Sector and Rs. 1,200 crores for the State Sector for the development of power projects. We all know that power is the real infra-structure of our national development. I am happy that we are going to produce nearly 2500 kilowatts of power for the coming year. Here I must emphasise that we should really congratulate our public sector electrical manufacturing industries like the Heavy Electricals, Bhopal, Hyderabad and Hardwar for their tremendous progress. They not

[Shri M. S. Sanjeevi Rao]

only manufacture all types of alternators, turbines, etc. but they are in a position to export quite a considerable amount of their machinery.

As time is limited, I would like to bring to the notice of the House the news item in today's paper that there is a record trade deficit of Rs. 1400 to 1800 crores as against Rs. 1134 crores last year. How are we going to face this situation? I think the Finance Minister must think not only in terms of long term measures but in terms of short term measures also. He must concentrate at the moment to see that our agro-based industrial products should be boosted. As we know, by exporting nearly 13 lakh tonnes of sugar, we have earned Rs. 475 crores. We must concentrate on more sugar production. So also, we must concentrate on textiles and jute. It is a happy augury that today's papers have informed us that a Textile Department has been created in the Commerce Ministry. It is a very useful thing because we must not only modernise these agro-based industries but also technologically step up and standardise our industries so that we can export more of textiles and jute in addition to sugar. Here, I like to bring to your notice that we have to strengthen our design and consultancy to see that we export this to the more developing countries. Here, I would like to congratulate our Indian consultants and designers for winning a contract in Libya wherein for the first time we are going to build an airport.

I like to emphasise the importance of electronics to earn more foreign exchange. In this industry technically competent labour is involved. I like that we should concentrate on electronics particularly tele-communications. In Africa and other countries we can earn large amount of foreign exchange by exporting tele-communication. India is in a fortunate position to design and plan all types of electronic communications including micro-waves. So also I like that we should concentrate on

the instruments for which there is scope in the middle-east countries. I also want to emphasise the importance of developing soft wear. Last year, we have exported soft wear to the tune of Rs. 75 lakhs to the Soviet Union.

I hope, the Finance Minister will give due importance to all these problems and see that adequate amount of foreign exchange is earned as quickly as possible and our rate of progress is continued. Thank you.

SHRI P. GANGADEB (Angul): I must congratulate to the Finance Minister for the meritorious budget for the year 1976-77. This indeed is a rejuvenated and production-generating budget, if I may say so. A combination of tax reliefs and marked increase in the Plan outlay, with a bias in favour of real investment, has rightly inspired the confidence amongst the various sections of our society. Special attention has been paid to priority sectors and to the backward districts of our country. And more so, appropriate lessons have also been drawn from the Gandhian approach towards economic development. The control of inflation has been a phenomenal success, and here, Sir, it needs to be acknowledged, with gratification, that while our Prime Minister had received unprecedented and massive support from the people during the 1971 elections, she has evoked cooperation and support in equal measure in creating a climate of national unity and economic discipline during last year, particularly with the announcement of her 26-point economic programme. Therefore, in the present mood of optimism and the economic stability prevailing at present, the bold initiative of the Prime Minister to direct the resources properly, will bear fruits for the Indian economy. There are, however, a few areas where the Finance Minister could possibly pay a greater attention, so far as the strategy for rural



development is concerned. This, I feel, is rather important; and it may be noted. Coming to direct taxes, it would have been perhaps in the fitness of things if the income-tax exemption limit had been raised to Rs. 12,000 because, in that case, the middle class families could have been spared the burden of this direct taxation. I, therefore, venture to suggest that the income-tax exemption may be graded up at least to Rs. 10,000, as against the present level of Rs. 8,000. Another weakness that emerges out of the national economy of today is the balance of payments. The trade gap of nearly Rs. 1,100 crores upto December 1975 and the debt-saving and interest payment obligations around Rs. 900 crores, pose a great challenge, in my opinion. No doubt the commitments in regard to foreign aid were favourable last year; but it shall be a great error to under-estimate the implications of mounting foreign debts and of greater encouragement needed to imports. I feel that this matter deserves the attention of the Government on a priority basis. There is a constant cry from Orissa; and I would draw the attention of the Finance Minister to the unfortunate fact of regional imbalance in Orissa. In my State, Sir, only 2 per cent of the gross domestic product is contributed by the industries. In spite of that, the advances given by the banks are hardly 50 per cent of the deposits received by them.

Therefore, the implied outflow of investible funds to other regions certainly goes against the balanced regional development which we are all the time striving to achieve. In this context, I would like the Finance Minister to again consider ways and means so that such drain of funds does not take place.

In conclusion, I would like to say that while seeking slight modifications of the budget projects and proposals in terms of my suggestions, I have much pleasure in supporting the

budget, and I am sure it will achieve its socio-economic objectives regardless of adverse criticisms.

**SHRI CHAPALENDU BHATTACHARYYA (Girdih):** Mr. Chairman, in the context of the emergency and our Prime Minister's 20-point programme, this budget assumes special significance. We welcome the budget. We support it because, firstly, it is a refreshing departure; secondly, it is growth-oriented and, thirdly, it promises us that we are; at long last, seeing the light at the end of the tunnel. The priorities are right in this budget, and in view of the consensus engineered by our Prime Minister and the political will behind this drive, we do feel confident that India's economy will be on the up-grade.

We would have very much liked the Finance Minister to let us know just at what phase of the economy we are in. Are we moving from the horror of inflationary slump that was there during the last two and a half years, to a phase of falling price boom? To what extent the Phillip's Curve is relevant to our situation, and at what point are we trying to trade-off unemployment with inflation?

The other point is the bank rates. Since savings have to increase, since investments must come up, since recovery in the situation has to be investment-led, as also Government-expenditure-led—the question of interest rates assumes urgency, the relationship between the inflationary rate and the interest rates requires scrutiny urgently. In 1975 in Switzerland the bank rate was 8.35 per cent. Now it has come down to 6.51 per cent. In Germany it was 10.14 per cent; now it has come down to 8.26 per cent. Even in Britain, where it was 19.57 per cent, it has now come down to 14.57 per cent. Therefore, a hard look at the complex of interest rates now prevalent through the various lending agencies has become urgently necessary, if the determinates of the

[Shri Chapalendu Bhattacharyya]

atomic systems, namely, savings, and investment have to be healthily expanded, so that the turn in the economy may have meaning.

A fine situation it is! There are some Ministries who can pat themselves on the back as glut-makers. Take, for example, the Department of Coal. We have 10 million tonnes of coal at pit-head. So, also the Ministry of Steel in the matter of steel and the Department of Mines in the matter of aluminium and the best part of it, agriculture, in food stocks. They are really the basis of strength for a take-off or an attempt at take-off now at this phase. We are poised for that take-off of our economy.

We welcome the abolition of excise duty on garments, we suggest excise duties on drugs should not be imposed, we suggest that interest rates should be brought down to increase investment, we suggest tax relief to the extent that it will increase the propensity to consume and support an acceleration-multiplier growth cycle.

I make a special plea for the pension-earners. Those who were entitled to the CGHS scheme benefits should continue to enjoy them.

The penalty clause relating to wealth tax should be equitably revised. It is confiscatory. If the wealth is Rs. 2,10,000 the penalty comes to Rs. 2,10,000. This should be brought in line with income-tax. It is anomalous, and hence a ceiling may be fixed to make it equitable.

We are having so many linear disciplinary movements in agriculture. We have to broaden them into a multilateral scientific agriculture, and a co-ordinated wide-spectrum effort has to be pushed through.

I suggest that we summon up our reserves to ensure export of at least 5 million tonnes of coal annually. There are now 10 million tonnes lying

at the pit-heads. For this, Haldia, Paradeep and Vizag. ports require urgent attention.

Coal which is worth Rs. 65 in India will fetch Rs. 650 abroad. I am speaking of the low ash coal. There is idle capacity in the engineering and other industries. If we can only marry off a few with one million tonnes of steel in States in the place of Rs. 1,000 a tonne which we are getting, we can earn Rs. 4500 or Rs. 5,000 per tonne through fabrication. Oil rigs and off-shore exploration rigs are particularly indicated, and that should be done in the eastern region, from Calcutta and Rasnchi to Vizag.

SHRI I. H. KHAN: (Barpeta): congratulate the Finance Minister on the current Budget. This is a real socialist Budget. I think this Budget will help in the implementation of the 20-point programme which has defined the way of salvation of 60 crores of people. If we desire to bring socialism and equality in our society, we must work hard and have patience for its results. If we desire to have social and economic equality in our society, we will have to destroy capitalism. It is a Herculean task to destroy one class and establish a new society, but it is possible for our Prime Minister.

Government should do something for the agriculturists who are the worst sufferers in our country. The salaried people get their salary, the business class get their business profit, but the agriculturist has no alternative way of getting his purchasing power increased. With the fall of general price level, the price of agricultural produce has been decreased to a great extent in comparison with other goods. The paddy in Assam is cheaper and sold in market at a lower price than the rates fixed by the Government. Again jute in our country, particularly in Assam, Bihar and West

Bengal is not well treated. At the time of harvest, it is so cheap that the growers do not get the actual cost of production by selling it. They are compelled to sell it in the lower price as they have got no alternative source of income. In Assam, jute growers are the worst sufferers because there is no jute mill to consume the whole jute produced in Assam. The price of Assam jute entirely depends upon the mercy of Calcutta Jute Mill. In Assam, Government has taken some proposals for establishing jute mills in Assam in public sector as well as in private sector, but up-till-now, they are not functioning. The Centre should give proper attention to this jute industry in Assam so that Assam's jute can be properly utilized.

The agriculturists of India are mostly poor and their purchasing power is too low. If their purchasing power can be increased, then they can get a great relief. This can be encouraged by secondary occupation like dairy, poultry, rearing goats, sheep, fowls, pigs etc. This is possible with a small amount of capital but yields a good profit. There is ample scope in India for this type of poultry industry.

Stress should be laid on the small scale and cottage industries and these should be introduced in the rural areas with the help of bank loans so that they can get encouragement. They should be given loans through rural banks.

Some of our agriculturists have got no land, but they have got good knowledge about agriculture. This is a great problem in our Assam. There are several categories of landless people. Some become landless by river-erosion; some become by selling their lands while others by birth, but all of them are agriculturists. They should be given proper attention and they should be given land on permanent basis.

It is a matter of great regret that up-till-now, there are several venture schools in our country without Government's help in which the poor people send their children for education. In this civilized world, education is most essential and Government should take over all the venture schools and give free education to the students upto Higher Secondary stage. Government should give attention to the education system so that after completion of education, the students can get self-employment and they should be looked into.

Unless we control our population, we cannot expect better social and economic life, whatever may be production of the country, whatever may be the growth of industry. If population is not checked, then we shall not be able to meet the total demand of food of our country, because population increases in geometrical progression whereas food crops increase in arithmetical progression. So, it is most essential to control the population in our country.

प्र० एम० एल० सक्सेना (महाराज-  
 राज) : महापति महोदय, मैं पानिवामेंटरी  
 अफेयर्स मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ  
 कि अगर इप मदन में विरोधी पार्टियों  
 के लीडर यहाँ नहीं हैं, तो इन्का मनलव यह  
 नहीं है कि बजट डिबेट 5 दिन के बजाय  
 डाई दिन कर दी जाये। आखिर बजट  
 के बारे में 5 मिनट में क्या कहा जा सकता  
 है। विरोधी पार्टियों के नेता सदन में नहीं  
 हैं, लेकिन फिर भी विरोधी सदस्यों को  
 5 मिनट दिये जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि  
 डिबेट को फार्म न बनाया जाये। आपोजिशन  
 के सदस्यों को काफ़ी समय मिलना चाहिये।  
 मैं इन्डिपेंडेंट मेम्बर हूँ, मैं किसी पार्टी में  
 नहीं हूँ, लेकिन मैं आपोजिशन में हूँ।

[को० एल० एल० सक्सेना]

इस बजट के लिए मैं भी मुन्नहाय्यम को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। यह यवैस्ट फ़ाइनेन्स मिनिस्टर हैं और यह उलका हूरा बजट है। वे इतने थिलियैट हैं और उन्होंने इतना रीयलिस्टिक बजट पेश किया है कि मैं इसके लिये उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इन वर्ष के प्लान का एमाउन्ट भी डेढ़ गुना कर दिया है, उसके लिये भी मैं उनको बधाई देता हूँ। टैक्सों में भी उन्होंने बहुत रियायत की है, और काफी छूट दी है, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

उन्होंने इनकम-टैक्स की हाइएम्प्ट लिमिट को बढ़ाया है, लेकिन लोअर लिमिट को नहीं बढ़ाया है। चूँकि रुपये की कीमत एक-तिहाई रह गई है, इसलिये 8,000 रुपये की लोअर लिमिटेड को 15,000 रुपये तक कर देना चाहिये।

पारसाल उन्होंने खण्डसारी पर बहुत ज्यादानी की थी, जिसका हम लोगों ने बहुत विरोध किया था। एक कांफरेन्स में, जिनमें मुन्नहाय्यम जी भी मौजूद थे, उन्होंने खण्डसारी के प्रति हमदर्दी जाहिर की थी, लेकिन मुझे अफ़सोस है कि इन बजट में उन्होंने खण्डसारी को कोई रियायत नहीं दी है। यह मुनासिब बात नहीं है। खण्डसारी इस देश की बुनकारी के बाद सबसे बड़ी काटेज इंडस्ट्री है। महात्मा गांधी इसके बहुत बड़े स्पोर्टर थे। उन्होंने कहा था कि “व्हाइट शुगर इज ए प्लायजन”। इसके अलावा खण्डसारी का एम्प्लायमेंट पोर्टेशल बहुत ज्यादा है। चीनी को एक कैंक्टरी जितनी लेबर को एम्प्लाय करती है, खण्डसारी को मनु चीनी बनाने में उससे 10, 12 गुना लेबर एम्प्लाय करती है। मुझे आशा है कि खण्डसारी के साथ जो ज्यादानी हुई है, फ़ाइनेन्स मिनिस्टर साहब उसको दूर करेंगे।

यह बजट 20 प्वाइंट प्रोग्राम को कार्यान्वित करने से और एमरवेंटी की अवस्था खत्म जा सकता है। उनके बिना न हमारी एका-नामी इम्पूब करती है और नहीं यह बजट था पाता। पिछले दो वर्षों में राउरकेला में था। 2 फरवरी को उन्होंने 10 मिलियन यानी एक करोड़ टन उत्पादन पूरा कर लिया। मैनेजर ने बताया कि जुलाई से अब तक उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी का 110 परसेंट हो गया है, जबकि वह पहले 70 परसेंट था। उन्होंने बताया कि 26 जून के बाद डिमिप्लिन,इ भी जबरदस्त हो गई कि उसकी बजह से वे अपने प्रोडक्शन को इतना बढ़ा सके हैं। मैं डिमिप्लिन का बड़ा समर्थक हूँ और चाहता हूँ कि वह बनी रहे, लेकिन यह डिमिप्लिन बहुत पहले आनी चाहिये थी। अगर इसको 10 साल पहले लाया जाता, तो हमारी स्थिति भिन्न होती। लेकिन अब भी हम इसको स्पोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि यह कायम रहे।

लेकिन मैं इस बात का समर्थक नहीं हूँ कि आप विरोधी पार्टियों के नेताओं को बराबर जेल में बन्द रखें। आखिर, उनकी यही मांग थी कि 20-प्वाइंट प्रोग्राम में जो कार्यक्रम दिये गये हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाये। सरकार उनको इम्प्लीमेंट कर रही है, इसलिये अब अगर उन लोगों को छोड़ दिया जाये तो वे सरकार का समर्थन करेंगे। सरकार ने श्री जयप्रकाश नारायण और श्री चरण सिंह को छोड़ दिया है। इससे कोई आश्चर्य तो नहीं गिर गया है। अगर सरकार अच्छे काम करे तो वे लोग आपका समर्थन करेंगे। कभी न कभी तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा। सरकार वह बचानाभी क्यों लेती है कि देश में सब विरोधी लीडर्स बन्द हैं और यहाँ कोई फ़ीडबैक नहीं है।

अबबार मैं यह खबर घाई है कि पब्लिस में संविधान अर्टिकल 226 को बदलने की सलाह दी है, जिसमें रिट और हेमिफ़ कारपस का प्राविजन है।

मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नर कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हैं। अगर सरकार ने ऐसा काम किया तो बुनिया में उसकी बहुत बदनामी होगी। हूँबियस कार्पस हमारे कॉन्स्टीट्यूशन की जान हैं। मैं कांस्टीट्यूट एसेम्बली का सदस्य था। और मैं जानता हूँ कि हमने बहुत मेहनत के साथ इस कॉन्स्टीट्यूशन को बनाया था। मैं चाहता हूँ कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कायम रखे जायें। और उनको छीना न जाये। सरकार टेम्पोरेरी डिफिकल्टीज से डरकर इन तरह का काम न करे, यह मुताबिक नहीं है।

फैमिली प्लानिंग पर बहुत जोर दिया गया है। और हम मन्वन्ध में कम्पलमरी स्ट्रगलाइजेशन तथा फाइन आदि की मजा देने की बात कही गई है। सरकार के लोग महात्मा गांधी के फालोश्रम हैं, उन्होंने फैमिली प्लानिंग की बहुत सख्त अपोजीशन किया था। उन्होंने एक किताब लिखी थी—“सल्फ कंट्रोल वगसेम मॅल्फ इडलजेम”। गांधी जी सैल्फ कंट्रोल यानी मंयम डाग फैमिली प्लानिंग को मानने वाले थे।

मैं चाहता हूँ कि बर्थ कंट्रोल हो। लेकिन प्राइमरी स्वर्य अपने ऊपर कंट्रोल करने कि इंडलजेम भी करे और फिर बर्थ कंट्रोल भी उसकी करना पड़े। उस तरह से आप कभी सकन नहीं हो पायेंगे। यह बहुत ही नुकसान की बीज है। इससे सारी नैतिकता खत्म हो जायेगी और सब मोरेलिटी खत्म हो जाएगी। फिर यदि आपने जर्बर्स्नी की और आपने दो चिन्डरेन की बात की तो हमारी पापुलेशन खत्म हो जाएगी। हमारी स्ट्रेन्थ हमारी पापुलेशन है। हम वर्ल्ड में सेफिड बिगेस्ट नेशन हैं। चाइना बिगेस्ट नेशन है पापुलेशन की दृष्टि से। तो पापुलेशन से डरना नहीं चाहिये। हमारी जमीन ऐसी है कि

we can sustain many times our population, only we have to plan properly and work properly and industrialize our country and agriculture properly.

हमारे दुश्मन चीन व पाकिस्तान की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहाँ बामन्ध में बर्थ कंट्रोल नहीं है। मजाक है। फिर हमारे यहाँ बहुत इन्फेन्ट मॉर्टलिटी है। दो बच्चों से अधिक बच्चे न पैदा करने की बात से कुछ वर्ष बाद हमारी आबादी समाप्त हो जाएगी। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल गलत चीज है और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। अगर आपने जर्बर्स्नी की और कम्पलमन किया तो सारा हिन्दुस्तान इनका विरोध करेगा। यहाँ की पब्लिक नहीं चाहेंगी और लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो।

फिर ऐजुकेशन है, एजुकेशन में आपने बहुत कम बढ़ाया है। आपने यू० जी० सी० को 70 करोड़ रुपया दिया है। यह ठीक नहीं है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हमारा एजुकेशन पर ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिये। प्राइमरी ऐजुकेशन नो स्टेट के ऊपर है हालांकि वह बहुत कम कर पाते हैं। तो उनकी भी मदद करनी चाहिये। लेकिन यह 70 करोड़ बहुत कम है। यू० जी० सी० के लिये ग्राट दुगुनी चाहिये। फिर मेरा कहना यह है कि यू० जी० सी० का खर्चा बहुत बेनगतीब है। नेहरू यूनिवर्सिटी पर 10 करोड़ रुपया खर्च करने है और सारे लगभग 5000 एफिलिएटिड कालेज पर 10 करोड़ रुपया खर्च करने है। जहाँ पांच हजार कालेज हैं वहाँ दस करोड़ और प्रकले नेहरू यूनिवर्सिटी पर 10 करोड़ खर्च करना यह बहुत बेजा बात है। यह नहीं होना चाहिये। एफिलिएटिड कालेज पर यू० जी० सी० को कम से कम अपना आधा बजट रखना चाहिये। उनकी संख्या 5 हजार के करीब है और उनमें 95 प्रतिशत

[श्री० एस० ए०० सभसेना]

लडके पटते हैं। 95 प्रतिशत लडको पर तो आप 10 करोड़ रुपया खर्च करते हैं और प्रकेले नेहरू यूनिवर्सिटी के 1500 लडको पर दस करोड़ खर्च करते हैं, यह बेजा बात है और नहीं होना चाहिये।

फिर एफिलिएटिड कालेज्ज में बच्चों के ट्रास्टेन नहीं हैं और टीचर्स के बवार्सेस नहीं हैं जो कि आवश्यक हैं और वह होने चाहिये।

कई विश्वविद्यालयों में बी० ए० में प्राइवेट परीक्षा देने की इजाजत दे दी है। उनसे ग्रेजुएट जो निकल रहे हैं प्राइवेट पढकर बे बिल्कुल बेकार हैं। इस तरह आपका मारा स्टैण्डर्ड खत्म हो जाएगा। मैं समझना हू कि आप को किसी भी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट बी ए की अनुमति नहीं देनी चाहिये। कम से कम दो साल तक वह ग्रेजुएट कोर्स पढे उसके बाद उनकी ग्रेजुएट का इम्तिहान देना चाहिये। फेल उम्मीदवार प्राइवेट बैठ सकें।

ऐग्रीकल्चर के मिलसिले में मुझे यह कहना है कि अबल तो आपने गेहू की प्रोक्पीरमेन्ट प्राइस फिक्स नहीं की है। आज इतना सस्ता गन्ना बिक रहा है कि किसान परेशान हैं। यह बहुत बेजा बात है। आपको ऐग्रीकल्चर की पैदावार की प्राइस मर्पेट करनी चाहिये ताकि किसान जिन्दा रह सकें। फिर वह जो बीजे खरीदना है जैसे कपड़ा है फटिलाइजर है या और दूसरी चीजें है वह बहुत महंगी हैं। वह बीजे उसको सस्ती मिलनी चाहिये। आपने फटिलाइजर का दाम कुछ कम किया है लेकिन वह काफी नहीं है। उसको और कम करना चाहिये जिससे किसान को फटिलाइजर सस्ता मिल सके। इसके बाद मेरी राय है कि नेहु का कम से कम 150 रुपये प्रोक्पीरमेन्ट प्राइस आपको देनी चाहिये।

डाउट और फलवस बहुत जवर्सेस कीर्ने-मिडीच हमारे यहाँ हैं। आपके नेता लोग नेपाल बात करने गये हुये हैं। मैं चाहूँगा कि राप्ती के कंट्रोल के लिए बहा बातचीत की जाय जिससे कि हम फलव से यहाँ बच सकें। और फरवी तहसील में घाबपामी हो सके।

शुगर इंडस्ट्री के नेशनलाइजेशन के लिए आपने वादा किया था, कई साल हो गये, अभी तक आपने नेशनलाइजेशन नहीं किया। 150 करोड़ रुपये गन्ने के दाम के बाकी है वह नहीं दिये गये। बेंजज बहुत बाकी है जो नहीं दिये जा रहे हैं। हमारे यहाँ कई फैक्टरीज के अन्वर कई महीने से तनकबाह नहीं मिल रही है। जो मिलनी चाहिये। फिर बहा मिनिमम बेज 300 रुपये है। जब कि और कारखानों में 450 रुपये मिनिमम बेज है। मैं कल क्रकेला गया था बहा 450 रुपये मिनिमम बेज है, 100 रुपये डी०ए० के हैं और 10 रुपये बीनम इत्याद की शकल में मिल जाना है इस तरह कुल मिला कर साठे छ सौ रुपया पड जाना है। तो शुगर फैक्टरीयों में भा इसको बढ़ाना चाहिये।

फीडम फाइदर्य के लिये आपने बहुत कम रकम रखी है। उनकी पेंशन बढ़ायी जावे क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। कम से कम उनकी पेंशन 500 रुपये मासिक हो।

हमारे यहाँ गावों में बिजली नहीं है। वह बहुत इम्पॉर्ट चीज है। बिजली हमारे यहाँ लगनी चाहिये।

टाइम कम है। इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन यह जगत जो है इसके लिये मैं बी सुबह्मयम साहब को बढाई देता हूँ और इसका समर्थन करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: There are no more speakers on the list. The debate is over. The Minister of Finance will give his reply tomorrow at 12 noon.

19.39½ hrs.

#### BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

##### SIXTIETH REPORT

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY

AFFAIRS (SHRI K. RAGHU-RAMALAH): I beg to present the Sixtieth Report of the Business Advisory Committee.

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11-00 a.m.

19.40 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 23, 1976/Chaitra 3, 1898 (Saka).*